



अंतर्राष्ट्रीय संबंध

Classroom Study Material

(May 2021 to January 2022)



DELHI



LUCKNOW



JAIPUR



HYDERABAD



PUNE



AHMEDABAD



CHANDIGARH



GUWAHATI



8468022022



9019066066



enquiry@visionias.in



[/c/VisionIASdelhi](https://www.youtube.com/c/VisionIASdelhi)



[/Vision_IAS](https://www.facebook.com/Vision_IAS)



[vision_ias](https://www.instagram.com/vision_ias)



www.visionias.in



[/VisionIAS_UPSC](https://www.t.me/VisionIAS_UPSC)



अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

विषय-सूची

1. भारत और उसके पड़ोसी (India and Its Neighbourhood)	4
1.1. भारत-चीन (India-China).....	4
1.2. भारत-तिब्बत (India-Tibet).....	5
1.3. भारत-बांग्लादेश (India-Bangladesh).....	6
1.4. भारत-नेपाल (India-Nepal).....	7
1.5. भारत- भूटान (India- Bhutan).....	8
1.6. अंतर्देशीय नदी विवाद (Inter-Country River Disputes)	9
1.7. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ (Other Important News)	10
1.8. सुर्खियों में रहे स्थल (Places in News).....	11
2. हिंद-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र (Indo-Pacific and Indian Ocean Region)	14
2.1. हिंद-प्रशांत कन्स्ट्रक्ट (Indo-Pacific Construct)	14
2.2. प्रथम क्वाड शिखर सम्मेलन (First Quad Summit)	15
2.3. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ (Other Important News)	16
2.4. सुर्खियों में रहे स्थल (Places in News).....	16
3. भारत, मध्य एशिया और रूस (India, Central Asia and Russia).....	19
3.1. भारत-सोवियत संधि के 50 वर्ष (50 Years of Indo-Soviet Treaty).....	19
3.1.1. भारत-रूस सैन्य सहयोग (India-Russia Military Cooperation)	20
3.2. भारत-मध्य एशिया (India-Central Asia).....	21
4. भारत और पश्चिमी एशिया (India and West Asia).....	23
4.1. अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण (Taliban Control Over Afghanistan)	23
4.2. भारत-ईरान (India-Iran).....	25
4.2.1 ईरान परमाणु समझौता (Iran Nuclear Deal)	26
4.3. भारत-फिलिस्तीन नीति (India-Palestine Policy)	26
4.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ (Other Important News)	28
4.5. सुर्खियों में रहे स्थल (Places in News).....	29
5. अमेरिकी महाद्वीप (American Continent)	32
5.1 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (India-US)	32
5.2. सुर्खियों में रहे स्थल (Places in News).....	33
6. यूरोप (Europe)	36
6.1. भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध (India-UK Relations)	36



6.2. भारत-यूरेशिया (India-Eurasia).....	37
6.3. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ (Other Important News)	37
6.4. सुर्खियों में रहे स्थल (Places in News).....	38
7. अंतर्राष्ट्रीय संगठन/ संस्थान (International Organization/ Institutions).....	42
7.1. संयुक्त राष्ट्र (United Nations)	42
7.1.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council: UNSC).....	43
7.2. जी-20 (G20).....	44
7.3. विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation: WHO)	45
7.4. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से देशों का निलंबन/निष्कासन (Suspension/Expulsion of countries from International Organisations).....	45
7.5. शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation: SCO)	46
7.6. दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ (Association of South East Asian Nations: ASEAN).....	47
7.7. 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (13th BRICS summit).....	48
7.7.1. ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक (BRICS New Development Bank)	49
7.8. सार्क (SAARC)	50
7.9. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ (Other Important News)	51
8. सुरक्षा से संबंधित मुद्दे (Issues Related To Security).....	54
8.1. परमाणु निःशस्त्रीकरण (Nuclear Disarmament)	54
8.2. आतंकवाद-रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय {Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED)}.....	56
8.3. अंतरिक्ष युद्ध (Space Warfare)	57
8.4. रक्षा निर्यात (Defence Exports).....	58
8.5. एकीकृत थिएटर कमान (Integrated Theatre Commands).....	60
8.6. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act: UAPA)	61
8.7. पूर्वोत्तर क्षेत्र (North East Region)	61
8.7.1. तीसरा बोडो शांति समझौता (3rd Bodo Peace Accord).....	61
8.8. द्वीपसमूह में विकासात्मक रणनीति (Island Developmental Strategy).....	62
8.9. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ (Other Important News)	65
9. विविध (Miscellaneous).....	71
9.1. गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement)	71
9.2. द्विपक्षीय निवेश संधियाँ (Bilateral Investment Treaties: BITs).....	72
9.3. ऋण जाल कूटनीति (Debt Trap Diplomacy).....	72
9.4. भारत का असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग (India's Civil Nuclear Energy Cooperation)	74
9.5. वैश्विक शासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत (Democratic Principles In Global Governance)	75



9.6. डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty).....	76
9.7. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ (Other Important News).....	77
9.8. सुर्खियों में रहे स्थल (Places in News).....	80
10. सुर्खियों में रहे भारत के सैन्य/नौसेना अभ्यास (Military/Naval Exercises of India in News).....	85

नोट:

PT 365 (हिंदी) डॉक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) की महत्वपूर्ण समसामयिकी को समेकित रूप से कवर किया गया है ताकि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके।

अभ्यर्थियों के हित में PT 365 डॉक्यूमेंट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित नवीन विशेषताओं को शामिल किया गया है:

1. टॉपिक्स के आसान वर्गीकरण और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को रेखांकित तथा याद करने के लिए इस अध्ययन सामग्री में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
2. अभ्यर्थी ने विषय को कितना बेहतर समझा है, इसके परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।
3. विषय/ टॉपिक की आसान समझ के लिए इन्फोग्राफिक्स को शामिल किया गया है। यह सीखने और समझने के अनुभव को आसान बनाता है तथा पढ़े गए विषय/कंटेंट को लंबे समय तक याद रखना सुनिश्चित करता है।

 SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	
--	---	---

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. भारत और उसके पड़ोसी (India and Its Neighbourhood)

1.1. भारत-चीन (India-China)

सुर्खियों में क्यों?

भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच वार्ता का 14वां दौर संपन्न हुआ। यह वार्ता लंबे समय से चल रहे पूर्वी लद्दाख के पर्वतीय क्षेत्रों में गतिरोध के समाधान हेतु आयोजित की गई थी।

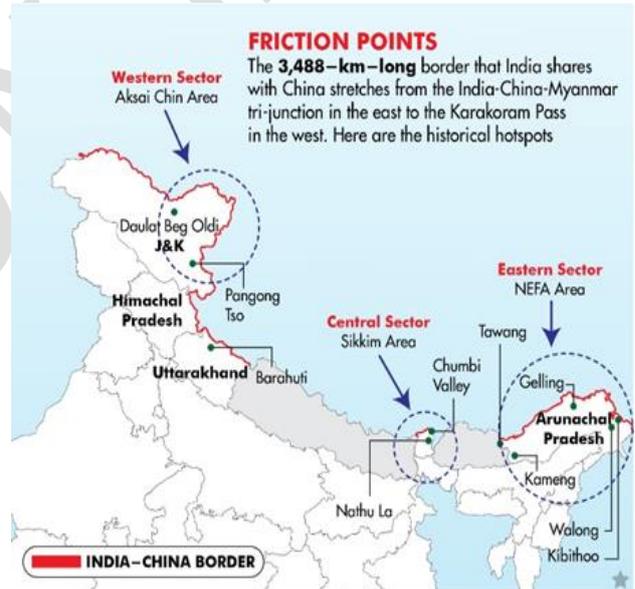
अन्य संबंधित तथ्य

दोनों पक्षों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि वे पहले के परिणामों पर ठोस कदम उठाएंगे। यह 13वें दौर की वार्ता की अपेक्षा एक सफल वार्ता सिद्ध हुई है, क्योंकि 13वें दौर की वार्ता में कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया था।

भारत-चीन सीमा विवाद

भारत-चीन सीमा का स्पष्ट रूप से सीमांकन नहीं किया गया है। लगभग 3,488 कि.मी. सीमा पर पारस्परिक रूप से सहमत कोई वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)¹ भी नहीं है।

- चीन भारत सहित 14 देशों के साथ अपनी भू-सीमा साझा करता है। चीन की मंगोलिया और रूस के बाद भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है।
- LAC को तीन भागों में विभाजित किया गया है, यथा- पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। (मानचित्र देखें)
 - पश्चिमी क्षेत्र (लद्दाख): यहाँ पर सीमा विवाद 1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित जॉनसन रेखा से संबंधित है। यह रेखा कुनलुन पर्वत तक विस्तृत थी तथा अक्साई चिन को जम्मू और कश्मीर की तत्कालीन रियासत में शामिल करती थी। लेकिन, चीन इस रेखा को स्वीकृति प्रदान नहीं करता है।
 - मध्य क्षेत्र: यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, जिसमें भारत और चीन परस्पर आदान-प्रदान किए गए मानचित्रों पर व्यापक रूप से सहमत हैं।
 - पूर्वी क्षेत्र: इस क्षेत्र में मैकमोहन रेखा पर विवाद है।



सीमा विवाद निपटान तंत्र

LAC पर उत्पन्न होने वाले विवादों को दूर करने के लिए भारत और चीन के बीच पांच समझौतों की एक श्रृंखला:



¹ Line of Actual Control

संबंधित तथ्य

वन चाइना पॉलिसी या एक चीन नीति

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की कि यदि चीन ताइवान पर हमला करता है तो वह ताइवान की रक्षा करेगा। अमेरिका का यह वक्तव्य चीन-ताइवान मुद्दे पर लंबे समय से विद्यमान अमेरिकी "रणनीतिक अस्पष्टता" में परिवर्तन को दर्शाता है।

- अमेरिका चीन की 'एक चीन नीति' के तहत ताइवान पर चीन के दावों को मान्यता प्रदान करता है। लेकिन ताइवान रिलेशन्स एक्ट, 1979 के तहत, यदि चीन ताइवान पर आक्रमण करता है, तो अमेरिका ताइवान की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।
 - ध्यातव्य है कि एक चीन नीति के तहत पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना (PRC, मुख्यभूमि चीन) के साथ संबंध स्थापित करने के इच्छुक देशों के न तो रिपब्लिक ऑफ़ चाइना (ROC, ताइवान) के साथ तथा न ही ताइवान के इन देशों के साथ कोई भी आधिकारिक संबंध होने चाहिए।
- भारत का पक्ष वर्ष 1949 से "एक चीन नीति" को मान्यता देने का रहा है। लेकिन वर्ष 2010 से भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बढ़ती चीनी आक्रामकता की पृष्ठभूमि में "एक चीन नीति" शब्द का इस्तेमाल बंद कर दिया है।

एक देश दो प्रणाली (One Country Two Systems: OCTS)

हाल ही में, चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (NPC) ने हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को स्वीकृति प्रदान की है। इससे चीनी गणराज्य की दशकों पुरानी नीति- "एक देश, दो प्रणाली (OCTS)" को फिर से चर्चा केंद्र में ला दिया है।



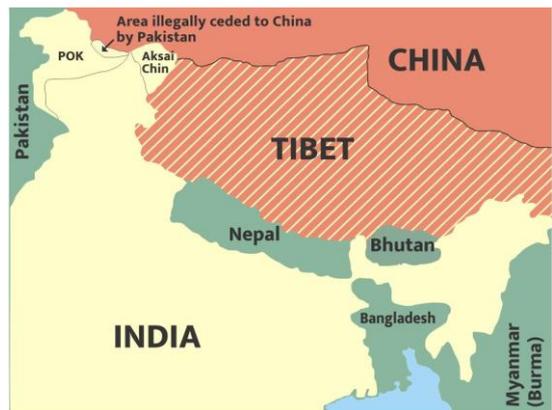
एक देश दो प्रणाली नीति के बारे में

- एक देश दो प्रणाली नीति को मूल रूप से चीन और ताइवान को एकजुट करने हेतु प्रस्तावित किया गया था, जिसे ताइवान ने अस्वीकार कर दिया था।
- यह विचार फिर तब सामने आया जब चीन ने ब्रिटेन और पुर्तगाल के साथ वार्ता प्रारंभ की, जिनका क्रमशः हांगकांग और मकाऊ पर औपनिवेशिक शासन था।
- OCTS मॉडल के तहत, चीन ने प्रस्ताव दिया कि, हांगकांग और मकाऊ में मुख्य भूमि चीन से पृथक आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालियां हो सकती हैं, लेकिन वे चीन का हिस्सा ही रहेंगे।
 - वर्ष 1997 में हांगकांग चीन के पुनः नियंत्रण में आ गया और वर्ष 1999 में मकाऊ की संप्रभुता भी उसके उसके पास आ गयी।
 - दोनों क्षेत्र अपनी-अपनी मुद्राओं, आर्थिक और कानूनी प्रणालियों के साथ चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (SAR)² घोषित किए गए, परन्तु रक्षा एवं विदेशी मामलों का निर्णय चीन द्वारा ही किया जाना था।
 - साथ ही, हांगकांग के लोगों को सभा करने और भाषण की स्वतंत्रता तथा कुछ लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं, जो मुख्य भूमि चीन में प्रदत्त नहीं हैं।
 - ये स्वतंत्रताएँ मूल कानून (Basic Law) द्वारा संरक्षित हैं (एक उप-संविधान जो हांगकांग और चीन के मध्य संबंधों को निर्देशित करता है)।

1.2. भारत-तिब्बत (India-Tibet)

सुखियों में क्यों?

हाल ही में, चीन ने तिब्बत में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण राजमार्ग के निर्माण कार्य को पूर्ण कर लिया है। इस राजमार्ग के निर्माण से अब चीन अधिक सुगमतापूर्वक भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट स्थित सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक (अर्थात् दोनों राष्ट्रों के मध्य विवादित क्षेत्रों तक) पहुंच प्राप्त कर सकता है।



² Special Administrative Regions

तिब्बत से संबंधित तथ्य

- प्रायः इसे 'एशिया का जल स्तंभ' कहा जाता है। तिब्बत के ग्लेशियर एशिया की विशाल नदियों (ब्रह्मपुत्र, मेकांग, यांग्त्ज़ी, सिंधु, येलो और साल्विन) के लिए एक विशाल जल स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। पठार का खनिज युक्त जल, क्षेत्र के प्रथम व्यावसायिक रूप से उपयोगी संसाधनों में से एक बन गया है।
- चीन का सबसे बड़ा तांबे का निक्षेप तिब्बत की तांबे की खदान यूलॉंग में स्थित है। तिब्बत में बड़ी मात्रा में लौह, सीसा, जस्ता और कैडमियम भी पाए जाते हैं। ये खनिज चीन की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि तिब्बत में महत्वपूर्ण कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार भी मौजूद हैं।
- बौद्ध धर्म को तिब्बत में भारतीयों द्वारा प्रारंभ किया गया था। तिब्बत को दलाई लामा का अधिवास स्थल माना जाता है, जो भारतीय बौद्धों के लिए एक सम्मानित एवं धार्मिक नेता हैं।
- पंचशील समझौता या "भारत तथा चीन के तिब्बत क्षेत्र के मध्य व्यापार और परस्पर अंतःक्रिया हेतु समझौते (1954)" के पश्चात्, भारत ने तिब्बत में सैन्य सुरक्षा, डाकघर, टेलीग्राफ आदि जैसे राज्यक्षेत्रातीत अधिकार त्याग दिए थे। अंततः भारत ने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया कि तिब्बत चीन का एक अभिन्न अंग है।



संयुक्त राज्य अमेरिका की तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम 2000 (Tibet Policy and Support Act: TPSA)

- TPSA को मुख्य रूप से तिब्बत के मुख्य शहर ल्हासा में एक अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की स्थापना करने, दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन को लेकर तिब्बतियों को पूर्ण अधिकार प्रदान करने और तिब्बत के सांस्कृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- यह केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (CTA) को औपचारिक रूप से विश्व भर में तिब्बती प्रवासियों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली वैध संस्था के रूप में स्वीकार करता है।

1.3. भारत-बांग्लादेश (India-Bangladesh)

सुखियों में क्यों?

बांग्लादेश को वर्ष 2021 में भारत-पाकिस्तान युद्ध (वर्ष 1971) के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। वर्ष 2021 में इस युद्ध के 50 वर्ष (स्वर्ण जयंती) पूर्ण हो गए।

भारत-बांग्लादेश संबंधों की पृष्ठभूमि

- भारत, दिसंबर 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के तुरंत पश्चात् इसे मान्यता देने और राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले प्रथम देशों में से एक था।
- व्यापार संबंध: बांग्लादेश, दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार (लगभग 9.5 बिलियन डॉलर) देश है।
- व्यापार असंतुलन के निवारणार्थ भारत ने बांग्लादेश के कई उत्पादों को शुल्क मुक्त घोषित किया है। साथ ही, भारत अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 10 एकीकृत चेक पोस्ट भी विकसित कर रहा है।
- सैन्य सहयोग: दोनों देशों के सशस्त्र बल नियमित रूप से 'संप्रति' और 'मिलन' जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। भारत ने बांग्लादेश को भारत से रक्षा उत्पादों को आयात करने के लिए 500 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया है।
- कनेक्टिविटी:
 - दोनों देशों की सरकारों द्वारा वर्ष 1965 के पूर्व भारत और बांग्लादेश के मध्य विद्यमान रेल संपर्क और अन्य कनेक्टिविटी संबंधी संपर्कों को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। उदाहरणार्थ- हाल ही में, भारत में हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश में चिल्हाटी के मध्य रेल संपर्क का उद्घाटन किया गया तथा अखौरा-अगरतला रेल संपर्क पर कार्य प्रगति पर है।



- दोनों देश चार दक्षिण एशियाई पड़ोसियों, यथा- बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और भारत (BBIN) के मध्य यात्री, व्यक्तिगत एवं मालवाहक वाहनों के आवागमन के विनियमन के लिए **मोटर यान समझौते (MVA)³, 2015** के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- हाल ही में, बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में माल-परिवहन के लिए अपने अंतर्देशीय मार्ग और **चटगांव एवं मोंगला बंदरगाहों** का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है।
- **सीमा प्रबंधन:** भारत, बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। वर्ष 2015 में **भूमि सीमा समझौते (LBA)⁴** के अनुसमर्थन और वर्ष 2014 में बंगाल की खाड़ी में **समुद्री सीमा के परिसीमन** ने दोनों देशों के मध्य दीर्घ समय से लंबित सीमा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया है।
- **पर्यटन:** भारत में रोगों का उपचार कराने आने वाले अंतर्राष्ट्रीय रोगियों में से 35% बांग्लादेश से आते हैं। साथ ही, बांग्लादेश, भारत के चिकित्सा पर्यटन के कुल राजस्व में 50% से अधिक का योगदान करता है।

संबंधित सुर्खियाँ

भारत-बांग्लादेश अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल {India-Bangladesh Protocol on Inland Water Transit and Trade (PIWTT)}

- PIWTT के द्वितीय परिशिष्ट में **नए मार्गों को शामिल करने और नए पोर्ट्स ऑफ कॉल** की घोषणा के साथ हस्ताक्षर किए गए।
 - **पोर्ट्स ऑफ कॉल** वे मध्यवर्ती पत्तन हैं, जहां पोत अपनी अनुसूचित यात्रा के दौरान आपूर्ति व ईंधन ग्रहण करने हेतु रुकते हैं।
- PIWTT पर वर्ष 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे और वर्ष 2015 में इसे पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था, जिसके अंतर्गत एक देश के अंतर्देशीय पोत अन्य देशों के निर्दिष्ट मार्गों से पारगमन कर सकते हैं।

भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग (India-Myanmar-Thailand trilateral highway: IMTTH)

- IMTTH वस्तुतः **सीमा-पार राजमार्ग गलियारा** है। इसके तहत **मणिपुर के मोरेह और थाईलैंड के माई सोत (Mae Sot) शहर** को जोड़ने का प्रस्ताव है।
- यह भारत की एकट ईस्ट पॉलिसी के एक भाग के रूप में प्रारंभ की गई एक अनुदान-सहायता पहल है। इसका उद्देश्य आसियान और भारतीय बाजारों में प्रवेश को सुलभ बनाना तथा व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना है।
- इसके वर्ष 2021 तक पूर्ण होने की संभावना है।
- भारत ने **कंबोडिया, लाओस और वियतनाम** के लिए भी राजमार्गों का विस्तार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

अन्य तथ्य

भारत और बांग्लादेश के प्रधान मंत्रियों के मध्य हुए वर्चुअल शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष

- **सीमा प्रबंधन और सुरक्षा सहयोग:** दोनों पक्ष **इच्छामती, कालिंदी, रायमंगोल, हरियाभंगा और कुहसियारा नदियों** के साथ संलग्न सीमाओं के परिसीमन को अंतिम रूप देने के लिए एक साथ कार्य करने के लिए सहमत हुए।
- **कनेक्टिविटी: हल्दीबाड़ी (भारत) और चिल्हाटी (बांग्लादेश)** के मध्य पुनर्स्थापित किए गए रेल संपर्क का उद्घाटन किया गया। यह वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के उपरांत से निष्क्रिय था।
 - साथ ही, बांग्लादेश ने **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना** में भी गहरी रुचि व्यक्त की है।
- **जल संसाधन, विद्युत और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग:** छह संयुक्त नदियों, यथा- **मनु, सुहरी, खोवाई, गुमटी, धारला और दुधकुमार** के जल के बंटवारे पर अंतरिम समझौते की रूपरेखा को शीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। इसके अतिरिक्त, **भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना** के साथ-साथ अन्य परियोजनाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की गई।

1.4. भारत-नेपाल (India-Nepal)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि भारत उन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियाँ आरंभ कर रहा है, जिन्हें नेपाल ने अपने मानचित्र में शामिल किया है। इस जानकारी को लेकर नेपाल में जन असंतोष उत्पन्न हो गया है।

इस मुद्दे से संबंधित अन्य तथ्य

- भारत द्वारा मानचित्र में कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों के शामिल किए जाने के महीनों बाद नेपाल सरकार ने उन क्षेत्रों सहित 370 वर्ग कि.मी. के अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करते हुए एक नया मानचित्र प्रकाशित किया था (इन्फोग्राफिक देखें)।

³ Motor Vehicles Agreement

⁴ Land Boundary Agreement

- **नेपाल वर्ष 1816 की सुगौली की संधि** (काठमांडू के गोरखा शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हस्ताक्षरित) को सीमा परिसीमन पर एकमात्र प्रामाणिक दस्तावेज मानता है।
 - **सुगौली की संधि** काली नदी को भारत के साथ उत्तर-पश्चिमी सीमा के रूप में चिन्हित करती है। काली नदी को नेपाल में महाकाली कहा जाता है।
- हालांकि, दोनों देश काली नदी के उद्गम की अलग-अलग व्याख्या करते हैं।
 - नेपाल के अनुसार, यह नदी उच्च हिमालय में लिंपियाधुरा से निकलती है। यह नदी नेपाल को लिंपियाधुरा-लिपुलेख और कालापानी क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करती है।
 - भारत के अनुसार, यह नदी कालापानी गांव से निकलती है। इस दृष्टिकोण से नेपाल का क्षेत्रीय दावा खत्म हो जाता है।
- **क्षेत्र का महत्व:**
 - तीर्थयात्री और पर्यटक कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करते हैं।
 - लिपुलेख दर्रे की ऊंचाई भारत को चीनी गतिविधियों की निगरानी में सहायता करती है।
- **वर्ष 2015 में मधेसियों** (नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले भारतीय मूल के लोग) और कुछ अन्य नृजातीय समूहों द्वारा नेपाली संविधान में उनके हितों की उपेक्षा किए जाने के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत-नेपाल सीमा की सीमाबंदी (blockade) की गई थी।



1.5. भारत- भूटान (India- Bhutan)

सुखियों में क्यों?

चीन ने पहली बार भूटान के पूर्वी क्षेत्रों को दोनों देशों के मध्य पारस्परिक सीमा विवाद में शामिल किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- चीन ने पूर्वी भूटान में स्थित सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)⁵ के तहत प्राप्त होने वाले अनुदान को रोकने का प्रयास किया है। उसके अनुसार यह एक विवादित क्षेत्र है। हालांकि, चीन की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है।
 - अभी तक, जकरलंग (Jakarlung), पसामलंग (Pasamlung) और डोकलाम (Doklam) पठार क्षेत्र ही दोनों के बीच विवादाग्रस्त क्षेत्र थे। (इन्फोग्राफिक्स देखें)
- भूटान ने सदैव चीन के साथ अपनी सीमा वार्ता में शांति बनाए रखी है और चीन के साथ इसके किसी प्रकार के औपचारिक राजनयिक संबंध भी नहीं हैं।
 - वर्ष 1984 और वर्ष 2016 के मध्य अब तक दोनों देशों के बीच 24 बार सीमा वार्ताओं⁶ का आयोजन हो चुका है। ये वार्ताएं मुख्य रूप से भूटान के उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्रों पर केंद्रित थीं।
- भारत द्वारा यह चिंता प्रकट की गई है कि डोकलाम और भूटान के समीप अन्य क्षेत्रों में चीनी उपस्थिति, चीन को भारत के संवेदनशील क्षेत्रों, यथा- 'चिकन नेक' (chicken's neck) या सिलीगुड़ी गलियारे के अति निकट लाएगी। भूटान भारत और चीन के मध्य एक बफर राष्ट्र के रूप में भी कार्य करता है।
 - वर्ष 2017 में, चीनी सेना ने डोकलाम पठार में घुसपैठ की थी, जो कि एक भूटानी क्षेत्र है। यह क्षेत्र भारत, भूटान और चीन के ड्राई-जंक्शन पर स्थित है।



⁵ Global Environment Facility

⁶ 24 rounds of boundary talks

- वर्ष 2007 की भारत-भूटान मैत्री संधि⁷ दोनों पक्षों को “अपने राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग बनाए रखने” के लिए प्रेरित करती है।

1.6. अंतर्देशीय नदी विवाद (Inter-Country River Disputes)

सुखियों में क्यों?

हाल ही में, उत्तरी बिहार (मिथिलांचल क्षेत्र) में आई बाढ़ से संकेत मिला है कि बिहार में बाढ़ नियंत्रण, भारत और नेपाल के मध्य अंतर-सरकारी नदी-बेसिन⁸ सहयोग पर निर्भर करता है।

भारत के नदी जल विवाद और वर्तमान सहयोगात्मक व्यवस्था



देश	सहयोगात्मक व्यवस्था
भारत-नेपाल	<ul style="list-style-type: none"> • वर्ष 1954 की कोसी संधि के तहत नेपाल में तटबंधों का निर्माण और उनका प्रबंधन किया गया। • महाकाली संधि, महाकाली नदी के जल के साझाकरण से संबंधित है।
भारत-पाकिस्तान	<ul style="list-style-type: none"> • वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियां (सिंधु, चिनाब और झेलम) तथा भारत को तीन पूर्वी नदियां (रावी, व्यास एवं सतलज) आवंटित की गई हैं। • भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। विश्व बैंक भी इसका एक हस्ताक्षरकर्ता है। • स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना सिंधु जल संधि की एक उल्लेखनीय विशेषता थी। इस जल संधि के क्रियान्वयन के लिए तथा विवादों और मतभेदों के निपटान हेतु प्रत्येक देश से एक आयुक्त नियुक्त किया जाता है। इन विवादों का निपटारा समझौते, तटस्थ विशेषज्ञ, मध्यस्थता न्यायालय या अन्य किसी भी स्वीकृत तरीके से किया जा सकता है।
भारत-चीन	<ul style="list-style-type: none"> • ब्रह्मपुत्र नदी की जल-विज्ञान से संबंधित सूचना के प्रावधान के संबंध में समझौता ज्ञापन। • सतलज नदी की जल-विज्ञान से संबंधित सूचना के साझाकरण के संबंध में समझौता ज्ञापन। • बाढ़ के मौसम में जल विज्ञान संबंधी आंकड़े, आपातकालीन प्रबंधन और अन्य मुद्दों पर परस्पर वार्ता करने तथा सहयोग करने के लिए एक विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र⁹ की स्थापना।

⁷ India-Bhutan Friendship Treaty

⁸ inter-governmental river-basin

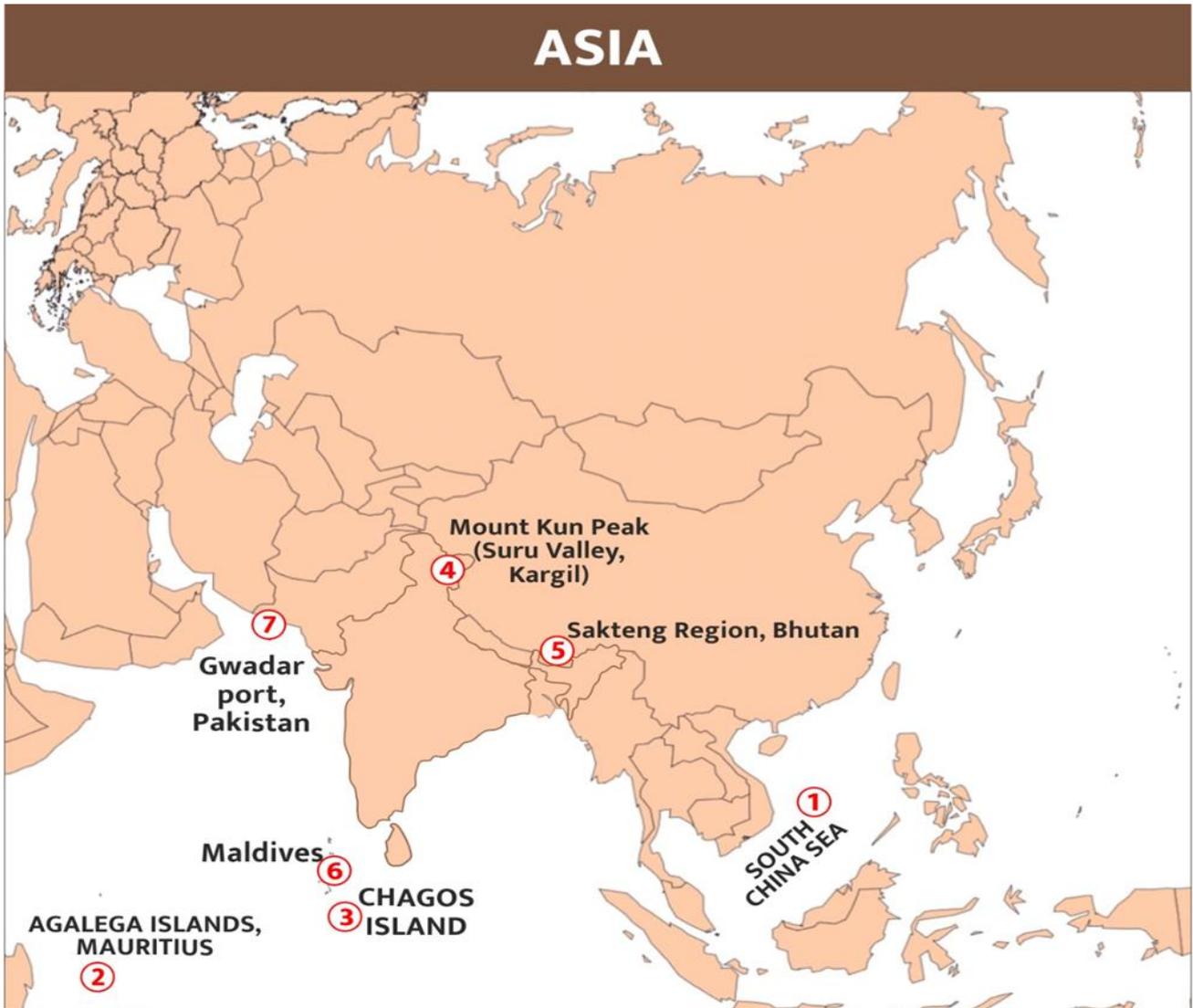
⁹ Expert-Level Mechanism

भारत-बांग्लादेश	<ul style="list-style-type: none"> गंगा संधि, फरक्का बैराज पर परस्पर सीमा के निकट सतही जल साझा करने हेतु एक समझौता है। मानसून के मौसम के दौरान गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र और बराक जैसी प्रमुख नदियों के संबंध में बाढ़ पूर्वानुमान संबंधी आंकड़ों के प्रेषण की प्रणाली।
भारत-भूटान	<ul style="list-style-type: none"> भारत और भूटान दोनों में प्रवाहित होने वाली साझा नदियों के संबंध में जल-मौसम विज्ञान एवं बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क की स्थापना के लिए व्यापक योजना। बाढ़ प्रबंधन पर संयुक्त विशेषज्ञ समूह (Joint Group of Expert)।

1.7. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ (Other Important News)

<p>मेकांग-गंगा सहयोग (Mekong-Ganga Cooperation: MGC)</p>	<p>भारत के विदेश मंत्री ने 11वीं MGC बैठक के दौरान कहा कि भारत मेकांग क्षेत्र के साथ बहुआयामी संलग्नता हेतु प्रयासरत है।</p> <ul style="list-style-type: none"> MGC पहल का प्रारंभ वर्ष 2000 में किया गया था। इसमें छह देशों यथा भारत, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य संयोजकता, शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। 	
भारत-वियतनाम	<p>भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पांचवीं वर्षगांठ मनाई गयी।</p> <ul style="list-style-type: none"> इस वर्षगांठ समारोह की पृष्ठभूमि में दोनों देशों ने संसदीय सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी और समुद्री विज्ञान में तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत-वियतनाम संबंध <ul style="list-style-type: none"> भारत और वियतनाम, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए साझा संघर्ष के इतिहास के साथ, पारंपरिक रूप से घनिष्ठ एवं सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध साझा करते हैं। वर्ष 2007 के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक बढ़ा दिया गया था। वर्ष 2016 में इसे "व्यापक रणनीतिक साझेदारी" तक विस्तार प्रदान किया गया। संबंधों को बढ़ावा देने संबंधी पहलें <ul style="list-style-type: none"> हनोई में स्वामी विवेकानंद भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (SVCC) की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना है। मेकांग गंगा सहयोग (MGC) ढांचे के तहत, भारत सामुदायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वियतनाम के विभिन्न प्रांतों में 50,000 अमेरिकी डॉलर प्रति योजना मूल्य की त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (QIP) पर कार्य कर रहा है। भारत से रक्षा उपकरण खरीदने के लिए भारत ने वियतनाम को 600 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ़ क्रेडिट दिया है। 	

1.8. सुर्खियों में रहे स्थल (Places in News)



PT 365 - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

क्रम संख्या	स्थल	मानचित्र
1.	<p>दक्षिण चीन सागर (South China Sea: SCS)</p> <p>हाल ही में, चीन के एक विमान वाहक कार्य समूह ने दक्षिण चीन सागर में एक सैन्य अभ्यास किया है। चीन ने इसे नियमित प्रशिक्षण के रूप में वर्णित किया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> चीन ने वर्ष 2016 में UNCLOS मध्यस्थता अधिकरण के निर्णय को अस्वीकार कर दिया था। उस निर्णय में यह कहा गया था कि चीन SCS के अधिकांश हिस्से को शामिल करने वाली "नाइन-डैश लाइन" के भीतर जल संसाधनों पर ऐतिहासिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है। <p>UNCLOS के बारे में</p> <ul style="list-style-type: none"> यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसे तृतीय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी (UNCLOS III) के दौरान अपनाया गया था। यह विश्व के महासागरों के राष्ट्रों द्वारा किए जाने वाले उपयोग हेतु राष्ट्रों के अधिकारों व उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है तथा इससे संबद्ध व्यवसायों, पर्यावरण और समुद्री प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में 	

	<p>दिशा-निर्देश जारी करता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> भारत द्वारा वर्ष 1982 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे और वर्ष 1995 में इसकी अभिपुष्टि कर दी गई थी। 	
<p>2.</p>	<p>अगालेगा द्वीप (Agalega island), मॉरीशस मॉरीशस ने अगालेगा द्वीप पर भारतीय सैन्य अड्डे की स्थापना की अनुमति देने संबंधी रिपोर्ट का खंडन किया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> पश्चिमी हिंद महासागर में मॉरीशस के अधीन दो-द्वीप हैं। इसमें उत्तरी द्वीप और दक्षिण द्वीप शामिल हैं। वर्ष 2015 में, भारत ने अगालेगा द्वीप समूह के विकास के लिए मॉरीशस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 	
<p>3.</p>	<p>चागोस द्वीपसमूह मॉरीशस ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU)¹⁰ के एक निर्णय के प्रति आभार प्रकट किया है। यह निर्णय चागोस द्वीपसमूह पर ब्रिटिश टिकटों के प्रयोग पर प्रतिबंध आरोपित करने से संबंधित है।</p> <ul style="list-style-type: none"> यद्यपि मॉरीशस वर्ष 1968 में ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त हो गया था, तथापि चागोस द्वीपसमूह अभी भी ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन है। इस द्वीप पर ब्रिटेन और अमेरिका का एक संयुक्त सैन्य अड्डा भी मौजूद है। 	
<p>4.</p>	<p>माउंट कुन पीक, नुन-कुन माउंटेन मैसिफ (सुरु घाटी, कारगिल)</p> <ul style="list-style-type: none"> हाल ही में, रक्षा मंत्री ने माउंटेन कुन अभियान को पूर्ण करने पर राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान (NIMAS)¹¹ की टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया। माउंट कुन पीक, नुन-कुन माउंटेन मैसिफ में स्थित है, जो जास्कर रेंज का सर्वाधिक ऊँचा शिखर है। इसमें माउंटेन नुन (7,135 मीटर) और कुन (7,077 मीटर) हैं। इस पर पहली बार वर्ष 1913 में इतालवी पर्वतारोहियों मारियो पियासेन्ज़ा और बोरेली एड गैस्पर्ड द्वारा रोहण किया गया था। 	
<p>5.</p>	<p>सकतेंग (Sakteng) क्षेत्र, भूटान हाल ही में, चीन ने भूटान के पूर्वी सकतेंग (Sakteng) क्षेत्र पर भी दावा किया है। इसमें भूटान का सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल है।</p>	

¹⁰ संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी

¹¹ National Institute of Mountaineering and Allied Sports

<p>6.</p>	<p>मालदीव हाल ही में, मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना- ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> GMCP के तहत माले और निकटवर्ती द्वीपों विलिंगली, गुल्हफालू और थिलाफुशी के मध्य एक सेतु लिंक को स्थापित किया जाएगा। भारतीय निर्माण कंपनी एफकोंस (AFCONS) को परियोजना को पूर्ण करने का दायित्व सौंपा गया है। 	
<p>7.</p>	<p>ग्वादर बंदरगाह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के कार्य की प्रगति की पृष्ठभूमि में क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> ग्वादर के बारे में: <ul style="list-style-type: none"> यह पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में स्थित है। यह एक गर्म जल वाला गहरा समुद्री बंदरगाह है, जो अरब सागर के तट पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक हथौड़े के आकार का प्रायद्वीप निर्मित करता है। इसके निकटवर्ती क्षेत्र में ईरान में ओमान की खाड़ी पर चाबहार बंदरगाह, स्थित है। यह भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है और भारत के लिए व्यापार एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 	

फाउंडेशन कोर्स

सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2023

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक को विस्तृत कवरेज
- सीसैट कक्षाएं
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- PT 365 कक्षाएं
- ए-नीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- MAINS 365 कक्षाएं
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करंट ओरिएंटेड अप्रोच
- निबंध टेस्ट सीरीज
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करंट अफेयर्स मैगजीन

DELHI: 5 APR, 9 AM | 1 FEB, 1 PM

LUCKNOW: 17 MAY | 9 AM

JAIPUR: 10 MAY | 4 PM

2. हिंद-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र (Indo-Pacific and Indian Ocean Region)

2.1. हिंद-प्रशांत कन्स्ट्रक्ट (Indo-Pacific Construct)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, अलग-अलग देशों की रूचि के कारण **इंडो-पसिफिक कन्स्ट्रक्ट** सुर्खियों में था।

भारत	<p>हिंद-प्रशांत महासागर पहल (Indo-Pacific Oceans Initiative: IPOI)</p> <p>भारत के IPOI को वर्ष 2019 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। यह देशों के लिए एक मुक्त और गैर-संधि आधारित पहल है। यह सभी देश द्वारा क्षेत्र में सामना की जाने वाली समान चुनौतियों के सहकारी और सहयोगात्मक समाधानों हेतु साथ में कार्य करने पर केंद्रित है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • भारत के IPOI के स्तंभ: <ul style="list-style-type: none"> ○ समुद्री सुरक्षा, ○ समुद्री पारिस्थितिकी और समुद्री संसाधन, ○ क्षमता निर्माण और सूचना साझाकरण, ○ समुद्री कनेक्टिविटी, तथा ○ आपदा प्रबंधन।
जापान	हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला बनाए रखना
यूरोपीय संघ	हिंद-प्रशांत में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ की रणनीति।

हिंद-प्रशांत के बारे में

- यह एक भौगोलिक कंस्ट्रक्ट है, जो लंबे समय से प्रचलित **‘एशिया-प्रशांत’** के विकल्प के रूप में उभरा है। यह वैश्विक विकास के यूरो-अटलांटिक आयातों से पूर्वी दिशा की ओर स्थानांतरण का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह एक एकीकृत मंच है, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर तथा इनके आस-पास के भू-क्षेत्रों को जोड़ता है।
- चूंकि, यह प्रमुख रूप से एक समुद्रीय अंचल है, इसलिए हिंद-प्रशांत भी समुद्री सुरक्षा और सहयोग से संबंधित है।
- विभिन्न देश इस क्षेत्र की विविध तरीकों से व्याख्या करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका हिंद-प्रशांत की उस क्षेत्र के रूप में व्याख्या करता है, जो अमेरिका के पश्चिमी तट से शुरू होकर भारतीय उपमहाद्वीप के तट पर समाप्त होता है। भारत और जापान के लिए, इस अवधारणा का विस्तार बहुत व्यापक है। उनके अनुसार यह अफ्रीकी उपमहाद्वीप के तट तक भी फैला हुआ है।
- इस क्षेत्र के मुख्य हितधारकों में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, आसियान (ASEAN) देश और अन्य समुद्री देश शामिल हैं, जिनकी हिंद एवं प्रशांत महासागर में सामरिक अवस्थिति है। इनमें छोटे द्वीपीय देश भी शामिल हैं।



हिंद-प्रशांत क्षेत्र की ओर वैश्विक आकर्षण के कारण

- **महत्वपूर्ण समुद्री संचार मार्ग (Sea Lines of Communication: SLOC):** पश्चिम में मोजाम्बिक चैनल और बॉब-अल-मंडब से पूर्व में लोम्बोक जलसंधि तक प्रमुख चोक पॉइंट्स की उपस्थिति।
- **व्यापार और अर्थव्यवस्था:** इस क्षेत्र में विश्व की 65% आबादी अधिवासित है। यह क्षेत्र वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 62% का योगदान करता है। विश्व के कुल वस्तु व्यापार में इस क्षेत्र की 46% की हिस्सेदारी है।

- **प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध:** इसमें अपतटीय हाइड्रोकार्बन, मीथेन हाइड्रेट्स, समुद्री तल खनिज, दुर्लभ मृदा धातु, प्रचुर मत्स्य भंडार इत्यादि शामिल हैं।
- **चीन कारक:** चीन की आक्रामक विदेश नीति, तीव्र आर्थिक विस्तार, सैन्य आधुनिकीकरण और शक्ति प्रदर्शन के विरुद्ध क्षेत्रीय एवं गैर-क्षेत्रीय देशों ने आपत्ति प्रकट की है।

संबंधित सुर्खियाँ

जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 'पारस्परिक पहुंच समझौते' (Reciprocal Access Agreement: RAA) पर हस्ताक्षर किए

- RAA एक नया समझौता है। यह रक्षा-क्षेत्र में बेहतर सहयोग करने के लिए संपन्न किया गया है। इसका उद्देश्य **चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक शक्ति के विरुद्ध आपसी सुरक्षा संबंधों को मजबूत** करना है।
 - RAA, ऑस्ट्रेलियाई और जापानी सेनाओं को रक्षा एवं मानवीय अभियानों पर एक-दूसरे के साथ निर्बाध रूप से कार्य करने की अनुमति प्रदान करेगा।
- RAA हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए जापान एवं ऑस्ट्रेलिया द्वारा **विस्तारित योगदान** का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।
 - इससे पूर्व फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ सहित कई देशों ने भी हिंद-प्रशांत क्षेत्र संबंधी अपनी रणनीति जारी की थी।

2.2. प्रथम क्वाड शिखर सम्मेलन (First Quad Summit)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, क्वाड देशों के पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।

क्वाड के बारे में:

- क्वाड को चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue) के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह **भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान** द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक अनौपचारिक संगठन है।
- वर्ष **2007** में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान/ASIAN) के शिखर सम्मेलन के दौरान इस समूह की पहली अनौपचारिक बैठक हुई थी।
 - इसकी शुरुआत प्रथम मालाबार सैन्य अभ्यास और वर्ष **2004** की सुनामी से जुड़ी हुई है। इस दौरान भारत ने स्वयं के लिए और पड़ोसी देशों हेतु राहत एवं बचाव अभियान संचालित किए थे। बाद में, इस अभियान में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित हो गए थे।
- शिखर सम्मेलन के तहत क्वाड द्वारा आरंभ की जाने वाली प्रमुख पहलों की घोषणा की गई:
 - क्वाड अवसंरचना समन्वय समूह की स्थापना करना: G-7 की बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) की घोषणा के आधार पर यह समूह इस क्षेत्र में संचालित बुनियादी ढांचे से संबंधित पहलों को सुदृढ़ करने और नए अवसरों की पहचान करने के लिए विशेषज्ञता, क्षमता एवं प्रभाव को संगठित करेगा।
 - स्वच्छ-हाइड्रोजन साझेदारी स्थापित करना: स्वच्छ-हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला के सभी तत्वों में लागत को कम करना और इसे सुदृढ़ करना।
 - हिंद-प्रशांत क्षेत्र में जलवायु अनुकूलन, प्रत्यास्थता और

क्वाड (QUAD) का विकासक्रम



तत्परता में वृद्धि करना।

- अर्द्धचालक (Semiconductor) आपूर्ति-शृंखला पहल को आरंभ किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है- अर्द्धचालकों व उनके महत्वपूर्ण घटकों के लिए क्षमता का विश्लेषण करना, सुभेद्यता की पहचान करना और आपूर्ति-शृंखला सुरक्षा को मजबूत करना।
- सदस्यों के मध्य उभरती प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए एक साझे दृष्टिकोण पर भी चर्चा की गई।

2.3. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ (Other Important News)

आपूर्ति शृंखला लचीलापन पहल (Supply Chain Resilience Initiative: SCRI)

हाल ही में, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के व्यापार मंत्रियों ने आपूर्ति शृंखला के लचीलेपन पर एक पहल को आरंभ करने का निर्णय लिया है। इस पहल का प्रथम प्रस्ताव जापान ने प्रस्तुत किया था। इसके लिए उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समान विचारधारा वाले देशों को पहल का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है।

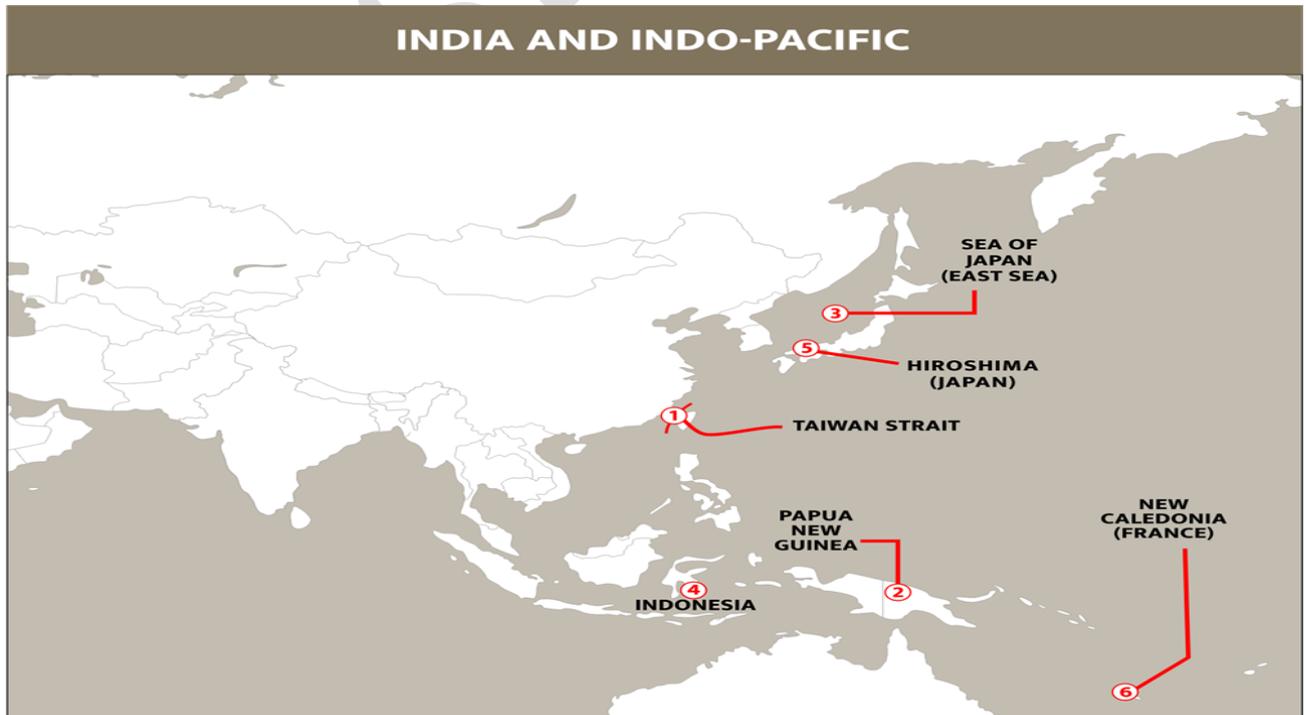
वैश्विक आपूर्ति शृंखला (Global Supply Chain: GSC) के बारे में

- GSCs ऐसे नेटवर्क हैं, जो वस्तुओं एवं सेवाओं की सोर्सिंग (स्रोत से प्राप्त करना) और आपूर्ति के उद्देश्य से लगभग सभी महाद्वीपों तथा अनेक देशों में विस्तृत होते हैं।
- GSC में विश्व भर में सूचनाओं, प्रक्रियाओं और संसाधनों का प्रवाह शामिल होता है।

SCRI के बारे में

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में, आपूर्ति शृंखला सुदृढ़ता/लचीलापन एक ऐसा दृष्टिकोण है जो किसी देश को सिर्फ एक या कुछ पर निर्भर होने के बजाय आपूर्ति करने वाले राष्ट्रों के समूह के माध्यम से अपने आपूर्ति जोखिम में विविधता प्राप्त करने में सहायता करता है।
- अप्रत्याशित घटनाएं, भले ही प्राकृतिक (जैसे- बाढ़, भूकंप या महामारी) या कृत्रिम/मानव निर्मित (जैसे कि किसी क्षेत्र में सशस्त्र विवाद) जो किसी निर्धारित देश से आपूर्ति को बाधित करती हैं या व्यापार को अवरुद्ध करती हैं, ऐसी घटनाएं गंतव्य देश की आर्थिक गतिविधि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं।
- उद्देश्य:
 - हिंद-प्रशांत क्षेत्र को अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र में परिवर्तित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना।
 - साझेदार देशों के मध्य पारस्परिक रूप से पूरक संबंध स्थापित करना।

2.4. सुर्खियों में रहे स्थल (Places in News)



क्रम संख्या	स्थल	मानचित्र
1.	<p>ताइवान जलडमरूमध्य</p> <p>हाल ही में, आयोजित चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quad) में शांति और स्थिरता के लिए ताइवान जलडमरूमध्य का उल्लेख किया गया था। इससे पूर्व G-7 वार्ता में तथा जापान और दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त वक्तव्य में भी इस पर चर्चा की गई थी।</p> <ul style="list-style-type: none"> ताइवान जलडमरूमध्य की औसत चौड़ाई 180 कि.मी. है। यह ताइवान को मुख्यभूमि चीन के फुजियान प्रांत से पृथक करता है अर्थात् दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है। इसे फारमोसा जलडमरूमध्य के रूप में भी जाना जाता है। 	
2.	<p>पापुआ न्यू गिनी (राजधानी: पोर्ट मोरेस्बी)</p> <p>इस देश ने कोविड-19 यात्रा नियमों के स्पष्ट उल्लंघनों को लेकर भारतीय राजनयिकों पर "नियमों के अपवंचन" का आरोप लगाते हुए भारतीय उड़ानों पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> यह देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। इसका क्षेत्रफल 4.6 लाख वर्ग कि.मी. से अधिक है। यह द्वीप बिस्मार्क द्वीपसमूह (न्यू ब्रिटेन व न्यू आयरलैंड), एडमिरैलिटी द्वीप, बोगनविले द्वीप और वूका (सोलोमन द्वीपसमूह का हिस्सा) के साथ सीमा साझा करता है। 	
3.	<p>जापान सागर (पूर्वी सागर)</p> <p>एक जलमग्न रूसी पनडुब्बी ने जापान सागर से एक कूज मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> भौगोलिक सीमा: यह पूर्व में जापान और सखालिन द्वीप से तथा पश्चिम में एशियाई मुख्य भूमि पर रूस एवं कोरिया से घिरा हुआ है। <ul style="list-style-type: none"> यह दक्षिण में पूर्वी चीन सागर और उत्तर में ओखोटस्क सागर से जुड़ा हुआ है। मुख्य विवाद: जापान निकटवर्ती ओखोटस्क सागर में रूसी नियंत्रण वाले दक्षिणी कुरील द्वीपों पर अपना दावा करता है, जिसे टोक्यो, उत्तरी राज्यक्षेत्र के रूप में संदर्भित करता है। 	

<p>4.</p>	<p>इंडोनेशिया</p> <ul style="list-style-type: none"> हाल ही में, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को जकार्ता से पूर्वी कालीमंतन में स्थानांतरित करने की घोषणा की है। नई राजधानी को नुसंतारा कहा जाएगा। जावाई भाषा में इसका अर्थ "द्वीपसमूह" होता है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीपसमूह है। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया में भूमध्य रेखा के आर-पार फैले 17,000 से अधिक द्वीप हैं। यह विश्व का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह अपनी सीमाएं निम्नलिखित देशों के साथ साझा करता है: <ul style="list-style-type: none"> स्थलीय सीमाएं: मलेशिया के साथ (बोर्नियो द्वीप पर), पापुआ न्यू गिनी के साथ (न्यू गिनी के द्वीप पर) और तिमोर द्वीप पर तिमोर-लेस्ते (पूर्वी तिमोर) के साथ। ऑस्ट्रेलिया, भारत, पलाऊ, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ इसकी समुद्री सीमाएं हैं। 	
<p>5.</p>	<p>हिरोशिमा (जापान)</p> <ul style="list-style-type: none"> 6 अगस्त, 2020 को जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम को 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत दो परमाणु बम निर्मित किए गए थे। पहले परमाणु बम को 'द लिटिल बॉय' नाम दिया गया था। इसे 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर में गिराया गया था। दूसरे परमाणु बम को 'द फैट मैन' नाम दिया गया था। इसे 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया था। 	
<p>6.</p>	<p>न्यू कैलेडोनिया (फ्रांस)</p> <p>न्यू कैलेडोनिया के फ्रांसीसी द्वीप क्षेत्र में मतदाताओं ने एक जनमत संग्रह में फ्रांस का हिस्सा बने रहने का विकल्प चुना है। ज्ञातव्य है कि स्वतंत्रता-समर्थक शक्तियों द्वारा इस जनमत-संग्रह का बहिष्कार किए गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> वर्ष 1998 के नौमिया समझौते के तहत, न्यू कैलेडोनिया को फ्रांसीसी विधिक प्रणाली के भीतर सीमित स्वायत्तता प्राप्त है। 	

3. भारत, मध्य एशिया और रूस (India, Central Asia and Russia)

3.1. भारत-सोवियत संधि के 50 वर्ष (50 Years of Indo-Soviet Treaty)

सुखियों में क्यों?

हाल ही में, भारत-सोवियत संधि की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। शांति, मैत्री और सहयोग की इस भारत-सोवियत संधि को वर्ष 1971 में हस्ताक्षरित किया गया था।

उक्त संधि की प्रमुख विशेषताएं

शांति	मित्रता	सहयोग
<ul style="list-style-type: none"> दोनों देशों को एक दूसरे के पक्ष की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के साथ, एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने हेतु प्रतिबद्ध किया जाता है। यह संधि दोनों देशों के दृढ़ संकल्प (हथियारों की प्रतिस्पर्धा को रोकना) को भी उजागर करती है। साथ ही, इसके द्वारा प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत, परमाणु और पारंपरिक अस्त्रों के सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण पर भी बल दिया जाता है। 	<ul style="list-style-type: none"> यह संधि उपनिवेशवाद की विरोधी रही है। साथ ही इसके द्वारा किसी अन्य रूप में उपनिवेशवाद की उपस्थिति और प्रसार के पूर्ण उन्मूलन पर भी बल दिया जाता है। इस संधि का उद्देश्य एक दूसरे के मध्य नियमित संपर्क को बनाए (दोनों देशों के हितों को प्रभावित करने वाली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर बैठकों के आयोजन और उनके प्रमुख राजनेताओं के बीच विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से) रखने हेतु दोनों देशों को प्रोत्साहित करना है। 	<ul style="list-style-type: none"> यह संधि दोनों पक्षों को, किसी तीसरे पक्ष (जो दोनों या किसी एक पक्ष के साथ सशस्त्र संघर्ष में शामिल हो) को सहायता न प्रदान करने के लिए बाध्य करती है। आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को अत्यंत महत्व देते हुए, दोनों पक्षों के मध्य इन क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभप्रद और व्यापक सहयोग को सशक्त तथा विस्तारित करने हेतु प्रयास किया जाता रहा है। साथ ही समानता, पारस्परिक लाभ और सबसे पसंदीदा राष्ट्र¹² का दर्जा प्रदान करने जैसे सिद्धांतों के आधार पर, दोनों देशों के मध्य परस्पर व्यापार, परिवहन और संचार के विस्तार पर भी बल दिया गया है।

भारत-रूस संबंध

- रक्षा साझेदारी:** रक्षा संबंध वस्तुतः भारत और रूस के अत्यधिक प्रभावशाली पहलुओं में से एक रहे हैं। ये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त विकास, विपणन व बिक्री एवं उपकरणों के निर्यात जैसे तीन घटकों के इर्द-गिर्द केंद्रित रहे हैं। ये रक्षा संबंध विशिष्ट समझौते का परिणाम हैं, जिसे किसी अन्य देश के साथ स्थापित नहीं किया गया है। साथ ही इसने भारत के स्वदेशी रक्षा निर्माण को महत्वपूर्ण बढत प्रदान की है।
 - दोनों देशों के मध्य संचालित कुछ प्रमुख रक्षा सहयोग कार्यक्रमों में शामिल हैं- ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल कार्यक्रम, सुखोई एसयू-30 और सामरिक परिवहन विमान (Tactical Transport Aircraft)।
- आर्थिक संबंध:** यह दोनों देशों के मध्य सुदृढ़ संबंधों की स्थापना की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है फिर भी इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच मात्र 7.5 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, किन्तु द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत और रूस द्वारा विभिन्न तरीके तलाशे जा रहे हैं।
- ऊर्जा सुरक्षा:** ऊर्जा क्षेत्र में, रूस प्रारंभ से ही भारत में परमाणु रिएक्टर (कुडनकुलम रिएक्टर) के निर्माण की दिशा में सहयोगी रहा है। साथ ही, यह परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी सामरिक दृष्टिकोण के अंगीकरण हेतु प्रतिबद्ध रहा है। रूस अपने ईंधन क्षेत्र में तेल, गैस और निवेश के अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में मददगार रहा है, उदाहरण के लिए, सखालिन-1 (Sakhalin-1) आदि।
 - दोनों देशों द्वारा, तीसरी दुनिया के देशों (3rd countries) जैसे कि बांग्लादेश को असैन्य परमाणु सहयोग प्रदान किया गया है।
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी:** अंतरिक्ष के क्षेत्र में, भारत और रूस के चार दशक से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। पूर्व सोवियत संघ की मदद से भारत के पहले दो उपग्रहों नामतः, आर्यभट्ट तथा भास्कर को प्रक्षेपित किया गया था। रूस ने भारी रॉकेट के निर्माण के लिए भारत को क्रायोजेनिक तकनीक प्रदान करने में भी मदद की है।

¹² most-favoured-nation



- अंतर्राष्ट्रीय स्थिति: रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। यह परमाणु सामग्री आपूर्तिकर्ता समूह (NSG)¹³ में भारत के प्रवेश का समर्थन करता रहा है। दोनों देश ब्रिक्स (BRICS), शंघाई सहयोग संगठन (SCO)¹⁴, जी20 (G20) आदि सहित विभिन्न मंचों पर एक-दूसरे के सहयोगी रहे हैं।
- सांस्कृतिक संबंध: लोगों-से-लोगों तक संपर्क ('नमस्ते रूस' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से) तथा जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र¹⁵ जैसे संस्थानों के माध्यम से, दोनों देशों के मध्य शैक्षणिक प्रतिभा को साझा करने हेतु प्रयास किए जाते रहे हैं। यह दोनों देशों के बीच बेहतर सांस्कृतिक संबंधों को प्रतिबिंबित करता है।

संबंधित सुर्खियाँ

पूर्वी आर्थिक मंच (Eastern Economic Forum)

- छठे पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन में, प्रधान मंत्री ने अपने संबोधन में भारत और रूस के मध्य हर समय सुदृढ़ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किया।
- पूर्वी आर्थिक मंच के बारे में
 - वर्ष 2015 में स्थापित, पूर्वी आर्थिक मंच ब्लादिबोस्तोक (रूस) में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है।
 - यह रूस के सुदूर पूर्व के आर्थिक विकास की दिशा में कार्य करता है। साथ ही, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करके एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विस्तार में मदद करता है।
 - वर्ष 2019 में, भारत ने इसी मंच से अपनी 'एक्ट फार-ईस्ट' नीति को आरंभ किया था। इस नीति में इस संसाधन-समृद्ध क्षेत्र के विकास के लिए 1 बिलियन डॉलर के लाइन ऑफ़ क्रेडिट की घोषणा की गई थी।

3.1.1. भारत-रूस सैन्य सहयोग (India-Russia Military Cooperation)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में संपन्न हुए 21वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन के दौरान, S-400 वायु रक्षा प्रणालियों की सुपुर्दगी की पृष्ठभूमि में दोनों देशों ने 10 वर्ष के रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।

अन्य संबंधित तथ्य

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों की धमकी के बावजूद, भारत ने अपने वायु प्रतिरक्षा क्षमता अंतराल¹⁶ को दूर करने के लिए पांच S-400 रेजिमेंटों की आपूर्ति हेतु, S-400 ट्रायंगल वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली¹⁷ की सुपुर्दगी लेना शुरू कर दिया है। इस मिसाइल की खरीद का सौदा वर्ष 2018 में 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर में किया गया था।

21वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में शामिल प्रमुख समझौते

रक्षा सहयोग के साथ-साथ, दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित प्रमुख समझौतों में शामिल हैं-

- प्रतिरक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए 6,00,000 से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों का संयुक्त उत्पादन करना।
- वर्ष 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब डॉलर और द्विपक्षीय निवेश को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- साइबर हमलों के विरुद्ध भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक ऑफ़ रूस संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। ये संयुक्त रूप से साइबर युद्ध से निपटेंगे तथा आई.एस.आई.एस, अल कायदा, लश्कर-ए-तैयबा आदि जैसे आतंकवादी संगठनों, नशीली दवाओं के दुर्व्यापार और संगठित अपराधों आदि के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे।

¹³ Nuclear Supplier Group

¹⁴ Shanghai Cooperation Organisation

¹⁵ Jawaharlal Nehru Cultural Centre

¹⁶ Air defence capability gaps

¹⁷ Triumf Air Defence Missile System

S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और CAATSA (काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट)

- S-400 वायु रक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे उन्नत मोबाइल वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों में से एक है। यह चार अलग-अलग मिसाइलों से लैस है और यह कई रेंज में दुश्मन के विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AWACS) विमानों को ध्वस्त कर सकती है।
- CAATSA एक्ट को काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसे वर्ष 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तीन देशों, अर्थात् रूस, ईरान एवं उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- तीन देशों पर प्रतिबंधों के अतिरिक्त, यह अधिनियम उन देशों पर भी प्रतिबंध लगाता है जो इन देशों के साथ व्यापार करते हैं। यह भारत और रूस के बीच मौजूदा S-400 सौदे को इसी परिधि में लाता है।
- परंतु, अमेरिका भारत जैसे सामरिक सहयोगी और रक्षा बाजार को दूर करने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसके परिणामस्वरूप, अमेरिकी सांसदों ने भारत पर प्रतिशोधी अमेरिकी कार्रवाई से बचने के लिए प्रतिबंधों में छूट हेतु एक विधेयक पेश किया है। हालांकि इस नाजुक हालत का भविष्य क्या होगा, यह तो समय ही बता सकता है।

3.2. भारत-मध्य एशिया (India-Central Asia)

सुखियों में क्यों?

भारत ने आभासी तौर पर प्रथम भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है।

मध्य एशिया के बारे में

- मध्य एशियाई देशों - कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान।
- यह गणराज्य भारत के विस्तारित पड़ोस का हिस्सा हैं।
- ये पांच मध्य एशियाई देश इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के भी सदस्य हैं।
- भारत के लिए मध्य-एशिया क्षेत्र का महत्व:
 - भू-रणनीतिक महत्व अर्थात् एशिया के विभिन्न क्षेत्रों और यूरोप एवं एशिया के बीच सेतु के रूप में।
 - क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
 - इस क्षेत्र में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, स्वर्ण, यूरेनियम आदि जैसे खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, जिनका अभी दोहन किया जाना शेष है।
 - हाल ही में, भारत ने “फोर सी (FOUR C)” दृष्टिकोण प्रस्तुत किया: इसके तहत वाणिज्य (commerce), क्षमता वृद्धि (capacity enhancement), कनेक्टिविटी तथा आपसी संपर्क (contacts) पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों पक्षों के बीच सहयोग को और अधिक विस्तारित करने पर चर्चा हुई।
 - हाल ही में, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में ‘मध्य और दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी: चुनौतियाँ और अवसर’ विषय पर 40 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।



भारत द्वारा कनेक्टिविटी के प्रयास

- भारत की कनेक्ट मध्य एशिया नीति वर्ष 2012 में तैयार की गई थी। यह राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक संबद्धता सहित एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है।

- वर्ष 2000 में संपन्न हुआ अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)¹⁸ समझौता, ईरान से होते हुए भारत और मध्य एशिया के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
- भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से और उसके बाद अफगानिस्तान से गुजरने वाले ओवरलैंड (भूमि मार्ग) कॉरिडोर के माध्यम से मध्य एशिया से संपर्क की संभावनाओं को खोजा है।
- ईरान के माध्यम से भारत और मध्य एशिया के बीच माल के परिवहन की सुविधा के लिए, भारत ने वर्ष 2017 में टी.आई.आर. कार्नेट के तहत आयोजित वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन पर सीमा शुल्क अभिसमय को स्वीकार कर लिया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018 में भारत, अश्गाबात समझौते में शामिल हो गया था। ज्ञातव्य है कि इस समझौते में ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी सम्मिलित हैं।

“You are as strong as your Foundation”

FOUNDATION COURSE GENERAL STUDIES PRELIMS CUM MAINS 2023

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination

- Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform
- Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2022

ONLINE Students

NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts and subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions and convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail.

DELHI: 10 MAY, 1 PM | 21 APR, 1 PM | 7 APR, 5 PM

LUCKNOW: 10th May, 1 PM | 9th Feb, 5 PM | **HYDERABAD: 16th May, 3:30 PM | 11th April, 7 AM** | **PUNE: 21st May**

CHANDIGARH: 19th May | 7th Mar, 5 PM | **AHMEDABAD: 21st April, 4 PM** | **JAIPUR: 10th May, 7 AM & 5 PM**

Live - online / Offline Classes

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

¹⁸ International North-South Transport Corridor

4. भारत और पश्चिमी एशिया (India and West Asia)

4.1. अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण (Taliban Control Over Afghanistan)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की वापसी के पश्चात् तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान में मौजूदा सत्ता पर अपना नियंत्रण और काबुल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **भारत का ऑपरेशन देवी शक्ति:** यह 800 लोगों, जिनमें, भारतीय एवं अन्य अफ़ग़ानी सहभागी शामिल हैं, को तालिबान प्रभावित अफ़ग़ानिस्तान से निकालने के लिए **भारत द्वारा संचालित एक निकासी मिशन है।**

तालिबान के बारे में

- **तालिबान** जिसे पश्तो भाषा में "छात्र" के रूप में संदर्भित किया जाता है, का उदय वर्ष 1994 में कंधार (अफ़ग़ान के दक्षिण में स्थित एक शहर) के आस-पास हुआ था।
- यह वर्ष **1989 में सोवियत संघ की वापसी के पश्चात्** और वर्ष 1992 में वहां मौजूदा सरकार के पतन के उपरांत **देश पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु गृहयुद्ध लड़ने वाले गुटों में से एक रहा है।**
- वर्ष 1998 तक, इसने लगभग संपूर्ण देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। हालांकि वर्ष 2001 में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं द्वारा इन्हें केवल सत्ता से हटाया गया था।
- इसके अतिरिक्त, उन्होंने अपने शासन के दौरान, शरीयत या इस्लामी कानून के कठोर संस्करण (तालिबान द्वारा स्वयं निर्मित) को लागू किया था। इसमें कठोर दंड, महिलाओं के शिक्षा प्राप्त करने और स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित करना तथा संगीत और सिनेमा पर प्रतिबंध लगाना आदि शामिल हैं।

तालिबान और अफ़ग़ानिस्तान सरकार के बीच अंतर-अफ़ग़ान संवाद और चर्चा के परिणामस्वरूप संपन्न एक राजनीतिक समझौता

अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के सभी सैनिकों की वापसी की समय सीमा

अमेरिका-अफ़ग़ानिस्तान शांति समझौता के 4 मार्गदर्शक सिद्धांत

अमेरिका और इसके सहयोगियों की सुरक्षा के संदर्भ में किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूह या व्यक्ति द्वारा अफ़ग़ानिस्तान की धरती का उपयोग नहीं करने देने की गारंटी

एक स्थायी और व्यापक युद्धविराम

क्या आप जानते हैं?

ऑपरेशन देवी शक्ति अफ़ग़ान युद्धरत क्षेत्रों से भारतीय एवं अन्य लोगों को निकालने का भारत का यह कोई पहला अनुभव/प्रयास नहीं है, बल्कि भारत पहले भी ऐसे कई अभियानों को संचालित कर चुका है। वर्ष 2000 के बाद से भारत द्वारा किए गए सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय निकासी अभियानों में निम्नलिखित शामिल रहे हैं:



वर्ष 2006, ऑपरेशन सुकून: इसे युद्ध प्रभावित लेबनान से भारतीय, श्रीलंकाई और नेपाली नागरिकों को निकालने के लिए संचालित किया था।



वर्ष 2011, ऑपरेशन सेफ होमकमिंग: इसे लीबिया गृह-युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए आरंभ किया गया था।



वर्ष 2015, ऑपरेशन राहत: इसे युद्ध प्रभावित यमन से भारतीयों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया था।

संबंधित सुर्खियाँ

तालिबान और अफ़ग़ान सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने ओस्लो वार्ता आरंभ की

- इस वार्ता को नाँवें आयोजित कर रहा है। यह वार्ता अफ़ग़ानिस्तान में मानवाधिकारों और मानवीय संकट पर केंद्रित है।
- अगस्त 2021, में 20 वर्ष बाद तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से अफ़ग़ानिस्तान में मानवीय दशा काफी खराब हो गई है।



अफ़गानिस्तान में भारतीय निवेश



इमारतों और विभिन्न प्रकार के अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार में भारत द्वारा अफ़गानिस्तान को प्रदान की जाने वाली सहायता। उदाहरण के लिए—

- काबुल में अफ़गानिस्तान की संसद का निर्माण।
- सलमा बांध का पुनर्निर्माण, जिसे अब अफ़गान-भारत मैत्री बांध के रूप में जाना जाता है।
- पुल-ए-खुमरी से काबुल तक विद्युत पारेषण लाइन की स्थापना।
- जरांज-डेलाराम सड़क का निर्माण।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, सरकारी भवनों, खेल सुविधाओं, कृषि और सिंचाई आदि जैसे क्षेत्रों में मध्यम स्तर की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना (High Impact Community Development Project: HICDP) कार्यक्रम।



विभिन्न वस्तुओं जैसे कि एम्बुलेंस, बस, बिस्कुट, दवा, सैन्य वाहन और हेलीकॉप्टर आदि के स्थानांतरण में भारत द्वारा की जाने वाली सहायता। उदाहरण के लिए—

- वायुसेना के लिए MI-25 और MI-35 हेलिकॉप्टर।
- राष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए एयरबस विमान।
- फ़रयाब प्रांत में उपकेंद्रों और पारेषण लाइन के लिए सामग्री।
- अफ़गान राष्ट्रीय सेना के लिए सैन्य वाहन।
- सरकारी अस्पतालों के लिए एंबुलेंस।



अफ़गान नागरिकों को भारत से ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए लोगों से लोगों के मध्य आदान-प्रदान। उदाहरण के लिए—

- अफ़गान संस्थानों को भारतीय तकनीकी सलाहकार प्रदान करना।
- अफ़गान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।
- अफ़गान सैनिकों, पुलिसकर्मियों और लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन।

सुर्खियों में रहे अफ़गानिस्तान के स्थल

दहला बांध

- यह अफ़गानिस्तान के कंधार प्रांत के लिए सिंचाई का प्राथमिक स्रोत है। इसे वर्ष 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनवाया गया था

बगराम एयरफील्ड (Bagram Airfield)

- इसे प्रथम बार सोवियत संघ द्वारा निर्मित किया गया था। इस एयरबेस की काबुल (अफ़गानिस्तान) से निकटता के कारण इसे लगभग 20 वर्षों तक **संयुक्त राज्य अमेरिका** द्वारा सबसे बड़े एयरबेस के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व दूत निक्की हेली द्वारा एक वक्तव्य में कहा गया है कि **चीन बगराम एयरबेस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु प्रयासरत है।**
- **चीन** हवाई युद्ध के दौरान **भारत के विरुद्ध अपने सामरिक अलाभ** (भारत-चीन सीमा पर स्थित तिब्बत की अत्यधिक ऊंचाई के कारण एयरबेस एवं युद्धक विमानों के परिचालन में कठिनाई होने के कारण) के **निवारण हेतु इस एयरबेस का उपयोग** कर सकता है।



जरांज, निमरोज प्रांत (Zaranj, Nimroz Province)

- अमेरिका द्वारा वर्ष 2020 में अमेरिकी सेना की वापसी के लिए तालिबानी समूह के साथ किए गए एक समझौते के उपरांत जरांज, तालिबान के अधीन आने वाली प्रथम प्रांतीय राजधानी बन गई है।
- जातव्य है कि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और पुनर्गठन के लिए भारत की प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में, भारत ने जरांज-डेलाराम राजमार्ग का निर्माण किया था।

मजार-ए-शरीफ (Mazar-i-Sharif)

- भारत मजार-ए-शरीफ में स्थित वाणिज्य दूतावास से भारतीय कर्मियों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करेगा।
- यह निर्णय सरकार द्वारा इस अफगान शहर से विशेष उड़ान के माध्यम से सभी भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जारी किए गए अत्यावश्यक दिशा-निर्देशों के पश्चात लिया गया है।

पंजशीर घाटी (Panjshir Valley)

- पंजशीर हिंदुकुश पर्वत में अवस्थित है और यह संपूर्ण घाटी पंजशीर नदी के तट पर स्थित है, जो घाटी की लम्बाई के साथ-साथ प्रवाहित होती है।
- इस घाटी की लगभग 100% आबादी नृजातीय ताजिकों की है।
- प्रमुख विशेषताएँ- यहाँ चांदी व पन्ना सहित विभिन्न प्रकार के कीमती रत्न व दुर्लभ मृदा तत्व भी प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं।
- इसे आक्रमणकारियों के कब्रिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कोई भी आक्रमणकारी इसे विजित करने में सफल नहीं हो सका था।

कंधार

- कंधार के निकट तालिबान लड़ाकों के उपस्थिति के कारण भारत ने एहतियात के तौर पर कंधार वाणिज्य दूतावास से अपने राजनयिकों और अन्य कर्मचारियों को निकाल लिया।
 - कंधार अफगानिस्तान का दूसरा मुख्य शहर (काबुल के बाद) है। यह दक्षिण-मध्य अफगानिस्तान में तरनक नदी के तट पर एक मैदान में स्थित है।

4.2. भारत-ईरान (India-Iran)

सुखियों में क्यों?

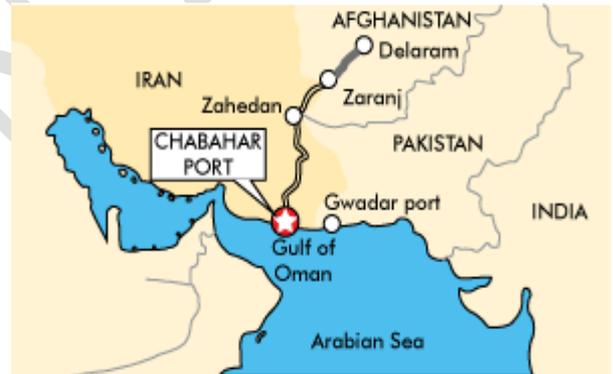
हाल ही में फरजाद-बी गैस क्षेत्र को घरेलू स्तर पर ही विकसित करने के ईरान के निर्णय ने भारत के तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) की विदेशी निवेश शाखा 'ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड' (OVL) के एक लाभकारी अनुबंध में शामिल होने की संभावना को समाप्त कर दिया है।

फरजाद-बी गैस क्षेत्र के बारे में

- फरजाद-बी फारस की खाड़ी (ईरान) में अवस्थित एक अपतटीय प्राकृतिक गैस क्षेत्र है।
- यह ईरान और सऊदी अरब की सीमा पर फारस के खाड़ी में अवस्थित है।
- फरजाद-बी गैस फील्ड में 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस रिज़र्व है। इसमें से 60 प्रतिशत तक गैस निकाली जा सकती है।
- गैस फील्ड में गैस कंडेंसेट्स मौजूद हैं। इनमें 5000 बैरल प्रति बिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है।
- इस क्षेत्र की खोज वर्ष 2008 में भारत के सरकारी स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) की विदेशी निवेश शाखा OVL द्वारा की गई थी।

ईरान में अन्य भारतीय निवेश: चाबहार बंदरगाह

- यह ऊर्जा संपन्न ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर ओमान की खाड़ी में स्थित है।
- इसे भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से वस्तुओं एवं यात्रियों की आवाजाही के लिए बहुविध परिवहन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- गुजरात के कांडला बंदरगाह से चाबहार की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है और चाबहार से मुंबई की दूरी लगभग 1450 किलोमीटर है। इस प्रकार यह बंदरगाह भारत से भौगोलिक रूप से निकट भी है।
- इस बंदरगाह पर दो टर्मिनल निर्मित किए गए हैं- शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहिश्ती।
- शाहिद बेहिश्ती को भारत, अफगानिस्तान और ईरान द्वारा वर्ष 2016 में हस्ताक्षरित, त्रिपक्षीय पारगमन समझौते के तहत संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है।
- भारत को चाबहार में शहीद बेहिश्ती बंदरगाह पर दो टर्मिनल और पांच बर्थ (Berths) विकसित करने तथा संचालित करने के लिए 10 वर्षों का पट्टा प्रदान किया गया है।



संबंधित सुर्खियाँ

ईरान ने भारत के सहयोग के बिना ही अफगानिस्तान की सीमा के साथ, चाबहार बंदरगाह से जाहेदान तक रेल लाइन के निर्माण का निर्णय लिया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2016 में, भारत, ईरान एवं अफगानिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे की स्थापना पर त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
 - यह परिवहन और पारगमन गलियारा भारतीय वस्तुओं को पाकिस्तानी क्षेत्र की उपेक्षा करते हुए ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। यह गलियारा वर्ष 2009 में अफगानिस्तान में भारत द्वारा निर्मित जरांज-डेलाराम राजमार्ग का पूरक है।
- इस समझौते के तहत, भारत ने चाबहार बंदरगाह के साथ-साथ इस बंदरगाह को अफगानिस्तान से जोड़ने वाले भूमि-आधारित मार्ग को भी विकसित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- भारत ने चाबहार-जाहेदान रेलवे लाइन के निर्माण के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने हेतु ईरान के साथ भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। यह रेलवे लाइन चाबहार बंदरगाह से ईरान-अफगानिस्तान सीमा तक यात्रा के समय को कम करेगी।



4.2.1 ईरान परमाणु समझौता (Iran Nuclear Deal)

सुर्खियों में क्यों?

ईरान, रूस, चीन और यूरोपीय देशों ने वर्ष 2015 की संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA)¹⁹, परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए वियना में पुनः वार्ता आरंभ कर दी है।

JCPOA के बारे में

- JCPOA पर ईरान और P5+1 (चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) देशों ने हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका इस समझौते से पीछे हट गया था।
- JCPOA की शर्तों के तहत, अनुसंधान रिएक्टर गतिविधियों को छोड़कर ईरान को 3.67% से अधिक संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन करने से प्रतिबंधित किया गया था।
 - ज्ञातव्य है कि 90% से अधिक संवर्धित यूरेनियम का परमाणु हथियारों के निर्माण में उपयोग किया जा सकता है।
- ईरान एक प्रोटोकॉल को भी लागू करने पर सहमत हुआ है। यह प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों को उसके परमाणु स्थलों तक पहुंचने की अनुमति प्रदान करेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ईरान गुप्त रूप से तो परमाणु हथियार विकसित नहीं कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के बारे में

- IAEA परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। इसे व्यापक रूप से संयुक्त राष्ट्र के भीतर विश्व के "शांति और विकास के लिए परमाणु संगठन" के रूप में जाना जाता है।
- एजेंसी विश्व भर में अपने सदस्य देशों और कई भागीदारों के साथ कार्य करती है। इसका कार्य परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है।
- IAEA का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। इसे परमाणु प्रौद्योगिकी की खोजों एवं विविध उपयोगों से उत्पन्न गहरे भय और अपेक्षाओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया में निर्मित किया गया था।
- IAEA का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के विएना में है।
- यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करता है। जब आवश्यक हो, तब IAEA सुरक्षा उपायों और सुरक्षा दायित्वों के सदस्यों द्वारा गैर-अनुपालन के मामलों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी रिपोर्ट करता है।

4.3. भारत-फिलिस्तीन नीति (India-Palestine Policy)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, गाज़ा पट्टी में इज़रायल और फिलिस्तीनी गुटों के मध्य हिंसक संघर्ष हुआ था। यह इज़रायल और हमास के बीच मिस्र की मध्यस्थता वाले युद्धविराम पर सहमत होने के साथ समाप्त हुआ है।

¹⁹ Joint Comprehensive Plan of Action

इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष का संक्षिप्त इतिहास

वर्ष 1917: बेलफोर घोषणा-पत्र: फिलिस्तीन के लिए ब्रिटिश मैंडेट का गठन

वर्ष 1947: संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप; दो नए राज्यों के रूप में इजरायल और फिलिस्तीन का गठन

15 मई 1948 – 10 मार्च 1949: प्रथम अरब-इजरायल युद्ध, इजरायल की जीत

वर्ष 1967: 6 दिवसीय युद्ध- इजरायल ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी समेत फिलिस्तीन के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया

वर्ष 1993: ओस्लो समझौता- इसकी परिणति वर्ष 1995 में इजरायल के उग्र-राष्ट्रवादियों द्वारा इजरायली प्रधान मंत्री की हत्या के रूप में हुई

19वीं सदी के अंत में: विश्व भर में राष्ट्रवाद/जायोनीवाद (यहूदीवाद) का उदय, जिसके चलते यहूदियों ने फिलिस्तीन लौटना शुरू किया

वर्ष 1941 – वर्ष 1945: होलोकॉस्ट, पृथक यहूदी देश के लिए मांग में वृद्धि

14 मई 1948: इजरायल द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा

वर्ष 1964: फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) का गठन

वर्ष 1987 – वर्ष 1993: प्रथम इतिहास-हमास का गठन

वर्ष 2000–2005: द्वितीय इतिहास-इजरायल ने गाजा पर से अपना अधिकार त्याग दिया और हमास ने वहाँ नियंत्रण स्थापित किया



द्विराष्ट्र समाधान (Two-State Solution) क्या है?

- यह एक स्वतंत्र एवं संप्रभु फिलिस्तीन राज्य (अर्थात् देश) और एक स्वतंत्र व संप्रभु इजरायली राज्य के शांतिपूर्ण अस्तित्व को संदर्भित करता है।
- वर्ष 1937 के पील आयोग की रिपोर्ट में फिलिस्तीन के ब्रिटिश मैंडेट में यहूदी और अरब राज्यों के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव जारी किया गया था। इसके तहत फिलिस्तीन को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाना था, यथा- एक अरब राज्य, एक यहूदी राज्य और पवित्र स्थानों वाले एक तटस्थ क्षेत्र के रूप में।
- वर्ष 1947 के फिलिस्तीन संबंधी संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना में भी यही उपबंध दोहराया गया था, परन्तु उस समय अरबों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।
- हालांकि, वर्ष 1991 में अमेरिकी मध्यस्थता वाले मैड्रिड शांति सम्मेलन के दौरान द्विराष्ट्र समाधान पर सहमति प्रदान कर दी गई थी।
- भारत फिलिस्तीनियों की वैध आकांक्षाओं और इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है।

भारत की इजरायल-फिलिस्तीन नीति

- **मैड्रिड शांति सम्मेलन:** वर्ष 1991 के मैड्रिड सम्मेलन (जहां दो राज्य समाधान पर सहमति हुई थी), सोवियत संघ के विघटन तथा वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन के उपरांत भारत ने वर्ष 1992 में इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, परन्तु वह फिलिस्तीनियों का सदैव समर्थक बना रहा है।
 - **डी-हाइड्रनेशन की नीति:** वर्ष 2018 में, भारत ने डी-हाइड्रनेशन की नीति अपनाई थी। इसका सीधा सा अर्थ है कि इजरायल के साथ भारत के स्वतंत्र संबंध हैं। साथ ही, भारत को अपने हितों के आधार पर इन संबंधों को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है तथा यह फिलिस्तीनियों के साथ भारत के संबंधों से भिन्न होंगे।

यरूशलम का धार्मिक महत्व

- यरूशलम वस्तुतः यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्मों के पवित्र स्थलों के लिए जाना जाता है:
 - **अल अक्सा मस्जिद,** इस्लाम समुदाय हेतु विश्व का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है।
 - **वेस्टर्न वाल,** यहूदी धर्म का एक पवित्र स्थल है।
 - **चर्च ऑफ द होली सेपल्कर,** यह यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने और उनके समाधि स्थल पर निर्मित एक चर्च है, जिसे ईसाई धर्म एक पवित्र स्थल मानता है।

संबंधित सुर्खियाँ

नया क्वाड (New QUAD)

संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने अब्राहम समझौते (Abraham Accords) के आधार पर इन देशों के मध्य सहयोग एवं भागीदारी में वृद्धि करने के लिए **चतुष्पक्षीय आर्थिक मंच** आरंभ करने का निर्णय लिया है।

- अब्राहम समझौते पर **दिसंबर 2020 में हस्ताक्षर** किए गए थे। इसका उद्देश्य इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में अरब देशों के एक समूह के मध्य संबंधों को सामान्य करना था।

- भारत, संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के मध्य इंडो-अब्राहमिक समझौते का विचार सर्वप्रथम वाशिंगटन में निवासरत मित्र के विद्वान मोहम्मद सोलिमन द्वारा सुझाया गया था।
- महत्व:
 - यह नया लघु-समूह संदर्भित करता है कि भारत अब एक एकीकृत क्षेत्रीय नीति की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार है।
 - यह मध्य पूर्व के साथ एक गैर-वैचारिक संबद्धता की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करता है।
 - इस मंच द्वारा व्यापार, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे गैर-सैन्य मुद्दों तथा सार्वजनिक उपयोगिता वाली वस्तुओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
 - यह दशकों से इजरायल और अरब देशों के मध्य व्याप्त गतिरोध के समाधान हेतु अधिक राजनीतिक एवं कूटनीतिक विकल्प प्रदान करेगा।
- हाल ही में, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) इजरायल के साथ राजनयिक संबंधों के सामान्य होने के बाद तेल-अवीव में अपना दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी राष्ट्र बन गया है।

भारत-इजरायल मुक्त व्यापार समझौता

- भारत और इजरायल, मुक्त व्यापार समझौते को संपन्न करने की वार्ता के साथ इनके राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
- दोनों देशों के बीच संबंध, इजरायल देश के निर्माण के साथ ही, 1948 में प्रारंभ हो गए थे। पूर्ण राजनयिक संबंध वर्ष 1992 में स्थापित किए गए थे।
 - इन्हें वर्ष 2017 में रणनीतिक स्तर पर उन्नत किया गया था। दोनों पक्षों द्वारा उच्च स्तरीय आदान-प्रदान और मंत्रिस्तरीय यात्राओं में वृद्धि ने विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है।
- सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:
 - आर्थिक: भारत एशिया में इजरायल का तीसरा तथा विश्व स्तर पर सातवां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
 - कृषि: दोनों देशों ने कृषि सहयोग में विकास के लिए तीन वर्षीय कार्यक्रम (वर्ष 2021-2023) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्यक्रम से दोनों देशों के स्थानीय किसानों को लाभ प्राप्त होगा।
 - रक्षा और सुरक्षा: पिछले पांच वर्षों से इजरायल, भारत के लिए शीर्ष तीन हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है।
 - सांस्कृतिक संबंध: इजरायल में भारतीय मूल के लगभग 85,000 यहूदी रह रहे हैं।

भारत-इजरायल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष {India-Israel Industrial R&D and Technological Innovation Fund (I4F)}

- भारत और इजरायल के विशेषज्ञों ने I4F के तहत 5.5 मिलियन डॉलर की 3 संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
 - I4F भारत और इजरायल के बीच एक सहयोग है। यह सहयोग भारत और इजरायल की कंपनियों के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने, सुविधाजनक बनाने और समर्थन देने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य सहमत 'फोकस क्षेत्रों' में मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना है।
 - इससे दोनों देशों को लाभ पहुंचाने वाली अभिनव प्रौद्योगिकियों का एक समान विकास और व्यावसायीकरण होगा।

4.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ (Other Important News)

भारत-संयुक्त अरब अमीरात	<p>भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) वार्ता शुरू की है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • भारत-UAE व्यापार संबंधों के बारे में <ul style="list-style-type: none"> ○ संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2019-20 में 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ○ वित्त वर्ष 2021 में UAE भारत का तीसरा (अमेरिका और चीन के बाद) सबसे बड़ा वस्तु निर्यात बाजार रहा है। ○ संयुक्त अरब अमीरात भारत में FDI का एक प्रमुख स्रोत है।
भारत और ओमान	<ul style="list-style-type: none"> • भारत और ओमान 10वीं संयुक्त सैन्य सहयोग समिति (JMMC) का आयोजन करेंगे • संयुक्त सैन्य सहयोग समिति (JMMC) रक्षा क्षेत्र में भारत और ओमान के लिए भागीदारी का शीर्ष मंच है। यह दोनों पक्षों के बीच रक्षा आदान-प्रदान के समग्र ढांचे को मार्गदर्शन प्रदान करता है। • भारत और ओमान के मध्य राजनयिक संबंध वर्ष 1955 में स्थापित किए गए थे। वर्ष 2008 में इन संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में अपग्रेड किया गया था। • ओमान, खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे प्रमुख रक्षा भागीदार है। • भारत ने सैन्य उपयोग और रसद समर्थन प्राप्त करने के लिए ओमान के दुकम बंदरगाह तक पहुंच प्राप्त कर ली है।



4.5. सुर्खियों में रहे स्थल (Places in News)

WEST ASIA



PT 365 - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

क्रम संख्या	स्थल	मानचित्र
1.	काला सागर (Black Sea) <ul style="list-style-type: none"> रूस ने काला सागर में ब्रिटिश विध्वंसक पोत पर चेतावनी के गोले दागे। यह भूमध्य सागर और एजियन सागर के माध्यम से तथा विभिन्न जलडमरूमध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। बोस्फोरस जलडमरूमध्य इसे मरमारा सागर से जोड़ता है तथा डारडेनेल्स जलडमरूमध्य इसे भूमध्य सागर के एजियन सागर क्षेत्र से जोड़ता है। उत्तर में, यह केर्च जलडमरूमध्य द्वारा आज़ोव सागर से जुड़ा हुआ है। 	
2.	लेबनान (राजधानी: बेरूत) <ul style="list-style-type: none"> हाल ही में, इज़रायल ने ईरान समर्थित लेबनान के समूह हिजबुल्ला द्वारा लेबनान से रॉकेट दागे जाने के विरुद्ध प्रतिक्रिया में आर्टिलरी फायर (तोपों से गोले दागना) किए हैं। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सैन्य-बल (United Nations Interim Force in Lebanon) के अनुसार स्थिति अत्यंत गंभीर है और उसने सभी पक्षों से संघर्ष विराम का आग्रह किया है। लेबनान (राजधानी: बेरूत) भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित लेवंट क्षेत्र (Levant) में एक पर्वतीय राष्ट्र है। 	

<p>3.</p>	<p>दुबई, (संयुक्त अरब अमीरात)</p> <ul style="list-style-type: none"> दुबई में विश्व के सबसे बड़े और सबसे ऊँचे ऑब्जर्वेशन व्हील 'आइन दुबई' (Ain Dubai) को लोगों के लिए खोला जाएगा। उल्लेखनीय है कि इसकी ऊंचाई 250 मीटर है। यह लंदन आई स्मारक से भी दोगुना ऊँचा है। दुबई अरब प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्व में स्थित है। यह उन सात अमीरातों में से एक है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates: UAE) का हिस्सा माना जाता है। दुबई में बुर्ज खलीफा (विश्व की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत) जैसी अनेक आधुनिक अवसंरचना/वास्तुकला का निर्माण किया गया है। 	
<p>4.</p>	<p>यमन (राजधानी: सना)</p> <ul style="list-style-type: none"> हाल ही में, हूती विद्रोहियों ने यमन के सबसे बड़े विमान पत्तन (अल-अनद एयरबेस) पर हमला किया है। अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसके पश्चिम में लाल सागर और बाब-अल-मंडेब स्थित है। इसकी स्थलीय सीमाएं सऊदी अरब और ओमान से संलग्न हैं। यहाँ वर्ष 2015 से ही गृह-युद्ध जारी है, जहाँ एक ओर सऊदी अरब द्वारा समर्थित सरकार है तो दूसरी ओर ईरान समर्थित हूती विद्रोही। इस गृह-युद्ध में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा समर्थित हूती विरोधी बल और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल भी शामिल हैं। जातव्य है कि यमन में प्राचीन दीवारों वाला शहर शिबाम (Shibam) अवस्थित है। यह एक यूनेस्को (UNESCO) विश्व धरोहर स्थल है और इसके शहरी नियोजन के कारण इसे 'मरुस्थल का मैनहट्टन' कहा जाता है। 	
<p>5.</p>	<p>सीरिया (राजधानी: दमिश्क)</p> <p>हाल ही में, इजरायल ने सीरियाई भूमि से सक्रिय ईरान समर्थित विद्रोहियों से निपटने हेतु सीरिया पर हवाई हमले किए हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रमुख जल निकाय- सीरिया भूमध्य सागर की पूर्वी सीमा पर स्थित है। यूफ्रेट्स या फ़रात (तुर्की के पर्वतों से उद्भूत होने वाली) सीरिया की एक प्रमुख नदी है तथा बलिख और खाबर इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। सीमावर्ती देश- तुर्की (उत्तर में), इराक (पूर्व में), जॉर्डन (दक्षिण में) और इजरायल एवं लेबनान (पश्चिम में)। 	
<p>6.</p>	<p>ओमान की खाड़ी</p> <ul style="list-style-type: none"> ईरान ने ओमान की खाड़ी में अपना प्रथम तेल टर्मिनल स्थापित किया है, ताकि ईरानी टैंकरों को सामरिक दृष्टि से सुभेद्य होर्मुज जलडमरूमध्य का उपयोग करने से रोका जा सके। 	

<p>7.</p>	<p>कुवैत (राजधानी: कुवैत सिटी) संयुक्त राष्ट्र के एक पैबल ने कुवैत की राष्ट्रीय तेल कंपनी को कुवैत पर इराक के आक्रमण और अधिकार की क्षतिपूर्ति के रूप में 600 मिलियन अमरीकी डॉलर का भुगतान किया है। ज्ञातव्य है कि इस इराकी आक्रमण के परिणामस्वरूप ही अमेरिका के नेतृत्व वाला खाड़ी युद्ध (1990-91) हुआ था।</p> <ul style="list-style-type: none"> • कुवैत खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) का संस्थापक सदस्य है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी भी है। <ul style="list-style-type: none"> ○ GCC अरब प्रायद्वीप में छह देशों का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसमें- बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। ○ इसकी स्थापना वर्ष 1981 में सहयोग और क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा करने के लिए की गई थी। • वर्तमान में कुवैत में मध्य पूर्व में सबसे बड़ी अमेरिकी सैन्य उपस्थिति है। 	
<p>8.</p>	<p>नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र हाल ही में, नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दशकों पुराना संघर्ष फिर से शुरू हो गया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • नागोर्नो-काराबाख को अर्साख भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अज़रबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन अधिकांश क्षेत्र आर्मेनियाई अलगाववादियों द्वारा नियंत्रित है। • नागोर्नो-काराबाख दक्षिण काकेशस / ट्रांसकेशिया (दक्षिण-पूर्वी यूरोप में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र) में एक अलग क्षेत्र है। 	

हिन्दी माध्यम
29 March

ENGLISH MEDIUM
22 March

- 📖 संदेह समाधान सत्र एवं मार्गदर्शन
- 📖 मई 2021 से अप्रैल 2022 तक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।
- 📖 प्रारंभिक परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।
- 📖 लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यर्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग में लचीलापन चाहते हैं।

1 वर्ष का करेंट अफेयर्स

प्रीलिम्स 2022 के लिए मात्र 60 घंटे में

5. अमेरिकी महाद्वीप (American Continent)

5.1 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (India-US)

सुखियों में क्यों?

भारत-अमेरिका ने 5 वर्षों के लिए वैश्विक विकास भागीदारी समझौते का नवीकरण किया है।

वैश्विक विकास भागीदारी समझौता

- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक वैश्विक विकास साझेदारी समझौते का नवीनीकरण किया है। यह समझौता अपने सहयोगी देशों को संयुक्त रूप से सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है।
 - दोनों पक्षों ने वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के वक्तव्य (Statement of Guiding Principles: SGP) में संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे समझौते की वैधता वर्ष 2026 तक विस्तारित हो गई है।
 - अफ्रीका के लिए फीड द फ्यूचर इंडिया ट्राइंगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम (FTF ITT) इसके तहत संचालित एक परियोजना का उदाहरण है।
 - आरंभ में वर्ष 2014 में SGP समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और वर्ष 2019 में वर्ष 2021 तक के लिए इसका नवीनीकरण किया गया था।
- त्रिकोणीय सहयोग (Triangular cooperation)
 - त्रिकोणीय सहयोग में तीन अभिकर्ता (इन्फोग्राफिक देखें), अर्थात् दक्षिण से दो (सुविधाकर्ता और लाभार्थी भागीदार) तथा उत्तर से एक (मुख्य भागीदार) शामिल होते हैं। मुख्य भागीदार के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संगठन भी हो सकता है।
 - "उत्तर" और "दक्षिण" के विभाजन का उपयोग विकसित देशों (उत्तर) तथा विकासशील देशों (दक्षिण) के बीच मौजूद सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भिन्नता को संदर्भित करने के लिए किया जाता है।
- भारत के अन्य त्रिकोणीय सहयोग के उदाहरण
 - भारत-जापान सहयोग: एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC)।
 - भारत-यूनाइटेड किंगडम त्रिकोणीय परियोजना, जिसे "अफ्रीका के लिए भारत की व्यापार प्राथमिकताओं का समर्थन (SITA)"²⁰ कहा जाता है। इसे यूनाइटेड किंगडम के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (DFID) द्वारा वित्त पोषित किया गया है।



संबंधित सुखियाँ

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एयर-लॉन्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल (ALUAV) के लिए एक परियोजना-समझौते पर हस्ताक्षर किए

- ALUAV के लिए परियोजना-समझौता रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहलू (DTTI)²¹ के अंतर्गत शामिल है।
 - DTTI के तहत, परियोजनाओं की 2 श्रेणियां हैं:
 - उद्योग-से-उद्योग (industry-to-industry) परियोजनाओं से संबंधित, जिन्हें निर्यात लाइसेंस द्वारा सुगम बनाया गया है, तथा
 - वे परियोजनाएं, जिन्हें परियोजना-समझौतों (Project Agreements: PA) के माध्यम से अंतिम रूप प्रदान किया गया है।
 - ALUAV के लिए परियोजना-समझौता वस्तुतः अनुसंधान, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन (RDT&E)²² समझौते के तहत आरंभ की गई दूसरी श्रेणी की एक परियोजना है। इसे प्रथम बार जनवरी 2006 में हस्ताक्षरित किया गया था और जनवरी 2015 में नवीनीकृत किया गया था।
- भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा संबंध:
 - वर्ष 2016 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामित किया था। इसे वर्ष 2018 में स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर-1 के दर्जे तक उन्नत कर दिया गया था।

²⁰ Supporting India's Trade Preferences for Africa

²¹ Defence Technology and Trade Initiative

²² Research, Development, Testing and Evaluation

- रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 संवाद आयोजित किया जाता है।
- भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित चार मूलभूत रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं:
 - सैन्य सूचना के आदान-प्रदान पर वर्ष 2002 में जनरल सिक्वोरिटी ऑफ़ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट (GSOMIA)।
 - वर्ष 2016 में एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग करने के लिए लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ़ एग्रीमेंट (LEMOA)।
 - दोनों सेनाओं के मध्य इंटरऑपरेबिलिटी और भारत को उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी के विक्रय के लिए वर्ष 2018 में कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्वोरिटी एग्रीमेंट (COMCASA)।
 - उच्च स्तरीय सैन्य प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक्स और भू-स्थानिक मानचित्रों को साझा करने के लिए वर्ष 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA)।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, समकारी शुल्क पर एक संक्रमणकालीन दृष्टिकोण पर सहमत हुए हैं

- दोनों देशों ने समकारी शुल्क (या डिजिटल टैक्स) से संक्रमण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम मौजूदा एकतरफा उपायों पर एक संक्रमणकालीन दृष्टिकोण पर सहमत हो गए थे।
- समकारी शुल्क को वर्ष 2016 में भारत में बिना किसी स्थायी प्रतिष्ठान वाली विदेशी फर्मों (जैसे अमेज़न, गूगल आदि) पर कर (Tax) लगाने के लिए प्रस्तुत किया गया था।
 - बाद में अमेरिका ने ऑस्ट्रिया, भारत, इटली, यूनाइटेड किंगडम आदि द्वारा अपनाए गए ऐसे डिजिटल करों की जांच की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह घोषणा की कि ये कर, अमेरिकी डिजिटल कंपनियों के प्रति भेदभाव करते हैं।
- अक्टूबर 2021 में, भारत सहित 136 देशों ने 15% की दर से वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर लागू करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। साथ ही, उन बाजारों में बड़ी कंपनियों के लाभों पर कर लगाने की एक समान प्रणाली लागू करने पर भी सहमति व्यक्त की गई थी, जहां इन लाभों को अर्जित किया जाता है।
 - समझौते के लिए देशों को सभी डिजिटल सेवा कर और अन्य समान एकपक्षीय उपायों को हटाने की आवश्यकता है।
- वैश्विक कर समझौते के प्रस्तावित समाधान में दो घटक शामिल हैं: स्तंभ एक, जो बाजार क्षेत्राधिकारिता के लाभ के एक अतिरिक्त हिस्से के पुनः आवंटन से संबंधित है और स्तंभ दो, न्यूनतम कर को शामिल करता है और जो कर नियमों के अधीन है।
- भारत-अमेरिका समझौते के अनुसार, भारत 31 मार्च, 2024 तक या स्तंभ 1 के लागू होने तक, जो भी पहले हो, समकारी शुल्क लागू करना जारी रखेगा।

5.2. सुर्खियों में रहे स्थल (Places in News)



क्रम संख्या	स्थल	मानचित्र
1.	<p>मध्य अमेरिका/कैरेबियन द्वीप समूह</p> <ul style="list-style-type: none"> डोमिनिका (Dominica): डोमिनिका की एक अदालत ने अगले आदेश तक भगोड़े भारतीय व्यवसायी मेहुल चोकसी को कैरेबियाई द्वीप देश से निर्वासित करने से अधिकारियों को 'रोक' दिया है। उसे डोमिनिका में 'अवैध प्रवेश' के लिए हिरासत में लिया गया था। हैती: हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या कर दी गई है। क्यूबा: हाल ही में, इस देश ने सोबराना 2 वैक्सीन विकसित की है। यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए वायरस के रिसेप्टर-बाइंडिंग डोमेन को टिटनेस के एक निष्क्रिय प्रतिरूप के साथ मिलाकर तैयार की गई विश्व की प्रथम संयुग्मी (conjugate) वैक्सीन है। बारबाडोस: महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राज्य के प्रमुख के पद से हटाने के बाद बारबाडोस विश्व का सबसे नया गणराज्य बन गया है। यह प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है। माउंट हिलैबी इसका उच्चतम बिंदु है। निकारागुआ: हाल ही में, निकारागुआ ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया है। साथ ही, आधिकारिक तौर पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ केवल "एक चीन" को अपनी एकमात्र वैध सरकार के रूप में मान्यता दी है। <ul style="list-style-type: none"> यह सबसे बड़ा मध्य अमेरिकी देश है। निकारागुआ झील, मध्य अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। होंडुरास: शियोमारा कास्त्रो ने होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस (St. Vincent & The Grenadines): भारत के प्रधान मंत्री ने सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के प्रधान मंत्री पर हमले की निंदा की है, जो एक प्रस्तावित वैक्सीन जनादेश के जन विरोध में घायल हो गए थे। <ul style="list-style-type: none"> सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस दक्षिणी कैरेबियन सागर में 32 द्वीपों की एक शृंखला है। 	

2.

चिली (राजधानी सैंटियागो)

- हाल ही में गेन्नियल बोरिक, चिली के अब तक के सबसे कम आयु के राष्ट्रपति बने हैं।
- विश्व का सबसे लंबा और सबसे संकीर्ण भूमि वाला देश है।



अभ्यास 2022

ऑल इंडिया प्रीलिम्स

(GS+CSAT)

मॉक टेस्ट सीरिज

3 टेस्ट | 17 अप्रैल | 1 मई | 15 मई

🎯 ऑल इंडिया रैंकिंग और अन्य अभ्यर्थियों के साथ विस्तृत तुलना
🎯 सुधारात्मक उपायों और प्रदर्शन में निरंतर सुधार के लिए
 Vision IAS द्वारा पोस्ट टेस्ट एनालिसिस™

पर्जीकरण करें
www.visionias.in/abhyaas

ऑफलाइन* मोड
100+ शहरों में

**सरकार के नियमों और छात्रों की सुरक्षा के अधीन*

AGARTALA | AGRA | AHMEDABAD | AIZAWL | AJMER | ALIGARH | ALMORA | ALWAR | AMRAVATI | AMRITSAR | ANANTHAPURU | AURANGABAD | BAREILLY | BENGALURU | BHAGALPUR | BHOPAL | BHUBANESWAR | BIKANER | BILASPUR | CHANDIGARH | CHENNAI | CHHATARPUR | COIMBATORE | CUTTACK | DEHRADUN | DELHI MUKHERJEE NAGAR | DELHI RAJINDER NAGAR | DHANBAD | DHARWAR | DIBRUGARH | FARIDABAD | GANGTOK | GAYA | GHAZIABAD | GORAKHPUR | GREATER NOIDA | GUNTUR | GURUGRAM | GUWAHATI | GWALIOR | HALDWANI | HARIDWAR | HAZARIBAGH | HISAR | HYDERABAD | IMPHAL | INDORE | ITANAGAR | JABALPUR | JAIPUR | JAMMU | JAMSHEDPUR | JHANSI | JODHPUR | JORHAT | KANPUR | KOCHI | KOHIMA | KOLKATTA | KOTA | KOZHIKODE (CALICUT) | KURNOOL | KURUKSHETRA | LUCKNOW | LUDHIANA | MADURAI | MANGALURU | MATHURA | MEERUT | MORADABAD | MUMBAI | MUZAFFARPUR | MYSURU | NAGPUR | NASIK | NAVI MUMBAI | NOIDA | ORAI | PANAJI (GOA) | PANIPAT | PATIALA | PATNA | PRAYAGRAJ (ALLAHABAD) | PUNE | RAIPUR | RAJKOT | RANCHI | ROHTAK | ROORKEE | SAMBALPUR | SHILLONG | SHIMLA | SILIGURI | SONIPAT | SRINAGAR | SURAT | THANE | THIRUVANANTHAPURAM | TIRUCHIRAPALLI | UDAIPUR | VADODARA | VARANASI | VIJAYAWADA | VISAKHAPATNAM | WARANGAL



6. यूरोप (Europe)

6.1. भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध (India-UK Relations)

सुखियों में क्यों?

हाल ही में, भारत-यूनाइटेड किंगडम के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को “व्यापक रणनीतिक साझेदारी”²³ तक बढ़ाने के लिए “रोडमैप 2030” अपनाया गया है।
 - यह रोडमैप आगामी दस वर्षों में लोगों से लोगों तक संपर्क, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई व स्वास्थ्य आदि से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में गहन तथा सुदृढ़ भागीदारी को बनाए रखने में मदद करेगा।
 - इससे पूर्व, वर्ष 2004 में, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने अपने संबंधों को द्विपक्षीय स्तर से बढ़ाकर रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचा दिया था।

रोडमैप 2030				
देशों और लोगों को जोड़ना	व्यापार और समृद्धि	रक्षा और सुरक्षा	जलवायु	स्वास्थ्य
<ul style="list-style-type: none"> • G-20, विश्व व्यापार संगठन आदि जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय को मजबूत करना। • व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी को लागू करना। • भावी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए साझेदारी हेतु प्रयास करना। • भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए “भारत-यू.के. दुगेदर” 	<ul style="list-style-type: none"> • उन्नत व्यापार भागीदारी (ETP)²⁴ आरंभ करना, जो एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता को शामिल करती हो। • आई.टी. और डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे सेवा क्षेत्र में विनियम एवं सहयोग बढ़ाना। • उत्पादन-से संबद्ध प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाकर यू.के. की कंपनियों को भारत के विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। 	<ul style="list-style-type: none"> • वर्ष 2015 में स्वीकृत रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भागीदारी (DISP)²⁵ के तहत सहयोग का विस्तार करना। • पश्चिमी हिंद महासागरीय क्षेत्र में एक साझेदारी के माध्यम से नौवहन और सार्वभौमिक पहुंच की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना तथा समुद्री सहयोग में सुधार करना। • महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और टीकों आदि पर द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से साइबर स्पेस में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता को बढ़ावा देना। 	<ul style="list-style-type: none"> • COP26 में एक वैश्विक हरित ग्रिड पहल आरंभ करना, जिसमें राष्ट्रीय नेताओं की राजनीतिक उद्घोषणा तथा भारत के ‘एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड (OSOWOG)’²⁶ के विज्ञान को पूरा करने में मदद करने के लिए तकनीकी, वित्तीय एवं अनुसंधान संबंधी सहयोग शामिल है। 	<ul style="list-style-type: none"> • टीके, चिकित्साविधान और निदान पर भारत-यू.के. साझेदारी विकसित करना तथा अप्रैल 2022 तक समान वैश्विक आपूर्ति की गारंटी में सहायता करते हुए, कोविड-19 से संबंधित वितरण नीति, नैदानिक परीक्षण, विनियमन, अनुसंधान और नवाचार विकसित करने के लिए यू.के.-भारत वैक्सीन हब का विस्तार करना।

²³ Comprehensive Strategic Partnership

²⁴ Enhanced Trade Partnership

²⁵ Defence and International Security Partnership

²⁶ One Sun One World One Grid

(‘साथ-साथ’) पहल को समर्थन प्रदान करना।				
--	--	--	--	--

भारत-यू.के. मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement: FTA) की संभावना

- वर्चुअल समिट के दौरान एक उन्नत व्यापार साझेदारी (ETP)²⁷ की घोषणा करते हुए, यू.के. सरकार ने वक्तव्य जारी किया है कि ब्रिटेन और भारत के मध्य इस वर्ष के अंत में औपचारिक FTA पर वार्ता को प्रारंभ किया जाएगा।
- पूर्व में भारत द्वारा यू.के. के साथ (ब्रेकिंग्ट के पूर्व यूरोपीय संघ के सदस्य के रूप में) एक व्यापक-आधारभूत व्यापार और निवेश समझौते (BTIA)²⁸ पर वार्ता करने हेतु प्रयास किए गए थे।
 - हालांकि भारत-यूरोपीय संघ के मध्य BTIA पर वार्ता को वर्ष 2007 में आरंभ किया गया था, परन्तु व्यापारिक निर्यात तथा अधिक से अधिक बाजार पहुंच से संबंधित बढ़ते मतभेदों को लेकर दोनों पक्षों के मध्य इस पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिए जा सके हैं।

6.2. भारत-यूरेशिया (India-Eurasia)

सुखियों में क्यों?

अपनी समुद्री भू-राजनीति के एक भाग के रूप में हिंद-प्रशांत की ओर राजनीतिक तथा संस्थागत रुचि उत्पन्न करने में भारत की सफलता के पश्चात्, यह अनुभव किया गया है कि भारत को यूरेशिया के प्रति अपनी महाद्वीपीय रणनीति का पुनः मूल्यांकन करना चाहिए।

यूरेशिया के बारे में

यूरेशिया पृथ्वी पर सबसे बड़े महाद्वीपीय क्षेत्र को संदर्भित करता है। यह यूरोप, तथा एशिया के अधिकतम क्षेत्र को लिए हुए है और यहां 5 बिलियन से अधिक लोग निवास करते हैं। हालांकि, इस क्षेत्र की सीमाओं के बारे में कोई साझी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता विद्यमान नहीं है।



भारत के लिए यूरेशिया का महत्व

- यूरेशियन देश ऊर्जा (तेल, प्राकृतिक गैस), प्राकृतिक संसाधनों (यूरैनियम, लौह अयस्क, एल्यूमीनियम) और कपास तथा सोने जैसी वस्तुओं में समृद्ध है।
- यूरेशिया की रणनीतिक प्रायद्वीपीय स्थिति जो एशिया और पश्चिम एशिया के विभिन्न उप-क्षेत्रों को जोड़ती है।
- चीनी प्रभाव को बाधित करने के अतिरिक्त, यह भारत को इस क्षेत्र में शत्रुतापूर्ण गठबंधनों (जैसे तुर्की-पाकिस्तान गठबंधन) को संतुलित करने में सहायता करेगा।

यूरेशिया के प्रति भारत की रणनीति में यह शामिल होना चाहिए:

- यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्यों के साथ अधिक जुड़ाव
- भारत-रूस संवादों को तीव्र करना
- भौगोलिक कटाव का समाधान करने के लिए, ईरान और अरब प्रायद्वीप के साथ सहयोग। ईरान की अवस्थिति अफगानिस्तान और मध्य एशिया के भविष्य के निर्धारण में ईरान को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती है।

6.3. अन्य महत्वपूर्ण सुखियाँ (Other Important News)

ग्लोबल गेटवे (Global)	चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के प्रत्युत्तर में यह 300 अरब यूरो के वैश्विक बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण पर यूरोपीय संघ की एक रणनीति है।
-----------------------	--

²⁷ Enhanced Trade Partnership

²⁸ Broad-based Trade and Investment Agreement

<p>Gateway)</p>	<ul style="list-style-type: none"> यह योजना सामाजिक, पर्यावरणीय, वित्तीय और श्रम संबंधी उच्च मानकों को बढ़ावा देने का वादा करती है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अन्य पहलें: <ul style="list-style-type: none"> बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) पार्टनरशिप: इसे हाल ही में G7 द्वारा आरंभ किया गया है। यह लोकतांत्रिक देशों के नेतृत्व में, एक नई मूल्य संचालित और पारदर्शी वैश्विक अवसंरचना साझेदारी है, जो विकासशील देशों में 40 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अवसंरचना आवश्यकता को पूरा करने में मदद करती है। एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर: यह एशिया और अफ्रीका के मध्य विकास, संपर्क तथा सहयोग के संबंध में भारत-जापान का एक सहयोगपूर्ण विज़न है। 	<p>The map illustrates the Belt and Road Initiative routes. The overland route (blue line) connects Europe (Rotterdam, Venice, Athens, Istanbul, Moscow) through the Middle East (Iran, Pakistan, India, China, Xian) to East Asia (Beijing, Dalian). The maritime route (pink line) connects Europe (Rotterdam) through the Mediterranean (Venice, Athens, Istanbul, Suez Canal) to the Indian Ocean (Gwadar, Colombo, Singapore) and East Asia (Fuzhou, Dalian).</p>
<p>एशिया-यूरोप बैठक (ASEM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> उपराष्ट्रपति ने 13वें ASEM शिखर सम्मेलन के प्रथम पूर्ण सत्र को संबोधित किया। ASEM संवाद और सहयोग के लिए एक अनौपचारिक मंच है। यह संपूर्ण यूरोप और एशिया से 53 भागीदारों को एकजुट करता है। ASEM, वैश्विक जनसंख्या के लगभग 62.3%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 57.2% और वैश्विक व्यापार के लगभग 60% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक संवाद को बढ़ावा देने, आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक चुनौतियों से एक साथ निपटने के लिए एक मंच प्रदान करना है। 	

6.4. सुर्खियों में रहे स्थल (Places in News)



क्रम संख्या	स्थल	मानचित्र
1.	<p>अल्बानिया (राजधानी: तिराना) उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) ने अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ किया। इसे डिफेंडर-यूरोप 21 नाम दिया गया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> अल्बानिया एड्रियाटिक सागर के दक्षिणी प्रवेश द्वार ओट्रांतो जलडमरूमध्य पर बाल्कन प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। 	
2.	<p>बेलारूस (राजधानी: मिन्स्क) एक विपक्षी पत्रकार को हिरासत में लिए जाने के पश्चात बेलारूस पर नए प्रतिबंध लागू करने में अमेरिका और अन्य देशों के साथ ब्रिटेन भी शामिल हो गया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> वर्ष 1991 में स्वतंत्र होने तक बेलारूस को बेलोरूसिया या व्हाइट रूस के नाम से जाना जाता था। उच्चतम बिंदु दज़ायज़िन्स्काया हिल (Dzyarzhynskaya Hill) है। नीपर नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बेलारूस से प्रवाहित होती है। यह काला सागर में गिरती है। 	
3.	<p>जॉर्जिया (राजधानी: त्बिलिसी) हाल ही में भारत ने महारानी केतेवन के 400 वर्ष प्राचीन अवशेष, जॉर्जिया को हस्तांतरित किए हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> रानी केतेवन के अवशेष 1627 ई. में पुरातन पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा गोवा के सेंट ऑगस्टीन चर्च में लाए गए थे। जॉर्जिया काला सागर के पूर्वी तट पर ग्रेटर काकेशस पर्वत के मुख्य शिखर के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। इंगुरी, रियोनी और कोडोरी इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। 	
4.	<p>पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट, फ्रांस (Port of Brest, France) संचालनरत विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में, INS तबर ने पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट में प्रवेश किया।</p> <ul style="list-style-type: none"> यह पेनफेल्ड नदी द्वारा विभाजित दो पहाड़ियों की ढलानों पर स्थित है। यह क्वेर्लर्न प्रायद्वीप द्वारा समुद्र से संरक्षित है। 	
5.	<p>लिथुआनिया (राजधानी: विलिनियस) यूरोपीय संघ ने चीन के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन (WTO) में कार्रवाई शुरू की है। चीन पर यह कार्रवाई ताइवान पर उसके पक्ष को लेकर लिथुआनिया को लक्षित करने के विरुद्ध की जा रही है।</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • लिथुआनिया ने इससे पहले मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ चीन के 17+1 सहयोग मंच को छोड़ दिया था। • नेमन नदी इसकी प्रमुख नदी है। • लिथुआनियाई भू परिदृश्य की एक विशिष्ट विशेषता लगभग 3,000 झीलों की उपस्थिति है, जो अधिकतर पूर्व और दक्षिण-पूर्व में स्थित हैं। 	
<p>6.</p>	<p>स्लोवेनिया</p> <p>हाल ही में, भारत और स्लोवेनिया ने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय विकास पर 8वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया।</p> <ul style="list-style-type: none"> • स्लोवेनिया ज्यादातर पहाड़ी और वनाच्छादित है। डिनारिक एल्प्स और जूलियन आल्प्स देश के आर-पार स्थित हैं। • डेन्यूब इसकी प्रमुख नदी है। 	
<p>7.</p>	<p>उत्तरी आयरलैंड (राजधानी: बेलफास्ट)</p> <p>यूरोपीय संघ ने उत्तरी आयरलैंड पर ब्रेक्जिट पश्चात नए समझौते की ब्रिटेन की मांग को खारिज कर दिया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड के द्वीप के लगभग छोटे हिस्से तक विस्तारित है। यह नॉर्थ चैनल द्वारा पूर्व में स्कॉटलैंड (यूके) से अलग हो जाता है। आयरिश सागर उत्तरी आयरलैंड को क्रमशः पूर्व और दक्षिण-पूर्व में इंग्लैंड एवं वेल्स से पृथक करता है। • एंटीम पर्वत, मोर्ने पर्वत और स्पेरिन पर्वत प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। • बान, ब्लैक वॉटर और लगान प्रमुख नदियां हैं। 	

8.

कोसोवो (राजधानी: प्रिस्टिना)

हाल ही में, भारत एवं सर्बिया ने कश्मीर और कोसोवो पर क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता पर एक-दूसरे की स्थिति की पुष्टि की है।

- कोसोवो सर्बिया (राजधानी: बेलग्रेड) का हिस्सा है, जो यूगोस्लाविया का उत्तराधिकारी और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सह-संस्थापक है।
- वर्ष 2008 में, कोसोवो ने सर्बिया से अपनी एकतरफा स्वतंत्रता की घोषणा की थी, जिसे बड़े पैमाने पर संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रमुख यूरोपीय संघ के देशों द्वारा केवल एक देश के रूप में मान्यता दी गई थी।
- यहाँ अल्बानियाई नृजातीयता के लोगों की अधिकता है।



व्यक्तित्व परीक्षण कार्यक्रम

सिविल सेवा परीक्षा 2021

प्रोग्राम की विशेषताएँ

- ★ Vision IAS के वरिष्ठ संकाय सदस्यों के साथ DAF विश्लेषण सेशन
- ★ पूर्व-प्रशासनिक अधिकारियों/शिक्षाविदों के साथ मॉक इंटरव्यू सेशन
- ★ विगत वर्षों के टॉपर्स तथा वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद
- ★ प्रदर्शन मूल्यांकन एवं प्रतिक्रिया
- ★ मॉक इंटरव्यू सेशंस की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवायी जाएगी

प्रवेश
प्रारम्भ



7. अंतर्राष्ट्रीय संगठन/ संस्थान (International Organization/ Institutions)

7.1. संयुक्त राष्ट्र (United Nations)

सुखियों में क्यों?

24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र (UN) दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में किए गए भारत के योगदानों को रेखांकित किया।

भारत और संयुक्त राष्ट्र

- संयुक्त राष्ट्र (UN) वर्ष 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी प्राथमिक भूमिका वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। भारत UN का संस्थापक सदस्य है।
- भारत का योगदान और हालिया घटनाक्रम:

उपनिवेशवाद और रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष	<ul style="list-style-type: none"> भारत औपनिवेशिक देशों और नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा का सह-प्रायोजक था। भारत संयुक्त राष्ट्र में रंगभेद का मुद्दा उठाने वाला प्रथम देश था। भारत नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अभिसमय के आरंभिक हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था।
शांति स्थापना	<ul style="list-style-type: none"> भारत ने विगत कुछ वर्षों में 49 संयुक्त राष्ट्र शांति-स्थापना मिशनों में ढाई लाख से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। भारत, लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन के लिए गठित पुलिस इकाई के लिए एक पूर्ण महिला दल को तैनात करने वाला प्रथम देश था। हाल ही में, भारत ने विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना कर्मियों के लिए कोविड-19 टीकों की 2,00,000 खुराक प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में <ul style="list-style-type: none"> शांति अभियान अपने अधिदेश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से प्राप्त करते हैं। सैनिकों और पुलिस की आपूर्ति सदस्य देशों द्वारा की जाती है। यह अभियान तीन बुनियादी सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं यथा: पक्षकारों की सहमति; निष्पक्षता तथा आत्मरक्षा और अधिदेश की रक्षा के अतिरिक्त बल का प्रयोग न करना। <ul style="list-style-type: none"> भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म (UNITE Aware Platform) लॉन्च किया है। यह एक स्थितिजन्य जागरूकता सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। यह शांति स्थापक सैनिकों के लिए वास्तविक समय (realtime) में खतरे के आकलन हेतु आधुनिक निगरानी तकनीक का उपयोग करेगा।
विकास और आर्थिक मुद्दे	<ul style="list-style-type: none"> व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1964 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD/ अंकटाड²⁹ की स्थापना में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत ने विकासशील देशों के लिए आधिकारिक विकास सहायता के प्रवाह को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है।
आतंकवाद / मानव अधिकार	<ul style="list-style-type: none"> भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय का प्रारूप तैयार करने की पहल की है। भारत ने मानवाधिकारों पर सार्वभौम घोषणा का प्रारूप तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में वर्ष 2022-24 के कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित कर लिया गया है। UNHRC में 47 सदस्य देश शामिल हैं। इन्हें महासभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत रूप से चयनित किया जाता है। <ul style="list-style-type: none"> परिषद के सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए सेवा प्रदान करेंगे। लगातार दो कार्यकालों के बाद तत्काल पुनः निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होंगे।
संयुक्त राष्ट्र में सुधार और पुनर्गठन	<ul style="list-style-type: none"> भारत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार व विस्तार पर G4 (भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान) तथा L.69 (एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के समान विचारधारा वाले देशों का समूह) के साथ सहयोग कर रहा है।

²⁹ United Nations Conference on Trade and Development

7.1.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council: UNSC)

सुर्खियों में क्यों?

भारत ने वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अध्यक्षता ग्रहण की।
अन्य संबंधित तथ्य

- भारत का अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल 1 जनवरी, 2021 को आरंभ हो गया था। UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में यह भारत का आठवाँ कार्यकाल है।
 - यह पद प्रत्येक सदस्य देश द्वारा सदस्य देशों के नामों के वर्णमाला क्रम के अनुसार बारी-बारी से एक माह तक धारण किया जाता है।
- अध्यक्ष के रूप में, भारत एक एजेंडा का निर्धारण करेगा, जिसके संकल्प और निर्देश सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी होंगे।
 - भारत ने तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों यथा- समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का सामना और शांति स्थापना पर उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित करने का अपना एजेंडा निर्धारित किया है।
 - शांति सैनिकों के लिए "स्थितिजन्य जागरूकता में सुधार" तथा क्षेत्र की जानकारी हेतु एक मोबाइल ऐप- "यूनाइट अवेयर" (UNITE AWARE) को भी अभिनियोजित करने की अपेक्षा की जा रही है।

UNSC के बारे में

- UNSC संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से एक है। इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।
 - संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रमुख अंग महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC), न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय हैं।
- भारत जर्मनी, जापान और ब्राजील (G-4 राष्ट्र) के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए प्रयास कर रहा है।
 - इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको और मिस्र जैसे देशों को शामिल करने वाले कॉफी क्लब ने भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का विरोध किया है।

संबंधित सुर्खियाँ

भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 'UNSC संकल्प 2593' को अंगीकृत किया है

- UNSC संकल्प 2593 अफगानिस्तान (UNSC में भारत की अध्यक्षता के दौरान अपनाया गया) के संबंध में लाया गया भारत समर्थित एक UNSC संकल्प है। इसे अफगानिस्तान संकट को संबोधित करने हेतु अपनाए जाने वाले एक वैश्विक दृष्टिकोण पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए लाया गया है।
 - यह तालिबान से जवाबदेही को सुनिश्चित करने का आह्वान करता है, ताकि उसके द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र का उपयोग आतंकवाद या किसी अन्य देश पर हमले के लिए न किया जाए।
 - यह अल्पसंख्यकों और महिलाओं की भागीदारी सहित वार्ता आधारित राजनीतिक समाधान के माध्यम से एक समावेशी सरकार की स्थापना का भी आह्वान करता है।
- मुख्य रूप से अफगानिस्तान मुद्दे पर आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन भी इसे और सुदृढ़ता प्रदान करने में मदद करेगा।

UNSC संकल्प 2615 (UNSC resolution 2615)

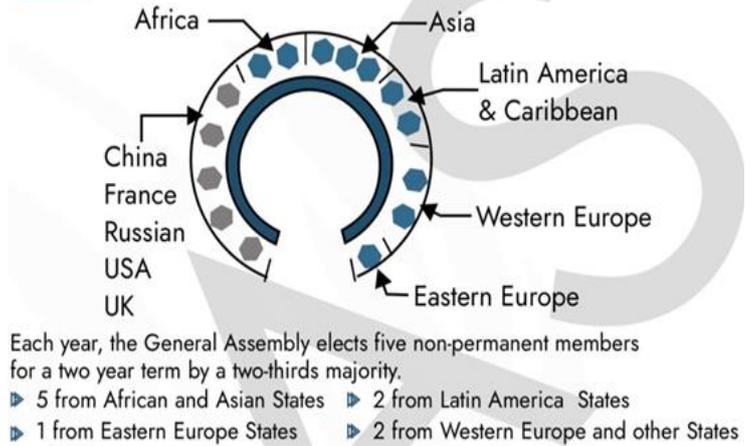
- UNSC ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है।
- संकल्प 2615 के बारे में

UN Security Council members

5 Permanent Members (having Veto Powers)



10 Non-Permanent Members (no Veto Powers)



- इसके अंतर्गत तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के संबंध में 2255 एवं 1988 के प्रस्तावों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों में मानवीय सहायता के लिए छूट प्रदान की गयी है।
- इस संकल्प में प्रत्येक छह माह में इन कार्रवाइयों की अनिवार्य समीक्षा का प्रावधान भी है।

7.2. जी-20 (G20)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारत G20 'ट्रोइका' में शामिल हुआ है। साथ ही, भारत ने 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक G20 अध्यक्ष पद संभालने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है।

जी-20 या ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G20) के बारे में

- G20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाता है। इसके सदस्यों की भागीदारी वैश्विक GDP में 80 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार में 75 प्रतिशत और वैश्विक जनसंख्या में 60 प्रतिशत से अधिक है।
- वर्ष 1999 से प्रत्येक वर्ष इस मंच की बैठक होती है, जिसे वर्ष 2008 से राष्ट्राध्यक्षों और सरकार की भागीदारी द्वारा एक वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में आयोजित किया जाता है।
- शिखर सम्मेलन के अलावा, पूरे वर्ष के दौरान **मंत्रिस्तरीय बैठकें**, **शेरपा बैठकें** (वार्ता को अंतिम रूप देने और नेताओं के बीच आम सहमति बनाने के लिए), **कार्य समूह और विशेष कार्यक्रम** आयोजित किए जाते हैं।
- **G20 के उद्देश्य हैं:**
 - वैश्विक आर्थिक स्थिरता एवं सतत विकास प्राप्त करने के लिए अपने सदस्यों के मध्य **नीतिगत समन्वय**;
 - जोखिम को कम करने तथा भविष्य के संभावित वित्तीय संकटों की रोकथाम के लिए **वित्तीय विनियमन को प्रोत्साहित करना**; तथा
 - एक नवीन **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना** का निर्माण करना।
- **G20 में दो कार्यशील ट्रैक हैं:**
 - **वित्त ट्रैक (Finance Track):** इसमें प्रमुख रूप से वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों, जैसे कि मौद्रिक, राजकोषीय और विनियम दर नीतियों, अवसंरचना निवेश, वित्तीय समावेशन और अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर ध्यान दिया जाता है।
 - **शेरपा ट्रैक (Sherpa Track):** इसमें व्यापक मुद्दों, जैसे- राजनीतिक संबद्धता, भ्रष्टाचार का विरोध, विकास, व्यापार, लैंगिक समानता, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है:** इसकी कार्यसूची और गतिविधियां सदस्यों के आपसी सहयोग से विभिन्न सदस्यों को चक्रीय क्रम में अध्यक्षता (G20 ट्रोइका) प्रदान करके निर्धारित की जाती है।
 - एक **"ट्रोइका (नेता के रूप में कार्य करने वाले तीन लोग)"** G20 के भीतर निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। इसमें उन तीन देशों के प्रतिनिधि होते हैं, जिनमें से एक आयोजन करने जा रहा है, दूसरा पूर्ववर्ती आयोजक और तीसरा भावी आयोजक होता है।
 - वर्तमान में ट्रोइका देश **इंडोनेशिया, इटली और भारत** हैं।
 - ट्रोइका सदस्य के रूप में, भारत G20 के एजेंडे की संगतता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए **इंडोनेशिया और इटली** के साथ मिलकर कार्य करेगा।
- **G20 को कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन प्राप्त है** जिसमें वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD), संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन शामिल हैं।



- भारत G20 का एक संस्थापक सदस्य है और इसने नए विचारों को प्रस्तावित करने और समाधान खोजने में सक्रिय भूमिका निभाई है।

7.3. विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation: WHO)

सुर्खियों में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा प्रस्तावित सतत वित्त-पोषण मॉडल³⁰ का विरोध कर रहा है।

WHO का वर्तमान वित्त-पोषण मॉडल:

- WHO के बजट में साधारणतः दो प्रकार के वित्त-पोषण शामिल हैं- आकलित योगदान (assessed contributions) और स्वैच्छिक योगदान (voluntary contributions)।
- WHO के कार्यों को पहले पूरी तरह से सदस्य राज्यों के आकलित योगदान द्वारा वित्त पोषित किया जाता था।
- वर्ष 1990 तक स्वैच्छिक योगदान का हिस्सा बढ़कर कुल फंड का 54% हो गया था। वर्तमान में, इसका कुल हिस्सा WHO की कुल आय का 80% से अधिक है।
- पिछले कुछ वर्षों में WHO का बजट व्यापक स्तर पर बढ़ गया है। यह वर्ष 1990-1991 के 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से वर्ष 2020-2021 में 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है। इसमें आकलित योगदान का हिस्सा लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर रहा है।

प्रस्तावित सतत वित्त-पोषण मॉडल के बारे में WHO के कार्यकारी समूह ने सतत वित्त-पोषण पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसमें सदस्यों के अनिवार्य योगदान को वर्ष 2028 तक एजेंसी के मुख्य बजट के 50 प्रतिशत तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। वर्तमान में अनिवार्य योगदान का हिस्सा 20 प्रतिशत से कम है।

WHO के मुख्य कार्य

स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर मुद्दों पर नेतृत्व प्रदान करना और जहाँ साझा कार्रवाई की आवश्यकता है, वहाँ साझेदारी को बढ़ाना	अनुसंधान एजेंडा को आकार प्रदान करना, पीढ़ीगत अंतरण को प्रेरित करना तथा बहुमूल्य ज्ञान का प्रसार करना	मानदंड एवं मानक तय करना तथा उनके कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना एवं समीक्षा करना	प्रमाणित एवं नैतिक अभिव्यक्ति आधारित नीतिगत विकल्पों को स्पष्ट रूप से रखना	तकनीकी सहायता प्रदान करना बदलावों को प्रेरित करना तथा संधारणीय संस्थागत क्षमता विकसित करना	स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी करना एवं स्वास्थ्य प्रवृत्तियों का आकलन करना

7.4. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से देशों का निलंबन/निष्कासन (Suspension/Expulsion of countries from International Organisations)

सुर्खियों में क्यों?

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता पर अधिकार करने के बाद से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अफगानिस्तान की सदस्यता को लेकर प्रश्न किए जा रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सदस्य देशों के निष्कासन या निलंबन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून

इस मुद्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को सामान्य तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है:

सदस्य देशों के निष्कासन या निलंबन के प्रावधान को स्पष्ट रूप से लागू करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन	अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनके द्वारा अपने सदस्य देशों के निष्कासन या निलंबन के संबंध में किसी प्रकार के कोई प्रावधान लागू नहीं किए गए हैं
<ul style="list-style-type: none"> उदाहरण के लिए, <ul style="list-style-type: none"> संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 6 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा को किसी देश को निष्कासित 	<ul style="list-style-type: none"> ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में किसी सदस्य राज्य को निष्कासित या निलंबित करने हेतु कोई अंतर्निहित प्रावधान नहीं किए गए हैं। SAARC इसी श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। हालांकि, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को होने वाले नुकसानों के

³⁰ Sustainable Financing Model

<p>करने की शक्ति प्रदान करता है, यदि उस देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर में दर्शाए गए सिद्धांतों का लगातार उल्लंघन किया गया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 5 किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है। ○ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुच्छेद XXVI (2) में भी किसी सदस्य देश के निलंबन और निष्कासन की संभावना पर विचार करने का अधिकार प्रदान किया गया है, यदि वह IMF के अनुच्छेदों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है। IMF की शब्दावली में इसे 'अनिवार्य निकासी' (compulsory withdrawal) के रूप में संदर्भित किया जाता है। 	<p>क्षतिपूर्ति के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के आधार पर देशों को निलंबित या निष्कासित करने की अंतर्निहित शक्ति प्रदान की गई है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● इस सिद्धांत के अनुसार, निम्नलिखित तीन स्थितियों के आधार पर किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय संगठन से निष्कासित या निलंबित किया जा सकता है: <ul style="list-style-type: none"> ○ यदि किसी देश की शासन प्रक्रिया लोकतांत्रिक से अलोकतांत्रिक हो जाती है। उदाहरण के लिए, अफ्रीकी संघ ने रक्तपात आधारित तख्तापलट के बाद वर्ष 2010 में माली और नाइजर को निलंबित कर दिया था। ○ यदि मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रमंडल ने वर्ष 2009 में फिजी को मानवाधिकारों के उल्लंघन (जैसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध, संघ निर्माण पर प्रतिबंध और मनमानी गिरफ्तारी) के लिए निलंबित कर दिया था। ○ यदि वह देश सशस्त्र आक्रमण जैसी गतिविधियों में शामिल होता है।
--	--

7.5. शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation: SCO)

सुखियों में क्यों?

हाल ही में, SCO की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 16वीं बैठक ताजिकिस्तान (SCO का वर्तमान अध्यक्ष) के दुशांबे में आयोजित की गई।

इस बैठक के मुख्य बिन्दुओं पर एक नज़र

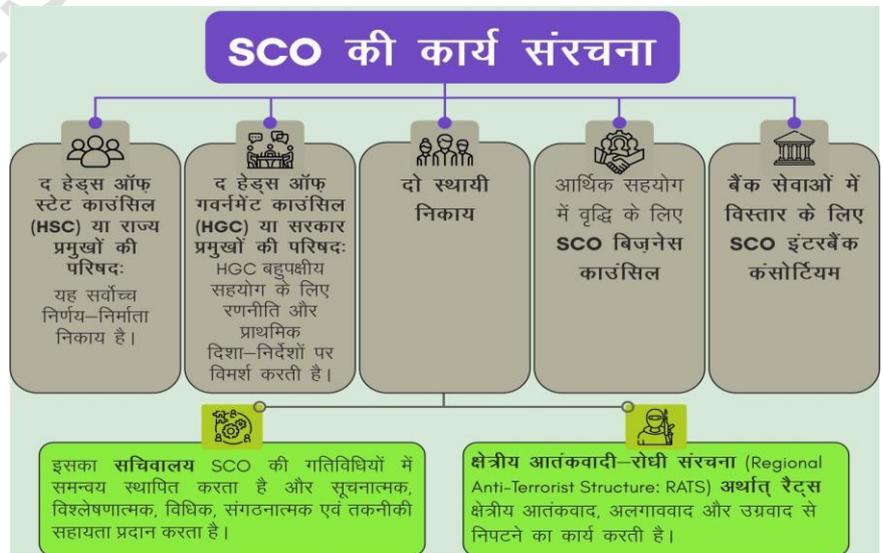
- इस दौरान ईरान, SCO के स्थायी सदस्य के रूप में तथा सऊदी अरब, मिस्र और कतर SCO के संवाद भागीदार के रूप में शामिल हुए।
- SCO शिखर सम्मेलन के उपरांत SCO और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (CSTO)³¹ के मध्य अफगानिस्तान पर आउटरीच सत्र आयोजित किया गया। इसमें भारत द्वारा SCO क्षेत्र में व्यापक रूप से बढ़ते कट्टरपंथ तथा उग्रवाद के कारण उत्पन्न समस्याओं को रेखांकित किया गया।

SCO के बारे में

- यह वर्ष 2001 में शंघाई में स्थापित एक स्थायी अंतर-सरकारी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है।
 - शंघाई-5 SCO का एक पूर्ववर्ती संगठन रहा है, जिसमें चीन, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान, ये पांच सदस्य शामिल थे।
 - क्षेत्रीय विकास एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दे (आतंकवाद, नृजातीय

सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (Collective Security Treaty Organization: CSTO)

- CSTO रूस के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन है। यह किसी भी सदस्य पर हुए बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रदान करता है।
 - CSTO की उत्पत्ति वर्ष 1992 में एक सामूहिक सुरक्षा संधि से हुई थी। इस संधि पर रूस और कुछ मध्य एशियाई देशों ने हस्ताक्षर किए थे।
 - CSTO, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) की तरह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है।
- वर्तमान सदस्य: आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, रूस और ताजिकिस्तान।



³¹ Collective Security Treaty Organisation

अलगाववाद और धार्मिक अतिवाद) इस संगठन के कार्य के केंद्रीय विषय रहे हैं।

- SCO के 4 सदस्य (भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान) परमाणु हथियार वाले देश हैं और 2 सदस्य देश (रूस एवं चीन) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं।
- भू-क्षेत्र के संदर्भ में SCO का अपना एक विशिष्ट प्रभाव है, जो NATO की तुलना में कहीं अधिक है।

- शंघाई फाइव (5) — चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान।
- कार्यप्रणाली में प्रयुक्त भाषा: रशियन एवं मंदारिन।
- SCO, विश्व की कुल GDP में 24% और कुल वैश्विक जनसंख्या में 43% की हिस्सेदारी रखता है।
- "शंघाई स्पिरिट" अर्थात् आपसी विश्वास, परस्पर लाभ, समानता, परामर्श, सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान और साझे विकास की ओर लक्षित होना SCO की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाते हैं।

सदस्य राष्ट्र



7.6. दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ (Association of South East Asian Nations: ASEAN)

सुखियों में क्यों?

भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को आसियान के डिजिटल मंत्रियों (ADGMIN) की दूसरी बैठक में अनुमोदित किया गया था। यह आसियान के 10 देशों के दूरसंचार मंत्रियों की वार्षिक बैठक थी।

आसियान के बारे में

- आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है। इसे एशिया-प्रशांत क्षेत्र के उत्तर-औपनिवेशिक देशों के बीच बढ़ते तनाव के चलते राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।
- इसकी स्थापना वर्ष 1967 में इसके संस्थापकों द्वारा आसियान घोषणा-पत्र (बैंकॉक घोषणा-पत्र) पर हस्ताक्षर के बाद हुई थी।
- आसियान के संस्थापक राष्ट्र हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड।





- भारत वर्ष 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना था।
- आसियान का आदर्श वाक्य "एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय (One Vision, One Identity, One Community)" है।
- आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है।
- आसियान, यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिकी बाजारों के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है और विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (एशिया में तीसरा) है।
- आसियान ने खुद को परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित किया है।

भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 में शामिल हैं:

- नकली और चोरी किए गए मोबाइल हैंडसेट के उपयोग से निपटना।
- राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक इंटरनेट के लिए वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस बनाना।
- क्षमता निर्माण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उभरने वाले पक्षों के बारे में जानकारी साझा करना।

7.7. 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (13th BRICS summit)

सुखियों में क्यों?

हाल ही में, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- इस शिखर सम्मेलन का थीम था- "ब्रिक्स के 15 वर्ष: निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर-ब्रिक्स सहयोग" (BRICS@15: Intra-BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation and Consensus)।
 - ये उपर्युक्त चार 'C' (Four Cs) एक प्रकार से ब्रिक्स साझेदारी के मूलभूत सिद्धांत हैं।
- 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र:
 - भारत के प्रधान मंत्री ने कोविड के पश्चात् वैश्विक रिकवरी के लिए "प्रत्यास्थ, नवोन्मेषी, विश्वसनीय और संधारणीय पुनर्निर्माण³²" के आदर्श वाक्य के अंतर्गत ब्रिक्स देशों के मध्य सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
 - इस दौरान "नई दिल्ली घोषणा-पत्र" को अंगीकृत किया गया। इसके तहत निम्नलिखित का आह्वान किया गया:
 - शांतिपूर्ण तरीकों से अफगान संकट का समाधान करना।
 - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) सहित संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में सुधार करना।
 - ब्रिक्स ने "बहुपक्षीय प्रणालियों को मजबूत करने तथा उनमें सुधार करने" पर सामूहिक एकजुटता व्यक्त की है।
 - मानवीय संकट की स्थितियों का समाधान करना तथा महिलाओं, बच्चों एवं अल्पसंख्यकों सहित सभी के मानवाधिकारों की रक्षा करना।
 - आतंकवाद विरोधी कार्य योजना³³ के कार्यान्वयन में तेजी लाना।
 - अंतरिक्ष एजेंसियों तथा सुदूर संवेदी उपग्रहों पर समझौते से वैश्विक जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, खाद्यान्न और जल संकट की रोकथाम आदि में अनुसंधान क्षमताओं में वृद्धि होगी।
 - कृषि सहयोग कार्ययोजना (वर्ष 2021-2024) अंगीकृत की गई।

ब्रिक्स के बारे में

- ब्रिक्स, प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।
- ब्रिक्स देश निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करते हैं:
 - विश्व की जनसंख्या का 41 प्रतिशत।
 - विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 24 प्रतिशत।
 - विश्व व्यापार में 16% से अधिक हिस्सेदारी।
- ब्रिक्स देश निम्नलिखित तीन स्तंभों के तहत अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं:
 - राजनीति और सुरक्षा,
 - आर्थिक और वित्तीय
 - सांस्कृतिक और लोगों के बीच समन्वय।
- ब्रिक्स के दो महत्वपूर्ण संस्थान:
 - न्यू डेवलपमेंट बैंक: यह ब्रिक्स देशों में बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है।

³² Build-back Resiliently, Innovatively, Credibly and Sustainably

³³ Action Plan on Counter-Terrorism

- आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था (Contingent Reserve Arrangement): भुगतान संतुलन में संकट से प्रभावित देशों के लिए एक वित्तीय स्थिरता तंत्र।
- 1 जनवरी, 2022 को, चीन ने आधिकारिक तौर पर BRICS की अध्यक्षता ग्रहण की। अब चीन 14वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

संबंधित सुर्खियाँ

वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आभासी रूप में आयोजित की गई

- शेरपा के बारे में:
 - एक शेरपा, एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जैसे G8, G20 आदि में सदस्य देश के नेता का निजी प्रतिनिधि होता है।
 - यह शब्द नेपाली शेरपा लोगों से लिया गया है। ये हिमालय में पर्वतारोहियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं।
- वे एजेंडे का समन्वय करते हैं तथा आम सहमति बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, अपने नेताओं का पक्ष रखते हुए चर्चा में मदद करने के लिए शिखर सम्मेलन-पूर्व परामर्शों में भाग लेते हैं।
- प्रति सदस्य देश के लिए प्रत्येक शिखर सम्मेलन में केवल एक शेरपा होता है।

हाल ही में भारत द्वारा ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक की मेजबानी की गई

- भारत ने STI के नेतृत्व वाले ब्रिक्स इनोवेशन कोऑपरेशन एक्शन प्लान (2021-24) का प्रस्ताव रखा है, ताकि एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध और बिग डेटा एनालिटिक्स सहित 10 विषयगत क्षेत्रों में एक-दूसरे के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के अनुभवों को साझा करने की सुविधा प्रदान की जा सके।

7.7.1. ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक (BRICS New Development Bank)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में मित्र का चौथे नये सदस्य के रूप में स्वागत किया है। इससे पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे भी सितंबर 2021 में इससे जुड़े थे।

NDB के बारे में

- NDB एक बहुपक्षीय विकास संस्थान (MDI) है। इसे छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान फोर्टलेजा (2014) में स्थापित किया गया था। ब्रिक्स (BRICS) देशों में शामिल हैं- ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका।
- इस बैंक की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए खुली है।
- उद्देश्य: NDB के पास 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अधिकृत पूंजी है। NDB ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती हुई एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक व निजी बुनियादी ढांचे तथा टिकाऊ विकास परियोजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
- शासन संरचना: इसके कार्यों को एक शासक मंडल, एक निदेशक मंडल, एक अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के माध्यम से संपादित किया जाता है। इसमें चक्रानुक्रम के आधार पर संस्थापक सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष के रूप में चयनित किया जाता है।



भारतीय सदस्यता वाले प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय बहुपक्षीय विकास संस्थान (MDIs)				
बहुपक्षीय विकास संस्थानों के नाम	स्थापना वर्ष	मुख्यालय	कुल सदस्य	वित्तपोषण का प्रकार
विश्व बैंक समूह*	IBRD - 1944 IFC - 1956 IDA - 1960 MIGA - 1988	वॉशिंगटन डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका	IBRD - 189 IFC - 185 IDA - 173 MIGA - 182	रियायती और गैर रियायती ऋण, इक्विटी निवेश, अनुदान (ग्रांट) और ऋण संबंधी गारंटी (अधीनस्थ / उप-संस्थानों के लिए)
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	1944	वॉशिंगटन डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका	190	यह मुख्य रूप से नीतिगत सुधारों को अपनाए जाने के शर्त पर ऋण देता है। इन नीतिगत सुधारों में शामिल हैं- निजीकरण, कृषि या विद्युत क्षेत्र में नीतिगत सुधार आदि।
अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप (AFDB)	AFDB - 1964 अफ्रीकन डेवलपमेंट फंड (ADF) - 1972	आबिदजान (आइवरी कोस्ट)	81	गैर-रियायती और रियायती ऋण, इक्विटी निवेश, और ADF द्वारा ऋण की गारंटी के रूप में अनुदान
एशियाई विकास बैंक (ADB)	ADB - 1966 एशियन डेवलपमेंट फंड (ADF) - 1973	फिलीपिंस के मनीला शहर का मंडालुयोंग	68	गैर-रियायती और रियायती ऋण, इक्विटी निवेश, और एशियन डेवलपमेंट फंड द्वारा ऋण की गारंटी के रूप में अनुदान
न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)	2004	शंघाई, चीन	8 (हालिया विस्तार के बाद)**	गारंटी, निजी निवेशकों की मदद से सामूहिक ऋण, इक्विटी निवेश, प्रोजेक्ट बॉण्ड और अन्य प्रमुख विकास संस्थानों के साथ मिलकर वित्तपोषण की व्यवस्था
एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB)	2016	बीजिंग, चीन	103	ऋण, किसी उद्यम की इक्विटी पूंजी में निवेश, अंडर-राइटिंग (जोखिम अंकन) के ओपन ऑप्शन के साथ गारंटी प्रदान करना

*विश्व बैंक समूह (World Bank Group) के अंतर्गत शामिल हैं- (i) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD), (ii) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA), (iii) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC), (iv) बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA), और (v) निवेश संबंधी विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID)। ज्ञातव्य है कि विश्व बैंक पद सामूहिक रूप से IBRD और IDA को संदर्भित करता है।

नोट- भारत ICSID का सदस्य नहीं है।

** यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यू.ए.ई. और उरुग्वे को भावी सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया है। हालांकि, ये देश तभी इसमें सदस्य के रूप में शामिल हो पाएंगे, जब ये दाखिला दस्तावेज़ (instrument of accession) सौंप देंगे।

7.8. सार्क (SAARC)

सुखियों में क्यों?

हाल ही में, सार्क की बैठक रद्द कर दी गई थी, क्योंकि सदस्य देश अफगानिस्तान की भागीदारी पर सहमत नहीं हो सके थे।

सार्क के बारे में

- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की स्थापना वर्ष 1985 में ढाका में SAARC चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
- ढाका बैठक में, सदस्य देशों ने एकीकृत कार्य योजना का भी शुभारंभ किया था।
 - इसमें सार्क देशों के बीच सहयोग के पांच क्षेत्रों को रेखांकित किया गया, यथा-
 - कृषि;
 - ग्रामीण विकास;
 - दूरसंचार;

SAARC के सदस्य देश

भारत भूटान पाकिस्तान नेपाल

बांग्लादेश मालदीव श्रीलंका अफगानिस्तान

इसके सात संस्थापक सदस्य हैं- बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसमें अफगानिस्तान बाद में 3 अप्रैल 2007 को शामिल हुआ।

- मौसम विज्ञान; और
- स्वास्थ्य और जनसंख्या गतिविधियां।
- सार्क का मुख्यालय और सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है।
- यह संगठन संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य देशों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों पर आधारित है।
- वर्ष 2005 में 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान सार्क का सबसे नया सदस्य बना।
- अंतिम सार्क शिखर सम्मेलन वर्ष 2014 (काठमांडू) में आयोजित किया गया था और भारत एवं पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण बाद के शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किए जा सके।
- वर्ष 2020 में, महामारी से निपटने के लिए सार्क नेताओं द्वारा 10 मिलियन का कोविड-19 आपातकालीन कोष शुरू किया गया था।

सार्क विशिष्ट निकायों में शामिल हैं:

- सार्क विकास कोष (SDF): इसका प्राथमिक उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, विकास आदि जैसे सामाजिक क्षेत्रों में परियोजना आधारित सहयोग का वित्तपोषण करना है।
- दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (SAU) भारत में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। SAU द्वारा प्रदान की गई डिग्रियां और प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों / संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली संबंधित डिग्री और प्रमाण-पत्र के समान हैं।
- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन की स्थापना सार्क सदस्य देशों के बीच समन्वय और सहयोग को प्राप्त करने और बढ़ाने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और वैश्विक बाजार में पहुंच प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र के लिए सामंजस्यपूर्ण मानक को विकसित करना है।

7.9. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ (Other Important News)

<p>अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग (International Law Commission: ILC)</p>	<p>भारतीय प्रोफेसर बिमल पटेल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है। उनका कार्यकाल पांच वर्ष के लिए होगा, जो 1 जनवरी, 2023 से शुरू होगा। पटेल भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं।</p> <p>ILC के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> • अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसके एक निकाय के रूप में की गयी थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रगतिशील विकास और इसके संहिताकरण को बढ़ावा देना है। • यह मुख्य रूप से सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित है, लेकिन यह निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में भी मामलों की सुनवाई कर सकता है। • इसमें 34 सदस्य होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ होते हैं।
<p>अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice: ICJ)</p>	<p>पाकिस्तान सरकार ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सैन्य अदालत द्वारा दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध अपील करने में मदद के लिए एक विधेयक पारित किया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • यह विधेयक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के वर्ष 2019 के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है। <p>ICJ, हेग के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> • यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। • संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से, यह एकमात्र ऐसा अंग है, जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। • महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है। • इसका निर्णय अंतिम होता है, और किसी मामले में बिना अपील के पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होता है।

<p>अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (International Criminal Police Organization: INTERPOL)</p>	<p>केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के लिए प्रतिनिधि चुना गया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> इंटरपोल एक अंतर सरकारी संगठन है, जो 194 सदस्य देशों के पुलिस बल के समन्वय में मदद करता है। इसका मुख्यालय फ्रांस के ल्योन में स्थित है। प्रत्येक सदस्य देश एक इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCB) की मेजबानी करता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को भारत के NCB के रूप में नामित किया गया है। 
<p>ओपेक और ओपेक + (OPEC and OPEC+)</p>	<p>संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और पेट्रोलीयम निर्यातक देशों के संगठन प्लस (ओपेक+) समूह के मध्य अप्रैल 2022 से आगे तेल उत्पादन में कटौती के लिए वैश्विक समझौते का विस्तार करने पर हालिया वार्ता आम सहमति तक नहीं पहुंच सकी है।</p> <p>कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में तेल की कीमतों में गिरावट की पृष्ठभूमि में, अप्रैल 2020 में ओपेक प्लस समूह ने बेहतर कीमत प्राप्त करने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में अत्यधिक कटौती हेतु दो वर्ष के एक आउटपुट पैकट पर हस्ताक्षर किए थे।</p> <p>ओपेक और ओपेक+ के बारे में</p> <ul style="list-style-type: none"> ओपेक (मुख्यालय- वियना) एक स्थायी, अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका गठन बगदाद सम्मेलन, 1960 में हुआ था। उद्देश्य: <ul style="list-style-type: none"> सदस्य देशों के बीच पेट्रोलीयम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना। पेट्रोलीयम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर मूल्य सुनिश्चित करना। उपभोक्ता देशों को पेट्रोलीयम की एक कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना और उद्योग में निवेश करने वालों को पूंजी पर उचित प्रतिलाभ सुनिश्चित करना। कच्चे तेल का निर्यात करने वाले 10 गैर-ओपेक देशों को ओपेक प्लस (+) देश कहा जाता है। इनमें अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल हैं। यह तेल का उत्पादन करने के लिए अन्य देशों की क्षमता का मुकाबला करने के लिए अस्तित्व में आया, जो ओपेक की आपूर्ति और कीमत को नियंत्रित करने की क्षमता को सीमित कर सकता है। 
<p>एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB)</p>	<ul style="list-style-type: none"> RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करना है।

	<ul style="list-style-type: none"> ○ इसकी स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। ● भारत AIIB का संस्थापक सदस्य है। भारत इसमें 7.6% वोटिंग शेयरों के साथ दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, जबकि चीन के पास सबसे ज्यादा 26.5% वोटिंग शेयर है। ● AIIB ने किसी भी अन्य सदस्य की तुलना में भारत के लिए अधिक ऋणों (28 परियोजनाओं के लिए 6.7 अरब डॉलर) को मंजूरी दी है।
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF)	<ul style="list-style-type: none"> ● यह सूचना की स्वतंत्रता की रक्षा और प्रचार में विश्व के अग्रणी गैर-सरकारी संगठनों में से एक है। यह पेरिस में स्थित है। ○ इसे संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को और यूरोपीय परिषद में सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। ○ यह प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित करता है। ● हाल ही में, RSF ने निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं: <ul style="list-style-type: none"> ○ वर्तमान में विश्व भर में 488 मीडिया पेशेवर बंदी हैं (25 वर्षों में सर्वाधिक)। ○ इसके विपरीत, पश्चिम एशिया में संघर्षों के सापेक्ष स्थायित्व के कारण इस वर्ष हत्या किये गए पेशेवरों की संख्या सबसे कम थी। ○ मीडिया पेशेवरों के लिए सबसे खतरनाक देश मेक्सिको, अफगानिस्तान, यमन और भारत हैं।
इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (Internet Governance Forum)	<p>भारत ने पहली बार इस मंच की मेजबानी की है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● इस कार्यक्रम का थीम "डिजिटल भारत के लिए समावेशी इंटरनेट" था। ● IGF इंटरनेट अभिशासन नीति पर विचार-विमर्श के लिए संयुक्त राष्ट्र-आधारित मंच है। यह इंटरनेट से संबंधित लोक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एक साथ एक मंच पर लाता है। ● यह इंटरनेट के इर्द-गिर्द अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण पर भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।



लाइव ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

अल्टरनेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2023 और 2024

DELHI: 10 MAY, 1 PM | 21 APR, 1 PM | 7 APR, 5 PM

- इसमें सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के सभी चार प्रश्न पत्रों के सभी टॉपिक, प्रारंभिक परीक्षा (सामान्य अध्ययन) एवं निबंध के प्रश्न पत्र का व्यापक कवरेज शामिल है।
- हमारा दृष्टिकोण प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर देने हेतु छात्रों की मौलिक अवधारणाओं एवं विश्लेषणात्मक क्षमता का निर्माण करना है।
- सिविल सेवा परीक्षा, 2022, 2023, 2024 के लिए हमारी PT 365 और Mains 365 की कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर्स की कक्षाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी (केवल ऑनलाइन कक्षाएं)।
- इसमें सिविल सेवा परीक्षा, 2022, 2023, 2024 के लिए ऑल इंडिया जी.एस. मेंस, प्रीलिम्स, सीसेट और निबंध टेस्ट सीरीज शामिल है।
- छात्रों के व्यक्तिगत ऑनलाइन पोर्टल पर लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा।



Scan the QR CODE to
download VISION IAS app

8. सुरक्षा से संबंधित मुद्दे (Issues Related To Security)

8.1. परमाणु निःशस्त्रीकरण (Nuclear Disarmament)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) 2021 रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में वैश्विक सैन्य भंडार में परमाणु हथियारों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है।

परमाणु निःशस्त्रीकरण क्या है?

- परमाणु निःशस्त्रीकरण परमाणु हथियारों में कमी या समाप्ति को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य एक परमाणु हथियार रहित स्थिति को प्राप्त करना है। पूर्ण परमाणु निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए डिन्यूक्लियराइजेशन (denuclearization) शब्द का भी प्रयोग किया जाता है।
- जातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए प्रथम प्रस्ताव में परमाणु हथियारों को समाप्त करने की मांग की थी।

इस रिपोर्ट से संबंधित अन्य तथ्य

- वर्ष 2020 के आरंभ में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या 150 थी, जो वर्ष 2021 के आरंभ में बढ़कर 156 हो गई है।
- पाकिस्तान और चीन के परमाणु हथियारों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।
- रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास कुल वैश्विक परमाणु हथियारों का 90% से अधिक विद्यमान है।

परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि परमाणु निःशस्त्रीकरण के लिए चिंताजनक संकेत प्रदर्शित करती है। यह बढ़ती इंगित करती है कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात् से वैश्विक परमाणु शस्त्रागार में गिरावट की प्रवृत्ति अवरुद्ध हुई है।

परमाणु निःशस्त्रीकरण की प्राप्ति हेतु उठाए गए कदम

परमाणु निःशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण एवं अप्रसार के लिए प्रमुख संधियाँ	संधि के अधिदेश
आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (Partial Test Ban Treaty: PTBT), 1963	<ul style="list-style-type: none"> यह वायुमंडल में, बाह्य अंतरिक्ष में, जल में या किसी देश के भीतर किसी भी क्षेत्र में परमाणु हथियारों के परीक्षण, जो उस देश के बाहर रेडियोएक्टिव अपशिष्ट का कारण हो, को प्रतिबंधित करती है।
परमाणु अप्रसार संधि (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: NPT), 1970	<ul style="list-style-type: none"> यह परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने, परमाणु निःशस्त्रीकरण की ओर बढ़ने तथा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। <ul style="list-style-type: none"> यह परमाणु हथियार संपन्न देशों द्वारा निःशस्त्रीकरण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक बहुपक्षीय संधि के तहत एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता है।
व्यापक परमाणु परीक्षण-प्रतिबंध संधि (Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty: CTBT)	<ul style="list-style-type: none"> यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो सभी परिवेशों में सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध आरोपित करती है। इसे वर्ष 1996 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था, परन्तु यह अभी तक लागू नहीं हुई है।
परमाणु हथियार निषेध संधि (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons: TPNW)	<ul style="list-style-type: none"> यह परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी साधन है, जो उनके पूर्ण उन्मूलन की दिशा में अग्रसर है। <ul style="list-style-type: none"> इसमें किसी भी परमाणु हथियार से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंधों का एक व्यापक समुच्चय शामिल है। इनमें परमाणु हथियारों का विकास, परीक्षण, उत्पादन, अधिग्रहण, धारण, भंडारण, उपयोग या उपयोग करने की धमकी देने से संबंधित उपक्रम शामिल हैं। इसे वर्ष 2020 में लागू किया गया है।

अप्रसार व्यवस्था

अप्रसार

गैर-परमाणु हथियार संपन्न देशों को कभी भी ऐसे हथियारों का अधिग्रहण नहीं करने और समय सुरक्षोपायों को स्वीकार करने के लिए अनुग्रह या एकमत करना।

निःशस्त्रीकरण

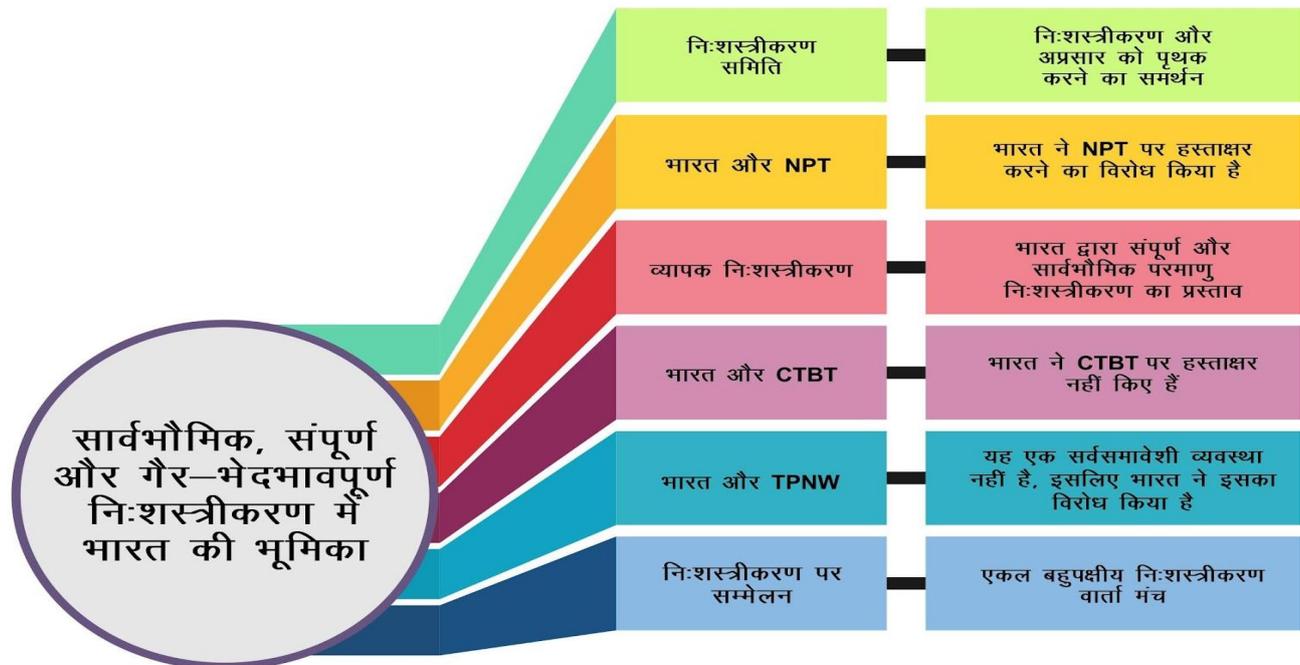
परमाणु हथियार संपन्न पांच देशों [यथा- यू.एस.ए., चीन, फ्रांस, सोवियत संघ (अब रूस) एवं यू.के.] को अपने परमाणु हथियारों की संख्या में कमी करने और अंततः उनके उन्मूलन पर चर्चा करने के लिए वार्ता की आवश्यकता पर बल देना।

परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग

गैर-परमाणु हथियार संपन्न देशों को परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों तक पूर्ण पहुंच प्रदान करने की गारंटी देना।

वैश्विक परमाणु निःशस्त्रीकरण में भारत की भूमिका

भारत द्वारा सदैव बहुपक्षीय परमाणु निःशस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार से संबंधित प्रयासों का प्रबल समर्थन किया गया है।



निःशस्त्रीकरण पर सम्मेलन (Conference on Disarmament: CD)

- इसका गठन वर्ष 1979 में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एकल बहुपक्षीय निःशस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में किया गया था। उल्लेखनीय है कि निःशस्त्रीकरण के प्रति समर्पित संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम विशेष सत्र (वर्ष 1978) के दौरान सदस्य देशों के मध्य समझौते पर पहुंचने के उपरांत इसकी स्थापना की गई थी।
- वर्ष 1996 में CTBT वार्ता के समापन के पश्चात् से ही, CD के संबंध में गतिरोध बना हुआ है। इस प्रकार यह वास्तविक विचार-विमर्श आरंभ करने के लिए एक कार्यवाही कार्यक्रम हेतु आम सहमति तक नहीं पहुंच पाया है।

भारत का परमाणु सिद्धांत

- भारत का उद्देश्य एक विश्वसनीय न्यूनतम निवारक³⁴ का निर्माण एवं अनुरक्षण (या प्रबंधन) करना है।
- भारत ने पहले प्रयोग न करने अर्थात् "नो फर्स्ट यूज" के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। परमाणु हथियारों का प्रयोग केवल भारत पर परमाणु हमले के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई में ही किया जाएगा।
- परमाणु प्रतिशोध के लिए प्रथम प्रहार व्यापक स्तर पर होगा और इसे अवांछनीय क्षति (unacceptable damage) पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- गैर-परमाणु संपन्न राष्ट्रों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करना।
- वैश्विक, सत्यापन योग्य एवं भेदभाव रहित परमाणु निःशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त करना।

³⁴ credible minimum deterrent

8.2. आतंकवाद-रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय {Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED)}

सुर्खियों में क्यों?

भारत ने आतंकवाद-रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय (CTED) के जनादेश को नवीनीकृत करने के लिए UNSC के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है।

CTED के बारे में

- CTED की स्थापना UNSC के प्रस्ताव 1535 के माध्यम से वर्ष 2004 में की गई थी। यह आतंकवाद रोधी समिति (CTC) का समर्थन करने वाला एक विशेषज्ञ निकाय है।

- CTED सदस्य देशों के

आतंकवाद-रोधी प्रयासों का आकलन करने के लिए आतंकवाद-रोधी समिति की ओर से सदस्य देशों का दौरा करता है। इस आकलन में की गई प्रगति, शेष कमी, तकनीकी सहायता आवश्यकताओं से संबंधित प्राथमिकता वाले क्षेत्र आदि शामिल हैं।

- CTC की स्थापना UNSC के प्रस्ताव 1373 (वर्ष 2001) द्वारा की गई थी। यह प्रस्ताव घरेलू, अपने संबद्ध क्षेत्रों और विश्व भर में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए UNSC के सभी सदस्य देशों के कानूनी एवं संस्थागत क्षमता को बढ़ाने वाले उपायों को लागू करने से संबंधित था।
 - इसकी स्थापना 9/11 के आतंकवादी हमले के पश्चात् की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की अपनी सीमाओं और क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की क्षमता को बढ़ाना है।
 - वर्तमान में, आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है।
 - भारत, वर्ष 2022 में CTC की अध्यक्षता करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के आतंकवाद विरोधी अन्य उपाय

ग्लोबल काउंटर – टेररिज्म फोरम (GCTF)

यह आतंकवाद का मुकाबला करने में प्रभावी बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के बाहर एक एक्शन-ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म (कार्रवाई-उन्मुख मंच) है।

काउंटर-टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स (CTITF)

इसे संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय और सुसंगतता को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति

यह आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक अद्वितीय वैश्विक साधन है।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT)

वर्ष 1996 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से इसे अपनाने का प्रस्ताव रखा था। (इसे अभी तक अपनाया नहीं गया है)।

संबंधित सुर्खियाँ

ब्रिक्स आतंकवाद-रोधी कार्य योजना (BRICS Counter Terrorism Action Plan)

भारत ने विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSAs) की 11वीं ब्रिक्स बैठक की मेजबानी की थी। इसके अंतर्गत आतंकवाद से निपटने के लिए कार्य योजनाओं को अपनाया गया।

- इस कार्य योजना का उद्देश्य आतंकवाद के वित्तपोषण एवं आतंकवाद का मुकाबला, आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग के मौजूदा तंत्र को और मजबूत करना है।

हाइब्रिड या पार्ट टाइम आतंकवादी (Hybrid terrorists)

- कश्मीर घाटी में आतंकी हमलों में वृद्धि दर्ज की गई है। ये हमले 'पार्ट टाइम या हाइब्रिड आतंकियों' द्वारा किए जा रहे हैं।
- हाइब्रिड आतंकवादियों के बारे में:
 - वे सुरक्षा बलों की आतंकी सूची में शामिल नहीं होते, लेकिन वे आतंकवादियों के संपर्क में रहते हैं।
 - “हाइब्रिड आतंकवादी” आसपास का कोई ऐसा लड़का हो सकता है, जिसे आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कट्टरपंथियों ने तैयार किया है और उसे स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है।
 - वह उसे सौंपे गए कार्य को संपन्न करता है और फिर अपने सरदार से अगले कार्य के मिलने की प्रतीक्षा करता है। इस बीच, वह सामान्य कामकाज करते हुए आम लोगों की तरह जीवन व्यतीत करता है।
 - ऐसे आतंकी 'आतंक और डर' का माहौल बनाने के लिए 'पिस्तौल व ग्रेनेड' जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं।
 - ये ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) से भिन्न होते हैं जो उग्रवादियों या आतंकवादियों को रसद सहायता, नकदी, आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं।

8.3. अंतरिक्ष युद्ध (Space Warfare)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने रूस पर आरोप लगाया कि उसने अंतरिक्ष में एक एंटी-सैटेलाइट हथियार का परीक्षण किया है। इस आरोप के बाद अंतरिक्ष युद्ध को लेकर चिंताएँ बढ़ गयी हैं।

अंतरिक्ष युद्ध के बारे में

- अंतरिक्ष युद्ध, बाह्य अंतरिक्ष में होने वाला युद्ध है। अंतरिक्ष युद्ध के दायरे में शामिल हैं:
 - स्थल से अंतरिक्ष युद्ध, जैसे कि पृथ्वी से उपग्रहों पर हमला करना;
 - अंतरिक्ष-से-अंतरिक्ष युद्ध, जैसे कि उपग्रहों पर हमला करने वाले उपग्रह; और
 - अंतरिक्ष-से-स्थल युद्ध, जैसे कि पृथ्वी पर स्थित लक्ष्यों पर हमला करने वाले उपग्रह।
- अंतरिक्ष युद्ध का भय वर्ष 1962 में उत्पन्न हुआ था, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक परमाणु हथियार का अंतरिक्ष में विस्फोट किया था। अंततः इसकी परिणति वर्ष 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) के रूप में हुई।

अंतरिक्ष संधियाँ

1967

बाह्य अंतरिक्ष संधि (OST)

- यह संधि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून पर बुनियादी ढांचा प्रदान करती है।
- इसे बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- भारत ने वर्ष 1982 में इस संधि की पुष्टि की थी।
- इस संधि के प्रमुख सिद्धांत:
 - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अंतरिक्ष का उपयोग
 - बाहरी अंतरिक्ष में संप्रभुता का दावा करने पर प्रतिबंध।
 - परमाणु हथियार की तैनाती पर प्रतिबंध।

1972

लायबिलिटी कन्वेंशन

- यह अंतरिक्ष पिंड के कारण होने वाली क्षति के लिए देयता के मानक निर्धारित करता है।

1975

रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन

- यह देशों की सभी अंतरिक्ष वस्तुओं को संयुक्त राष्ट्र के साथ पंजीकृत करना आवश्यक करता है।

1979

मून एग्रीमेंट

- यह सुनिश्चित करता है कि चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाये।



अंतरिक्ष में भारत की रक्षात्मक क्षमताएं

- **मिशन शक्ति:** वर्ष 2019 में, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया, जिसने एक ऊर्ध्वाधर उड़ान वाली एंटी-सैटेलाइट (ASAT) मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल ने पृथ्वी की निचली कक्षा में एक उपग्रह को लक्षित किया था।
 - इसने पूर्ण स्वदेशी तकनीक के आधार पर बाहरी अंतरिक्ष में एक उपग्रह को नष्ट और इंटरसेप्ट करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।
- **रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA)** की स्थापना थल सेना, नौसेना और वायु सेना की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के नियंत्रण के लिए की गई थी।
 - यह अंतरिक्ष-आधारित खतरों से निपटने सहित अंतरिक्ष में भारत के हितों की रक्षा के लिए एक रणनीति भी तैयार करती है।
- **रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Defence Space Research Organisation: DSRO):** DSA को तकनीकी और अनुसंधान सहायता प्रदान करने के लिए DSRO का गठन हुआ है।
- अंतरिक्ष में संघर्ष की स्थिति बढ़ने के दौरान प्रमुख चुनौतियों और कमियों की पहचान करने के लिए वर्ष 2019 में **इंड-स्पेस सैन्य अभ्यास (IndSpaceEx)** (सिम्युलेटेड स्पेस वारफेयर एक्सरसाइज) आयोजित किया गया था।

8.4. रक्षा निर्यात (Defence Exports)

सुखियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने फिलीपींस के साथ अपने पहले बड़े रक्षा प्रणाली निर्यात समझौते का औपचारिक करार किया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपर मिसाइल क्लूज मिसाइल के लिए 375 मिलियम डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

ब्रह्मोस के बारे में

- ब्रह्मोस, लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली एक सुपरसोनिक क्लूज मिसाइल प्रणाली है। इसे भूमि स्थित और समुद्र-आधारित लक्ष्यों के विरुद्ध भूमि, समुद्र और हवा से दागा जा सकता है।
 - ब्रह्मोस को एक संयुक्त सहयोग के आधार पर भारत {रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO)} और रूस (NPO मशीनो-स्टोनिया) द्वारा विकसित किया गया है।
 - इसका नामकरण भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर किया गया है।
- यह दो चरणों वाली मिसाइल है। पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट इंजन है।
 - यह दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है।
- मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR)³⁵ के तहत निर्धारित बाध्यताओं के कारण, मिसाइल की रेंज मूल रूप से 290 कि.मी. तय की गई थी।
 - भारत, वर्ष 2016 में MTCR में शामिल हुआ था। इसके बाद से इस सीमा को 450 कि.मी. और बाद के चरण में 600 कि.मी. तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।

अन्य समकक्ष मिसाइल प्रणालियाँ

- चीनी HD-1 सुपरसोनिक मिसाइल एक व्यापक हथियार प्रणाली है। इसमें मिसाइल, लॉन्च, कमान और नियंत्रण, लक्ष्य संकेतन व व्यापक समर्थन प्रणाली इत्यादि विशेषताओं को शामिल किया गया है।
 - इस मिसाइल को विमान और पोतों के साथ-साथ सामान्य भूमि आधारित सैन्य वाहनों से भी लॉन्च किया जा सकता है।
 - HD-1 को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम ईंधन की आवश्यकता होती है। इसके कारण मिसाइल का वजन हल्का हो जाता है। इससे यह तीव्र गति से और दूर तक उड़ान भरने में सक्षम हो जाती है।
- टॉमहॉक को अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा उपयोग किया जाता है। यह एक सबसोनिक क्लूज मिसाइल है। यह लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली तथा सभी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम मिसाइल है। इसे पोतों और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है। यह 1,000 मील दूर तक के लक्ष्य को सटीकता से भेद सकती है।
- इज़राइल की सी-ब्रेकर (Sea Breaker), 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाली स्वायत्त व सटीक-निर्देशित मिसाइल प्रणाली है। इसे महत्वपूर्ण समुद्री और भूमि आधारित लक्ष्यों को भेदने हेतु विकसित किया गया है।
- P-800 ओनिक्स/याखोंत (Oniks/Yakhont) एक रूसी सुपरसोनिक पोत-रोधी क्लूज मिसाइल है। इसे एक प्रभावी मार्गदर्शन प्रणाली के आधार पर विकसित किया गया है। यह 'दागो और भूल जाओ' सिद्धांत पर आधारित है।

रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्द्धन नीति (Defence Production & Export Promotion Policy: DPEPP) के प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य

- वर्ष 2025 तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा उपकरणों तथा सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपये का निर्यात सुनिश्चित करना। साथ ही, 1,75,000 करोड़ रुपये की कुल बिक्री के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- आयात पर निर्भरता को कम करना। घरेलू डिजाइन और विकास के माध्यम से "मेक इन इंडिया" पहल को आगे बढ़ाना।
- रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। साथ ही, वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनना।
- एक ऐसे परिवेश का निर्माण करना, जो अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करता हो, नवाचार को बल प्रदान करता हो तथा भारतीय बौद्धिक संपदा स्वामित्व का निर्माण करता हो।

भारत के रक्षा निर्यात में वृद्धि

1 भारत ने पिछले सात वर्षों में 38,500 करोड़ रुपये के सैन्य हार्डवेयर और सिस्टम का निर्यात किया है।

2

रक्षा निर्यात वर्ष 2016-17 के 1,521 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 8,434.84 करोड़ रुपये हो गया।

निर्यात किए गए प्रमुख शस्त्र

3 बख्तरबंद सुरक्षा वाहन, हल्के वजन वाले टारपीडो, हथियारों का पता लगाने वाले रडार, अग्नि नियंत्रण प्रणाली, अपतटीय गश्ती वाहन और आंसू गैस लांचर।

4

वर्तमान में, भारत, दुनिया भर के 75 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है।

5 तीन भारतीय कंपनियां शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की रैंकिंग 2020 में शामिल हैं - हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), आयुध निर्माणी बोर्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)।

6

वर्ष 2020 में, रक्षा खरीद और निर्यात प्रोत्साहन नीति (DPEPP) का मसौदा तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को एयरोस्पेस और नौसेना जहाज निर्माण क्षेत्रों सहित रक्षा क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करना है।

³⁵ Missile Technology Control Regime



हाल ही में, रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु स्वदेशीकरण से संबंधित सहायता (Indigenisation Support to MSMEs)	<ul style="list-style-type: none"> सरकार ने दो "सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची" जारी की है। इसमें 209 मदों को शामिल किया गया है। साथ ही, इन मदों के आयात को प्रतिबंधित किया गया है। इन्हें केवल घरेलू उद्योग से ही खरीदा जा सकता है। इसके अलावा, रक्षा बजट के पूंजीगत परिव्यय का कुछ प्रतिशत घरेलू उद्योग से खरीद हेतु आरक्षित किया गया है। सृजन (SRIJAN) पोर्टल MSMEs/स्टार्टअप/उद्योग को विकास सहायता प्रदान करेगा।
रक्षा उद्योग में लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण	<ul style="list-style-type: none"> विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)³⁶ ने विभिन्न मदों के निर्यात के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण के रूप में रक्षा उत्पादन विभाग (DDP)³⁷ को प्राधिकृत एवं अधिसूचित किया है। गृह मंत्रालय ने भी DDP को कुछ शक्तियां प्रदान की हैं। इसके परिणामस्वरूप यह छोटे हथियारों और गोला-बारूद के कलपुर्जों एवं घटकों के निर्यात हेतु निर्यातकों के लिए संपर्क का एकल बिंदु बन गया है। खुला सामान्य निर्यात लाइसेंस उद्योगों को, निर्धारित मदों के निर्दिष्ट गंतव्यों तक निर्यात की अनुमति प्रदान करता है।
निवेश प्रोत्साहन और व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of Doing Business: EoDB)	<ul style="list-style-type: none"> निर्यात प्राधिकरण की अनुमति हेतु आवेदन करने और स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से एंड-टू-एंड ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। कंपनी की विभिन्न शाखाओं के मध्य व्यवसाय में, आयातक देश की सरकार से अंतिम उपयोगकर्ता प्रमाण-पत्र (EUC)³⁸ प्राप्त करने की पूर्व आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। निर्यात के अवसरों की खोज करने और वैश्विक निविदाओं में भागीदारी के लिए DRDO एवं रक्षा से संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य प्रबंध निदेशकों (CMDs) को अधिकार सौंपे गए हैं।
रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए योजना (Scheme for Promotion of Defence Exports)	<ul style="list-style-type: none"> संभावित निर्यातकों को अपने उत्पाद को सरकार से प्रमाणित कराने के वैकल्पिक अवसर प्रदान किए गए हैं। उत्पाद के प्रारंभिक सत्यापन और उसके बाद के क्षेत्र परीक्षणों के लिए रक्षा मंत्रालय के परीक्षण बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान की गई है।
ऑफसेट नीति से संबंधित सुधार	<ul style="list-style-type: none"> ऑफसेट, घरेलू उद्योग की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण तंत्र है। <ul style="list-style-type: none"> ऑफसेट, अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं से भारत द्वारा रक्षा उपकरणों की खरीद की स्थिति में उन पर आरोपित दायित्व को रेखांकित करता है। यह दायित्व भारत के घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित है। यह अत्याधुनिक हथियारों/प्लेटफार्मों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की प्राप्ति में मदद करता है, ताकि निर्यात के लिए इनका लाभ उठाया जा सके। ऑफसेट नीति से संबंधित सुधारों को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP)³⁹ 2020 के अंतर्गत शामिल किया गया है।
रक्षा-क्षेत्र का स्वदेशीकरण	<ul style="list-style-type: none"> रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP), 2020: पूंजीगत उपकरणों की खरीद के लिए 'खरीदें' {भारतीय-IDD (स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित)} श्रेणी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 के तहत रक्षा उद्योग के साथ दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना (15 वर्ष) और भविष्य की आवश्यकताओं को साझा करने के लिए प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और

³⁶ Directorate General of Foreign Trade³⁷ Department of Defence Productio³⁸ End User Certificat³⁹ Defence Acquisition Procedur

	<p>क्षमता रोडमैप (TPCR)⁴⁰ का प्रावधान किया गया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ इससे रक्षा उपकरण निर्माताओं को मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs)⁴¹ के साथ प्रौद्योगिकी समझौता संबंधी योजनाओं के निर्माण में, उत्पादन लाइनें स्थापित करने में या उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी। ● रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में स्वचालित मार्ग से 74% तक और सरकारी मार्ग द्वारा 100% तक वृद्धि की गई है। ● रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (IDEX) को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य MSMEs, स्टार्टअप्स आदि सहित संबंधित उद्योगों को शामिल करना है। ● दो रक्षा औद्योगिक गलियारों (उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में) की स्थापना की गई है।
<p>अन्य</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● रक्षा और अत्याधुनिक मर्दों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेश व्यापार नीति (2015) में विशेष प्रोत्साहन प्रस्तुत किए गए हैं। ● घरेलू उत्पादन और रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दो रक्षा औद्योगिक गलियारों के गठन का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

8.5. एकीकृत थिएटर कमान (Integrated Theatre Commands)

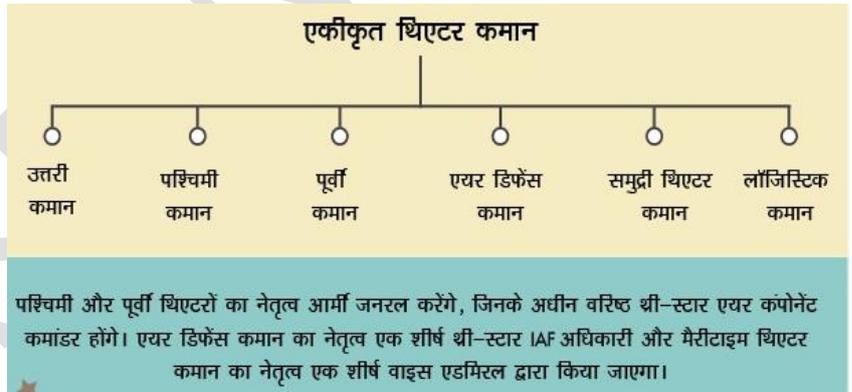
सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, एकीकृत थिएटर कमान के प्रस्तावित मॉडल से संबंधित मुद्दों के आलोक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।

एकीकृत थिएटर कमान के बारे में

- एकीकृत थिएटर कमान वस्तुतः सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों के लिए **एकल कमांडर के अधीन तीनों सेनाओं की एकीकृत कमान** की परिकल्पना को संदर्भित करती है।

- एकीकृत थिएटर कमान का कमांडर अपनी क्षमता के अधीन किसी भी विपरीत परिस्थिति में सरलता से तीनों सैन्य बलों (थल सेना, वायुसेना और नौसेना) से सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सक्षम होगा।



- एकीकृत थिएटर कमान के विचार को **कारगिल समीक्षा समिति और डी. बी. शेकटकर समिति** दोनों द्वारा प्रस्तावित किया गया है।
- वर्ष 2016 में **शेकटकर समिति** ने 3 एकीकृत थिएटर कमान की स्थापना की सिफारिश की थी:
 - चीनी सीमा के लिए उत्तरी कमान;
 - पाकिस्तानी सीमा के लिए पश्चिमी कमान; और
 - समुद्री सीमाओं के लिए दक्षिणी कमान।
- वर्तमान में जो थिएटर मॉडल विचाराधीन है, उसके तहत कम से कम **छह नए एकीकृत कमान** स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।
- इस थिएटर मॉडल में एक अंतर्निहित लचीलेपन का समावेश किया जाएगा, ताकि संक्रमण चरण के दौरान यदि कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है तो देश को किसी संकट में डाले बिना इसे वापस वर्तमान कमान और नियंत्रण संरचना में सरलता से तब्दील किया जा सके।
- भारत के **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ** को इस थिएटर मॉडल को मूर्त रूप देने हेतु अधिदेशित किया गया है। हालांकि, यह संभावना व्यक्त की गई कि तीनों सेवाओं के एकीकृत संचालन को वर्ष 2023 तक आरंभ कर लिया जाएगा।

⁴⁰ Technology Perspective and Capability Roadmap

⁴¹ Original Equipment Manufacturers

- CDS के बारे में
 - CDS सभी त्रि-सेवा मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
 - CDS की सेवानिवृत्ति की आयु से संबंधित प्रावधान, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG), मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) तथा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) की सेवानिवृत्ति की आयु से संबंधित उपबंधों के समान होते हैं।

8.6. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act: UAPA)

सुर्खियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA)⁴² के तहत न्यायाधीश जांच अवधि नहीं बढ़ा सकते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- न्यायालय ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि केवल विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA की धारा 43D) के तहत नामित एक विशेष न्यायालय ही आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए समय विस्तार के मुद्दे का निवारण करने हेतु अधिकृत होगा। अन्य न्यायाधीश समय विस्तार के ऐसे मामलों के निवारण के लिए प्राधिकृत नहीं हैं।
 - उच्चतम न्यायालय ने बिक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद, 2020 में भी ऐसा ही निर्णय दिया था।
 - विशेष न्यायालयों को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम⁴³ के तहत और ऐसे विशेष न्यायालयों की अनुपस्थिति में सत्र न्यायालयों के साथ स्थापित किया जाता है।

UAPA के बारे में

- UAPA भारत का प्रमुख आतंकवाद-रोधी कानून है। इसके अंतर्गत 90 दिनों के भीतर जांच प्रक्रिया पूर्ण किए जाने का प्रावधान किया गया है। यदि ऐसा करने में सफल नहीं हुए, तो आरोपी, चूक जमानत (default bail) का पात्र हो जाता है।
- UAPA, 1967 के प्रमुख प्रावधान (वर्ष 2019 में संशोधित)
 - केंद्र किसी संगठन या व्यक्ति को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकता है।
 - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के महानिदेशक को संपत्ति की जब्ती या कुर्की की स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान करता है।
 - आतंकवाद के मामलों की जांच के लिए NIA के इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को अधिकार प्रदान करता है।
- UAPA के तहत दोषसिद्धि की दर अत्यंत कम है। वर्ष 2016 और वर्ष 2019 के मध्य UAPA के तहत दर्ज किए गए मामलों में से केवल 2.2% मामलों में ही अभियुक्तों को न्यायालयों द्वारा दोष सिद्ध घोषित किया गया था।

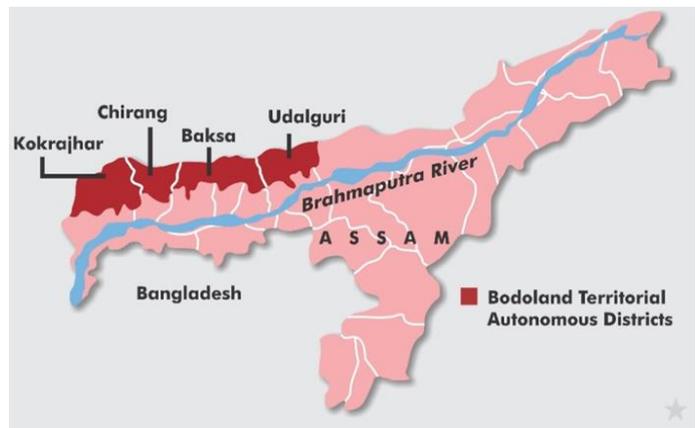
8.7. पूर्वोत्तर क्षेत्र (North East Region)

8.7.1. तीसरा बोडो शांति समझौता (3rd Bodo Peace Accord)

सुर्खियों में क्यों?

असम सरकार ने बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) के तीव्रता से विकास के लिए बोडोलैंड विभाग की स्थापना की है। यह तीसरे बोडो शांति समझौते के भाग के रूप में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR)⁴⁴ के चार जिलों (कोकराझार, बक्सा, चिरांग और उदलगुडी) के मुद्दों से निपटेगा।

- तीसरा बोडो शांति समझौता केंद्र सरकार, असम सरकार और असम के प्रतिबंधित विद्रोही समूह नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) के मध्य 2020 में हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौता था।
 - इसके तहत बोडो प्रादेशिक क्षेत्र जिला (BTAD) का



⁴² Unlawful Activities Prevention Act

⁴³ National Investigation Agency Act

⁴⁴ Bodoland Territorial Region

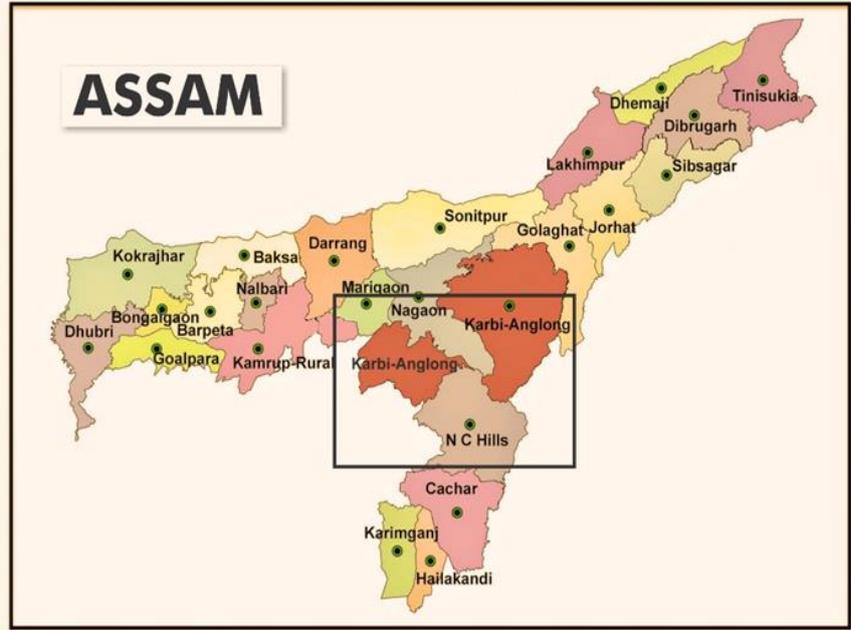
नाम परिवर्तित कर **BTR** कर दिया गया था। साथ ही, **BTR** को अधिक कार्यकारी, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई थीं।

- BTAD का प्रशासन **बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (BTC)** द्वारा किया जाता था। यह भारत के संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान के तहत कार्य करती है।
- हालांकि, समझौते में यह भी उपबंधित किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा **BTR** के सीमांकन और पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि बोडोलैंड एक परिकल्पित राज्य है, जिसकी मांग असम के बोडो नामक जनजातीय समुदाय द्वारा की जा रही है। इसमें राज्य की आबादी का 5 से 6 प्रतिशत भाग शामिल होगा।

संबंधित सुर्खियाँ

कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में अशांति को समाप्त करने के लिए त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं

- कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में वर्षों से जारी हिंसा को समाप्त करने के लिए असम के पांच विद्रोही समूहों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
 - कार्बी आंगलोंग और उत्तरी कछार पहाड़ियों को शामिल करते हुए एक पृथक राज्य हेतु कार्बी विद्रोह उन कई विद्रोहों में से एक है, जिनका असम द्वारा वर्षों से सामना किया जा रहा है। इस विद्रोह के अतिरिक्त बोडोलैंड आंदोलन और असम की संप्रभुता के लिए यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा/ULFA) के नेतृत्व में संचालित एक आंदोलन असम राज्य द्वारा सामना किए जा रहे प्रमुख विद्रोह हैं।
- कार्बी आंगलोंग:
 - यह असम का सबसे बड़ा जिला है। इसमें विभिन्न जनजातीय और नृजातीय समूह जैसे कार्बी, बोडो, कुकी, दिमासा आदि अधिवासित हैं।
 - कार्बी नस्लीय रूप से मंगोलाइड समूह से संबंधित हैं और भाषाई रूप से तिब्बती-बर्मी समूह से संबंधित हैं।
 - यह भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत गठित एक स्वायत्त जिला है। वर्ष 1995 में, इसे कार्बी आंगलोंग जिला परिषद (KADC) से कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) में क्रमोन्नत किया गया था।



8.8. द्वीपसमूह में विकासात्मक रणनीति (Island Developmental Strategy)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में कुछ विकासात्मक परिवर्तनों का विरोध देखने को मिला।

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल ही में, लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा निम्नलिखित तीन विधान प्रस्तुत किए गए हैं:

विनियमन	प्रमुख उपबंध
लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन, 2021 (The Lakshadweep Animal Preservation Regulation, 2021)	<ul style="list-style-type: none"> ● इस विनियमन में प्रावधान किया गया है कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र के बिना कोई व्यक्ति, न तो किसी पशु का वध करेगा या न ही किसी अन्य व्यक्ति से पशु का वध करवाएगा। ● इस विनियमन में यह उल्लिखित है कि यह दुधारू, प्रजनन या कृषि प्रयोजनों के लिए उपयुक्त पशुओं के संरक्षण का प्रावधान करता है। इस उद्देश्य के लिए द्वीप में गाय,

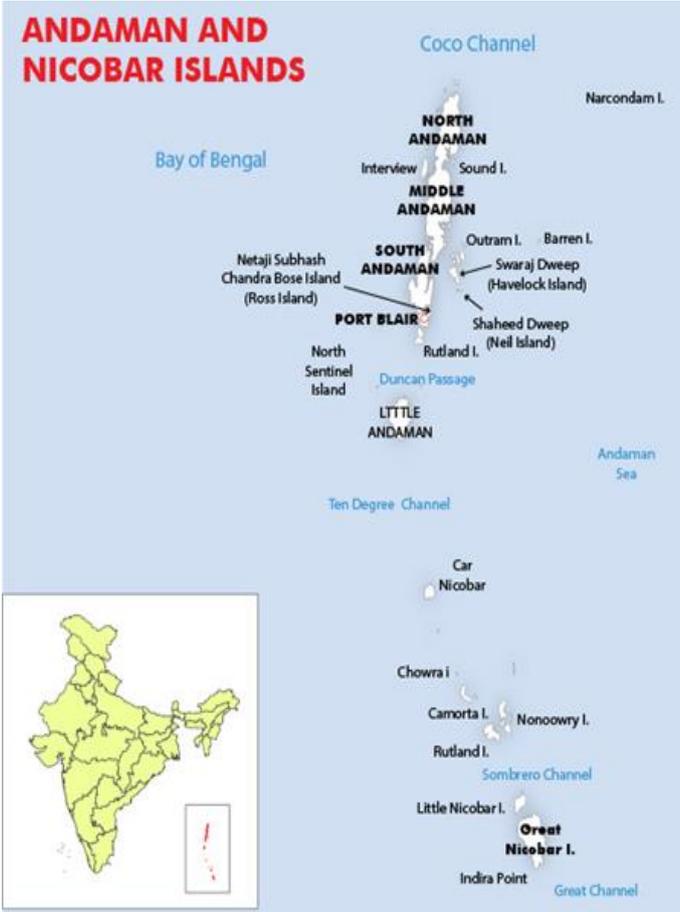
	बछड़े, सांड या वृषभ (बैल) का वध करने का कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाएगा।
लक्षद्वीप पंचायत विनियमन, 2021 (The Lakshadweep Panchayat Regulation, 2021)	<ul style="list-style-type: none"> इसके तहत एक नवीन पंचायत विनियमन प्रस्तावित किया गया, जो दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी व्यक्ति को पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के रूप में या पंचायत सदस्य बने रहने के लिए निरर्ह घोषित करता है।
लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन, 2021 (The Lakshadweep Development Authority Regulation, 2021)	<ul style="list-style-type: none"> यह विनियमन सरकार को विकास संबंधी उद्देश्यों के लिए द्वीप में किसी भी आम व्यक्ति के स्वामित्व वाली किसी भी भूमि से उसे निष्कापित करने, उसके स्वामित्व में परिवर्तन करने और/या अधिग्रहण करने की अनुमति देता है।
लक्षद्वीप असामाजिक क्रियाकलाप निवारण विनियमन (The Lakshadweep Prevention of Anti-Social Activities Regulation)	<ul style="list-style-type: none"> इस विनियमन में यह उपबंध है कि यदि किसी दोषी व्यक्ति के कृत्यों से लोक व्यवस्था को बनाए रखना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, तो प्रशासक द्वारा उक्त व्यक्ति को एक वर्ष तक की अवधि के लिए हिरासत में रखने संबंधी आदेश जारी किया जा सकता है।

- स्थानीय स्तर पर इन विधानों का अत्यधिक विरोध हो रहा है।
- सभी हितधारकों की विकासात्मक आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए नीति आयोग द्वारा सुझाए गए 'संधारणीय विकास के पंचतंत्र सिद्धांतों'⁴⁵ को अपनाया जा सकता है। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

सतत विकास के लिए पंचतंत्र सिद्धांत



⁴⁵ Panchatantra Principles of Sustainable Development



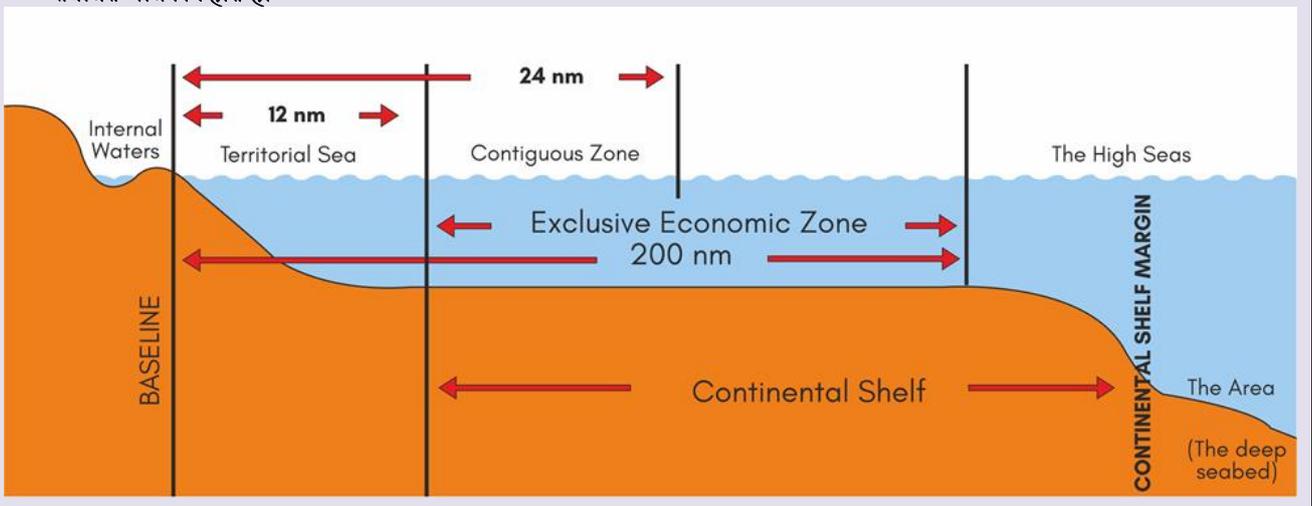
संबंधित तथ्य

द्वीप विकास एजेंसी (Island Development Agency: IDA)

- द्वीपों के समग्र विकास के लिए जून 2017 में IDA का गठन किया गया था।
- इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है और इसमें विभिन्न मंत्रालयों के सचिव सम्मिलित होते हैं।

अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone: EEZ)

- समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS) द्वारा EEZ को सामान्य तौर पर तटरेखा से 200 नॉटीकल मील की दूरी तक विस्तृत क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। इस क्षेत्र में संबंधित तटीय देश के पास प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण, दोहन, संरक्षण एवं प्रबंधन तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों जैसे कि पवन या ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन करने से संबंधित अधिकार होते हैं।





8.9. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ (Other Important News)

<p>ऑक्स (AUKUS)</p>	<p>ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम तथा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑक्स (AUKUS) नामक एक नए त्रिपक्षीय कार्यक्रम की घोषणा की है।</p> <p>ऑक्स के बारे में</p> <ul style="list-style-type: none"> ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित ऑक्स, एक नया सुरक्षा गठबंधन है। इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और गठबंधन में शामिल देशों के मध्य रक्षा क्षमताओं को अधिक से अधिक साझा करना है। इसके तहत अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा ऑस्ट्रेलिया को अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी सुविधा उपलब्ध प्रदान कराने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम तकनीक जैसी भविष्य की क्षमताएं शामिल हैं। इस समझौते के हिस्से के रूप में, ऑस्ट्रेलिया फ्रांसीसी पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की अपनी 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना का परित्याग कर देगा। इसके स्थान पर वह यूनाइटेड किंगडम-संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित तकनीकों के आधार पर पोतों को निर्मित करेगा।
<p>ड्रग ट्रेफिकिंग पर संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) की रिपोर्ट</p>	<p>UNODC की एक रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान में अफीम के उत्पादन में लगातार पांचवें वर्ष भी वृद्धि दर्ज की गई</p> <ul style="list-style-type: none"> उपर्युक्त निष्कर्ष UNODC की एक रिपोर्ट का हिस्सा है। इस रिपोर्ट को पेरिस समझौता पहल (Paris Pact Initiative: PPI) की बैठक में लॉन्च किया गया था। <ul style="list-style-type: none"> PPI एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। भारत भी इसका एक हिस्सा है। इसे अफगानिस्तान में उत्पादित होने वाले अफीम की अवैध तस्करी से निपटने के लिए वर्ष 2003 में लॉन्च किया गया था। <p>इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र</p> <ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2021 में अफगानिस्तान में अफीम की फसल में 8% की वृद्धि हुई है और कुल 6,800 टन अफीम का उत्पादन हुआ है। वर्ष 2020 में वैश्विक अफीम उत्पादन का 85% हिस्सा अफगान अफीम का था। यह अफीम विश्व भर में 10 में से 8 (80%) अफीम उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति की जाती है। अपने चरम पर पहुँच कर स्थिर हो चुके अफीम के बाजार और मेथमफेटामाइन की उच्च क्षेत्रीय एवं वैश्विक मांग के कारण अफगानिस्तान में मेथमफेटामाइन का उत्पादन बढ़ रहा है। <p>भारत पर प्रभाव</p> <ul style="list-style-type: none"> UNODC की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 45 प्रतिशत हेरोइन अफगानिस्तान से आती है। हाल ही में, कम लागत वाली सिंथेटिक मेथमफेटामाइन, भारत में बड़ी संख्या में युवा उपयोगकर्ताओं को आकर्षित कर रही है। दक्षिणी अवैध व्यापार मार्ग के प्रति सुभेद्यता।
<p>दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता (Delhi Regional Security Dialogue)</p>	<ul style="list-style-type: none"> तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान में समग्र सुरक्षा स्थिति पर परिचर्चा हेतु भारत क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी करेगा। हालांकि, इस संस्करण की दो बैठकें पहले ही वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में ईरान में आयोजित की जा चुकी हैं। यह पहली बार है जब न केवल अफगानिस्तान के निकट पड़ोसी बल्कि सभी मध्य एशियाई देश भी इस वार्ता में भाग ले रहे हैं। अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में रूस, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों द्वारा दिल्ली घोषणापत्र को अपनाया गया है। निम्नलिखित मुद्दों पर सहमति बनी: <ul style="list-style-type: none"> शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान के लिए मजबूत समर्थन पर बल दिया गया। क्षेत्र में कट्टरता, उग्रवाद, अलगाववाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे के विरुद्ध सामूहिक सहयोग का आह्वान किया गया। <p>अफगानिस्तान को अबाध, प्रत्यक्ष और सुनिश्चित तरीके से मानवीय सहायता प्रदान किए जाने पर बल दिया गया।</p>



<p>राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (National Maritime Security Coordinator: NMSC)</p>	<p>केंद्र सरकार ने NMSC की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की है</p> <ul style="list-style-type: none"> इसकी सिफारिश कारगिल समीक्षा समिति द्वारा की गई थी। NMSC के बारे में: <ul style="list-style-type: none"> यह असैन्य और सैन्य समुद्री प्रक्षेत्रों के मध्य इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के अधीन कार्य करेगा। यह समुद्री सुरक्षा प्रक्षेत्र पर सरकार का प्रमुख परामर्शदाता होगा। NMSC का महत्व: <ul style="list-style-type: none"> दक्षता में सुधार: चूंकि नौसेना, तटरक्षक बल और राज्य समुद्री बोर्ड सभी अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र के साथ, बिना किसी सहयोग के कार्य करते हैं तथा उनमें लगातार एक-दूसरे के साथ समन्वय का अभाव भी रहता है। समुद्री और ऊर्जा सुरक्षा: ज्ञातव्य है कि चीन भारतीय समुद्री क्षेत्र के माध्यम से अफ्रीका के पूर्वी समुद्री तट तक पहुंचने की योजना निर्मित कर रहा है। NMSC का निर्माण एक्ट ईस्ट पॉलिसी विजन का भाग है, जिसमें क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास (SAGAR/सागर)⁴⁶, डीप ओशन मिशन तथा सागरमाला परियोजना भी शामिल हैं। 												
<p>वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए सिद्धांत (Principles for Global Maritime Security)</p>	<p>UNSC की परिचर्चा में, प्रधान मंत्री ने वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए 5 सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया है यह भारत द्वारा कार्यान्वित पहल, सागर (SAGAR) के अनुरूप है।</p> <table border="1" data-bbox="432 840 1468 1753"> <thead> <tr> <th>पांच सिद्धांत</th> <th>तर्काधार</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>वैश्व समुद्री व्यापार के लिए बाधाओं का निवारण करना</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> महासागर विश्व की साझी विरासत हैं तथा आधुनिक समुद्री मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखाएं हैं। </td> </tr> <tr> <td>समुद्री विवादों का शांतिपूर्ण तरीकों से और अंतर्राष्ट्रीय विधियों के आधार पर समाधान करना</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रों को समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) के आधार पर समुद्री विवादों का निपटान करना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत ने इसके आधार पर ही बांग्लादेश के साथ अपने विवादों का समाधान किया है। </td> </tr> <tr> <td>प्राकृतिक आपदाओं व गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा उत्पन्न सामुद्रिक खतरों का संयुक्त होकर सामना करना</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> वैश्विक स्तर पर, समुद्री यातायात की मात्रा में गिरावट के बावजूद, वर्ष 2020 की प्रथम छमाही के दौरान समुद्री जलदस्युता और सशस्त्र डकैती के कृत्यों में 20% की वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय⁴⁷ (2000) को लागू करने की आवश्यकता है। </td> </tr> <tr> <td>समुद्री पर्यावरण एवं संसाधनों का संरक्षण</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> महासागर, तटीय क्षेत्रों में अधिवासित निर्धन समुदायों की न केवल आजीविका अपितु उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। </td> </tr> <tr> <td>उत्तरदायी समुद्री संपर्क को प्रोत्साहित करना</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> वर्तमान में, हमारे पास इसके लिए इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिन्क्रोरीटी (ISPS) कोड उपलब्ध है। </td> </tr> </tbody> </table>	पांच सिद्धांत	तर्काधार	वैश्व समुद्री व्यापार के लिए बाधाओं का निवारण करना	<ul style="list-style-type: none"> महासागर विश्व की साझी विरासत हैं तथा आधुनिक समुद्री मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखाएं हैं। 	समुद्री विवादों का शांतिपूर्ण तरीकों से और अंतर्राष्ट्रीय विधियों के आधार पर समाधान करना	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रों को समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) के आधार पर समुद्री विवादों का निपटान करना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत ने इसके आधार पर ही बांग्लादेश के साथ अपने विवादों का समाधान किया है। 	प्राकृतिक आपदाओं व गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा उत्पन्न सामुद्रिक खतरों का संयुक्त होकर सामना करना	<ul style="list-style-type: none"> वैश्विक स्तर पर, समुद्री यातायात की मात्रा में गिरावट के बावजूद, वर्ष 2020 की प्रथम छमाही के दौरान समुद्री जलदस्युता और सशस्त्र डकैती के कृत्यों में 20% की वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय⁴⁷ (2000) को लागू करने की आवश्यकता है। 	समुद्री पर्यावरण एवं संसाधनों का संरक्षण	<ul style="list-style-type: none"> महासागर, तटीय क्षेत्रों में अधिवासित निर्धन समुदायों की न केवल आजीविका अपितु उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। 	उत्तरदायी समुद्री संपर्क को प्रोत्साहित करना	<ul style="list-style-type: none"> वर्तमान में, हमारे पास इसके लिए इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिन्क्रोरीटी (ISPS) कोड उपलब्ध है।
पांच सिद्धांत	तर्काधार												
वैश्व समुद्री व्यापार के लिए बाधाओं का निवारण करना	<ul style="list-style-type: none"> महासागर विश्व की साझी विरासत हैं तथा आधुनिक समुद्री मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखाएं हैं। 												
समुद्री विवादों का शांतिपूर्ण तरीकों से और अंतर्राष्ट्रीय विधियों के आधार पर समाधान करना	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रों को समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) के आधार पर समुद्री विवादों का निपटान करना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत ने इसके आधार पर ही बांग्लादेश के साथ अपने विवादों का समाधान किया है। 												
प्राकृतिक आपदाओं व गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा उत्पन्न सामुद्रिक खतरों का संयुक्त होकर सामना करना	<ul style="list-style-type: none"> वैश्विक स्तर पर, समुद्री यातायात की मात्रा में गिरावट के बावजूद, वर्ष 2020 की प्रथम छमाही के दौरान समुद्री जलदस्युता और सशस्त्र डकैती के कृत्यों में 20% की वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय⁴⁷ (2000) को लागू करने की आवश्यकता है। 												
समुद्री पर्यावरण एवं संसाधनों का संरक्षण	<ul style="list-style-type: none"> महासागर, तटीय क्षेत्रों में अधिवासित निर्धन समुदायों की न केवल आजीविका अपितु उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। 												
उत्तरदायी समुद्री संपर्क को प्रोत्साहित करना	<ul style="list-style-type: none"> वर्तमान में, हमारे पास इसके लिए इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिन्क्रोरीटी (ISPS) कोड उपलब्ध है। 												

⁴⁶ Security and Growth of All in the Regio

⁴⁷ United Nations Convention against Transnational Organized Crime



<p>वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (Air Defence Identification Zone: ADIZ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> चीनी विमानों ने ताइवान के ADIZ में प्रवेश किया। ADIZ के बारे में: <ul style="list-style-type: none"> यह भूमि या जल के ऊपर का हवाई क्षेत्र होता है, जो किसी राष्ट्र को अपने संप्रभु हवाई क्षेत्र में संभावित घुसपैठ का पता लगाने में मदद करने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली प्रदान करता है। यह देश के राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र की सीमा से परे विस्तृत होता है। ADIZs कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते नहीं होते हैं। साथ ही, विभिन्न राष्ट्रों के ADIZs एक दूसरे का अतिव्यापन कर सकते हैं। हालांकि, कोई देश बिना किसी सूचना के उसके ADIZ में प्रवेश करने वाले विमान पर हमला नहीं कर सकता है।
<p>वित्तीय कार्यवाही कार्य बल (Financial Action Task Force: FATF)</p>	<ul style="list-style-type: none"> पाकिस्तान को FATF की 'ग्रे लिस्ट' में बनाये रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त तुर्की, जॉर्डन और माली को भी 'ग्रे लिस्ट' में शामिल किया गया है। हालांकि, मॉरीशस और बोत्सवाना को इस सूची से हटा दिया गया है। ग्रे लिस्ट वस्तुतः मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों के वित्तपोषण को रोकने हेतु किसी देश की नीतियों में मौजूद रणनीतिक दोषों को प्रकट करती है। इससे किसी देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय सहायता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। वर्ष 1989 में स्थापित FATF एक अंतर-सरकारी निकाय है। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के समक्ष उत्पन्न अन्य खतरों से निपटने में सहयोग करना है। भारत FATF का एक सदस्य देश है।
<p>फाइव आईज (Five Eyes)</p>	<ul style="list-style-type: none"> हाल ही में 'फाइव आईज' के सुरक्षा अलर्ट के कारण न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान दौरा रद्द करना पड़ा है। फाइव आईज गठबंधन संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य एक खुफिया-साझाकरण व्यवस्था है। इसके अंतर्गत, इन पांच देशों की खुफिया एजेंसियां आपस में संकेत, सैन्य और मानवीय आसूचना साझा करती हैं।
<p>रक्षा सलाहकार परिषद (Defence Advisory Council: DAC)</p>	<ul style="list-style-type: none"> DAC ने रूस के साथ AK 203 राइफल्स के सौदे को मंजूरी दे दी है। <ul style="list-style-type: none"> पहली 20,000 राइफलों को रूस से आयात किया जाएगा। इसके बाद 6 लाख से अधिक राइफलों का निर्माण भारत में होगा। DAC रक्षा मंत्रालय का सर्वोच्च निर्णय निर्माता निकाय है। यह तीन सेवाओं (थल-सेना, नौसेना और वायुसेना) तथा भारतीय तटरक्षक बल के लिए नई नीतियों एवं पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेता है। <ul style="list-style-type: none"> रक्षा मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं।
<p>प्रोजेक्ट 75 (इंडिया) [पी-75(आई)] {Project 75 (India) [P-75(I)]}</p>	<ul style="list-style-type: none"> रक्षा मंत्रालय ने प्रथम पी-75(आई) सबमरीन टेंडर जारी किया। पी-75(आई) में फ्यूल-सेल आधारित वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली (AIP: Air Independent Propulsion Plant) सहित समकालीन उपकरण, हथियार और सेंसर के साथ छह आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। <ul style="list-style-type: none"> AIP तकनीक पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को अधिक समय तक जल के भीतर रहने में सक्षम बनाती है। इससे इनकी मारक क्षमता बढ़ जाती है। AIP प्रणाली धारक अन्य देशों में चीन, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन और रूस शामिल हैं। अनुमानित 5.5 बिलियन डॉलर से अधिक की पी-75(आई) पनडुब्बी परियोजना भारत द्वारा अपने रणनीतिक साझेदारी खरीद मॉडल के माध्यम से किया गया प्रथम अधिग्रहण है।
<p>आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board: OFB)</p>	<ul style="list-style-type: none"> रक्षा मंत्रालय ने OFB के विघटन (1 अक्टूबर से प्रभावी) का आदेश जारी किया है। यह कदम OFB को निगमित करने हेतु लंबे समय से प्रतीक्षा में रही सुधार योजना को कार्यान्वित करने के लिए उठाया जा रहा है। <ul style="list-style-type: none"> OFB के तहत 41 आयुध कारखानों की संपत्ति, कर्मचारियों और परिचालन को सार्वजनिक क्षेत्र की सात रक्षा इकाइयों को हस्तांतरित किया जाएगा। निगमीकरण का उद्देश्य दक्षता में सुधार लाना, उत्पादों को लागत-प्रतिस्पर्धी बनाना और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। OFB भूमि, समुद्र और वायु प्रणालियों के क्षेत्र में व्यापक उत्पाद शृंखला के उत्पादन, परीक्षण, लॉजिस्टिक्स, अनुसंधान, विकास एवं विपणन में संलग्न रहा है।



<p>कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC)</p>	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने पहली CSC वर्चुअल कार्यशाला आयोजित की है। इसका विषय "रक्षात्मक संचालन, डीप/ डार्क वेब हैंडलिंग और डिजिटल फोरेंसिक पर क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा क्षमताओं का विकास" है। CSC, को पहले समुद्री सुरक्षा पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) स्तर की त्रिपक्षीय बैठक (वर्ष 2011) कहा जाता था। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरीशस, मालदीव और सेशेल्स इसके सदस्य हैं। इसका सचिवालय कोलंबो में स्थित है। यह सदस्य देशों को अपने सहयोग के निम्नलिखित चार स्तंभों के माध्यम से साझे सुरक्षा खतरों पर प्रभावी ढंग से क्षमता निर्माण करने में मदद करता है: <ul style="list-style-type: none"> समुद्री सुरक्षा और संरक्षा, आतंकवाद एवं कट्टरता, तस्करी व संगठित अपराध तथा साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा। साइबर सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय स्तर पर की गई कुछ पहलों में प्रशांत साइबर सुरक्षा परिचालन नेटवर्क (PaCSON)⁴⁸, सिंगापुर-आसियान साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (ASCCE)⁴⁹, यक्ष (YAKSHA), EU-आसियान साझेदारी शामिल हैं।
<p>लॉग फॉर शेल (Log4Shell)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 'Log4Shell' को अब तक खोजी गई सबसे निम्नस्तरीय साइबर सुरक्षा त्रुटियों में से एक के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। इससे जुड़ी सुभेद्यता एक ओपन-सोर्स लॉगिंग लाइब्रेरी पर आधारित है। इसका उपयोग उद्यमों और यहां तक कि सरकारी एजेंसियों द्वारा अधिकांश एप्लीकेशन्स में किया जाता है। इस सुभेद्यता का उपयोग करके हैकर्स किसी एप्लीकेशन तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और संभावित रूप से किसी डिवाइस या सर्वर पर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का संचालन कर सकते हैं।
<p>रेविल (REvil)</p>	<ul style="list-style-type: none"> अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के अनुरोध पर रूसी अधिकारियों ने रैंसमवेयर समूह 'रेविल' को नष्ट कर दिया है। <ul style="list-style-type: none"> रेविल नाम "रैंसमवेयर" और "ईविल" का मिश्रण है। यह रूस स्थित एक हैकिंग संगठन है। रैंसमवेयर एक मैलवेयर (दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर वेरिएंट के लिए एक संयुक्त नाम) है। यह पीड़ित की जानकारी पर नियंत्रण रखने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। रेविल ग्रुप पहले कंप्यूटर से डेटा चोरी करता है। इसके बाद पीड़ित को उसके कंप्यूटर के उपयोग से वंचित कर देता है और फिर चोरी किए गए डेटा को नीलाम करके जारी करने की धमकी देता है।
<p>भारत में निगरानी से संबंधित कानून (Laws on Surveillance in India)</p>	<ul style="list-style-type: none"> भारत में मुख्य रूप से दो कानूनों के तहत संचार-साधनों पर निगरानी की जाती है: टेलीग्राफ अधिनियम, 1885; और सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) अधिनियम, 2000 इन दोनों कानूनों के तहत, केवल सरकार ही कुछ विशेष परिस्थितियों में निगरानी कर सकती है। निजी व्यक्तियों या संस्थाओं को इसकी अनुमति नहीं है। <ul style="list-style-type: none"> टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत सरकार केवल कुछ विशेष स्थितियों में ही कॉल को इंटरसेप्ट कर सकती है। इन विशेष स्थितियों में शामिल हैं: भारत की संप्रभुता और अखंडता, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, आदि। <ul style="list-style-type: none"> ये वही प्रतिबंध हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी आरोपित किए गए हैं। वर्ष 2009 में आई.टी. अधिनियम के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना के अवरोधन, निगरानी और डिक्लिप्शन के लिए प्रक्रियाएं एवं रक्षोपाय) नियम⁵⁰ बनाए गए थे। इन नियमों के अंतर्गत, केवल सक्षम प्राधिकारी ही इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है। <ul style="list-style-type: none"> सक्षम प्राधिकारी में शामिल हैं- केंद्रीय गृह सचिव और राज्यों में गृह विभाग के प्रभारी सचिव।
<p>पेगासस (Pegasus)</p>	<p>पेगासस स्पाइवेयर को लेकर हाल ही में हुए विवाद ने भारत में साइबर निगरानी से जुड़ी बहस को हवा दे दी है।</p> <ul style="list-style-type: none"> यह एक इज़रायली कंपनी NSO समूह द्वारा विकसित और लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर है।

⁴⁸ Pacific Cyber Security Operational Network

⁴⁹ Singapore-ASEAN Cybersecurity Centre of Excellence

⁵⁰ IT (Procedures and Safeguards for Interception, Monitoring and Decryption of Information) Rules



<p>प्रादेशिक सेना (Territorial Army: TA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 09 अक्टूबर 2021 को TA का 72वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसे वर्ष 1920 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। हालांकि, स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1948 में प्रादेशिक सेना अधिनियम पारित कर TA को औपचारिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया था। वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर लगभग 50,000 हो गई है। यह नियमित सेना (Regular Army: RA) का एक भाग है और इसकी वर्तमान भूमिकाओं के अंतर्गत शामिल हैं: <ul style="list-style-type: none"> RA को स्थायी दायित्वों के निर्वहन से मुक्त करना। यह प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में नागरिक प्रशासन की सहायता करती है। उन स्थितियों में आवश्यक सेवाओं के प्रबंधन को सुनिश्चित करती है, जिनमें समुदायों का जीवन प्रभावित हो रहा है या देश की सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न हो रहा है। यह आवश्यकता पड़ने पर RA के लिए यूनिट्स उपलब्ध करवाती है।
<p>सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force: BSF)</p>	<ul style="list-style-type: none"> हाल ही में, सरकार ने बी.एस.एफ. को सशक्त बनाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में बी.एस.एफ. को दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) तथा पासपोर्ट अधिनियम और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम के तहत भारत-पाकिस्तान व भारत-बांग्लादेश सीमाओं से 50 किमी तक के क्षेत्र में तलाशी लेने, संदिग्धों को गिरफ्तार करने और सामग्रियों को जब्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। <ul style="list-style-type: none"> बी.एस.एफ. को वर्ष 1965 में पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान) और पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के साथ संलग्न भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था। साथ ही, इन्हें आतंकवाद रोधी और अन्य आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कर्तव्यों के निर्वहन हेतु भी तैनात किया जाता है। बी.एस.एफ. का संचालन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
<p>राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps: NCC)</p>	<ul style="list-style-type: none"> रक्षा मंत्रालय (MoD) ने NCC की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, ताकि इसे बदलते समय में और अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके। NCC एक युवा विकास आंदोलन है, जो वर्ष 1948 में अस्तित्व में आया था। <ul style="list-style-type: none"> NCC का उद्देश्य युवा नागरिकों में चरित्र, साहचर्य, अनुशासन, एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहस की भावना और निःस्वार्थ सेवा के आदर्शों का विकास करना है। विद्यालयों और महाविद्यालयों के सभी नियमित छात्र NCC में स्वैच्छिक रूप से शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर NCC को रक्षा मंत्रालय द्वारा और सभी राज्यों में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
<p>डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज 5.0 (Defence India Startup Challenge 5.0)</p>	<ul style="list-style-type: none"> इसे रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार-रक्षा नवाचार संगठन (iDEX-DIO)⁵¹ के अंतर्गत आरंभ किया गया है। iDEX का उद्देश्य रक्षा व एयरोस्पेस में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा नवाचार और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs), स्टार्ट-अप्स, व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों, अनुसंधान एवं विकास (R&D) संस्थानों और शिक्षाविदों सहित उद्योगों को शामिल किया जाता है। <ul style="list-style-type: none"> DIO एक "गैर-लाभकारी" कंपनी है, जो iDEX ढांचे को संचालित करती है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा iDEX नेटवर्क की स्थापना और प्रबंधन के लिए DIO को वित्त उपलब्ध कराया जाएगा।
<p>मंथन 2021 हैकाथॉन (MANTHAN Hackathon) 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> यह एक विशेष राष्ट्रीय पहल है। यह देश की खुफिया एजेंसियों द्वारा सामना की जाने वाली 21वीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों के समाधान हेतु नवीन अवधारणाओं को विकसित करने और प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करने में मदद करती है। <ul style="list-style-type: none"> इस 21वीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों में जाली सामग्री पहचान, भविष्य सूचक साइबर अपराध डेटा विश्लेषण आदि शामिल हैं। इसे शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के समन्वय में गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) द्वारा आयोजित किया गया है।

⁵¹ Innovations for Defence Excellence - Defence Innovation Organisation

<p>व्हाइट शिपिंग सूचना विनिमय (White shipping information exchange)</p>	<ul style="list-style-type: none"> हाल ही में इस विनिमय समझौते पर भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी ने हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट शिपिंग सूचना वस्तुतः वाणिज्यिक गैर-सैन्य व्यापारिक पोतों की पहचान और आवाजाही पर प्रासंगिक अग्रिम सूचनाओं के आदान-प्रदान में सहयोग करती है। <ul style="list-style-type: none"> इसके तहत जलयुक्त पोतों को व्हाइट (वाणिज्यिक जहाज), ग्रे (सैन्य जहाज) और ब्लैक (अवैध/अनधिकृत जहाज) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह समुद्री क्षेत्रों से जुड़े संभावित खतरों को देश की तटीय और अपतटीय सुरक्षा को प्रभावित करने से रोकने में मदद करती है। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर और फ्रांस सहित कई देशों के साथ व्हाइट शिपिंग समझौते संपन्न किए हैं।
<p>ऑपरेशन सद्भावना {Operation Sadbhavana (Goodwill)}</p>	<ul style="list-style-type: none"> हाल ही में, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के भाग के रूप में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के 110 छात्रों के लिए अपने आवासीय स्कूलों व उच्च शिक्षा संस्थानों में उच्चतर शिक्षा प्रायोजित करने का निर्णय लिया है। ऑपरेशन सद्भावना के बारे में: <ul style="list-style-type: none"> इसे वर्ष 1998 में सेना द्वारा आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य उपर्युक्त दो संघ राज्य क्षेत्रों के निवासियों के हृदय में विश्वास सृजित करना है। ज्ञातव्य है कि यह आतंकवाद के संकट से प्रभावित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु एक अनूठी मानवीय पहल है। यह पहल शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि जैसे सामाजिक क्षेत्रों में नागरिक प्रशासन के साथ सेना की सक्रिय भागीदारी को प्रेरित करती है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

प्रारंभिक

✓ सामान्य अध्ययन ✓ सीसैट

for **PRELIMS 2022: 16 Apr** प्रारंभिक 2022 के लिए **16 अप्रैल**

PRELIMS 2023 starting from 17 Apr

मुख्य

✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र

for **MAINS 2022: 2 Apr** मुख्य 2022 के लिए **2 अप्रैल**

for **MAINS 2023 starting from 17 Apr**

Scan the QR CODE to download **VISION IAS** app

9. विविध (Miscellaneous)

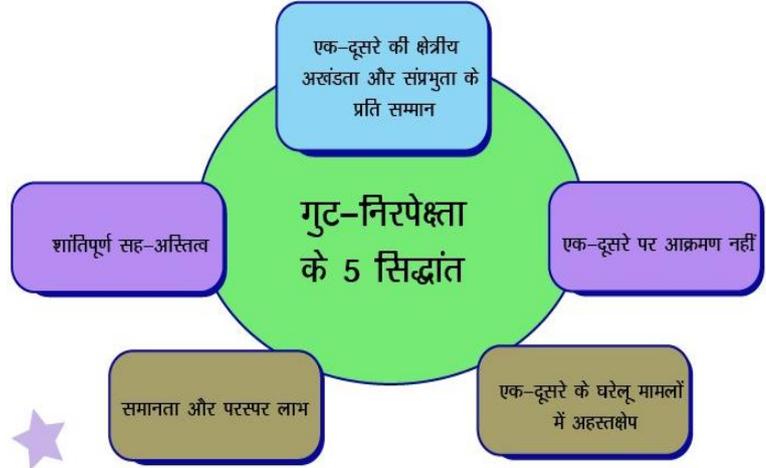
9.1. गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के 60 वर्ष पूरे हुए।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में

- NAM का गठन अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तथा शीत युद्ध के चरम दौर में हुआ था।
 - इसके गठन के पीछे मूल विचार यह था कि दो नवगठित सैन्य गुटों (नाटो और वारसाँ संधि) से स्वयं को "गुटनिरपेक्ष" घोषित किया जाए।
 - इस प्रक्रिया में **मिस्र, घाना, भारत, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया** के तत्कालीन सरकार प्रमुखों द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, जो बाद में इस आंदोलन के संस्थापक बने।



- उत्पत्ति: वर्ष 1955 में बांडुंग (इंडोनेशिया) में आयोजित एशिया-अफ्रीका सम्मेलन के दौरान।
- इस सम्मेलन के दौरान घोषित "बांडुंग के दस सिद्धांतों" को बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुख्य लक्ष्यों के रूप में अपनाया गया था।
- **NAM का पहला सम्मेलन: बेलग्रेड सम्मेलन वर्ष 1961 में भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना और इंडोनेशिया के नेतृत्व में आयोजित किया गया था।**
- NAM की नीति पंचशील के 5 सिद्धांतों पर आधारित है।
- ज्ञातव्य है कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात्, आंदोलन की प्रासंगिकता का लोप होने लगा था। किंतु **हवाना शिखर सम्मेलन (2006)** के दौरान, सदस्य देशों ने उन आदर्शों, सिद्धांतों और उद्देश्यों (संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनर्पुष्टि की, जिनके आधार पर आंदोलन की स्थापना हुई थी।
- इसके **120 सदस्य** हैं जिनमें अफ्रीका से 53 देश, एशिया से 39, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से 26 और यूरोप (बेलारूस, अजरबैजान) से 2 देश शामिल हैं।
- 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन NAM में पर्यवेक्षक हैं।

NON-ALIGNED MOVEMENT (NAM) MEMBERS



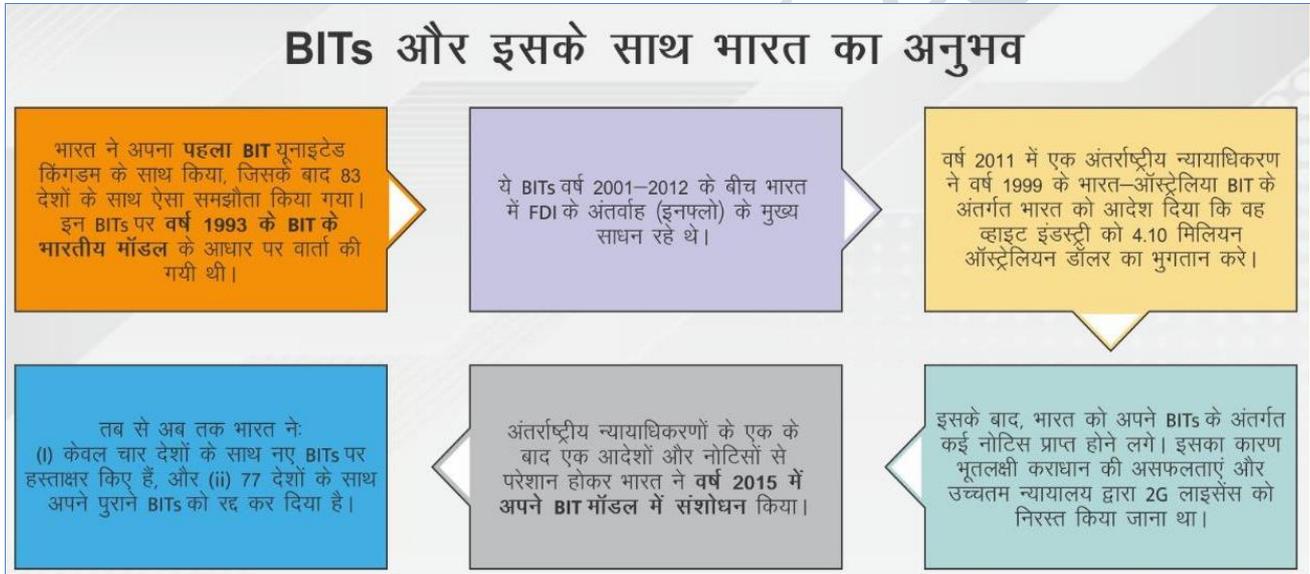
9.2. द्विपक्षीय निवेश संधियां (Bilateral Investment Treaties: BITs)

सुखियों में क्यों?

हाल ही में, विदेश मामलों की स्थायी समिति ने 'भारत और द्विपक्षीय निवेश संधियों' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

द्विपक्षीय निवेश संधियों (BITs) के बारे में

- BITs अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जो एक देश के नागरिकों एवं कंपनियों द्वारा दूसरे देश में निजी निवेश हेतु नियम एवं शर्तें निर्धारित करते हैं ताकि एक-दूसरे के राज्यक्षेत्रों में विदेशी निजी निवेश को प्रोत्साहित एवं संरक्षित किया जा सके।
- BITs विदेशी निवेश के प्रति व्यवहार/नीतियों के संबंध में दोनों देशों के बीच न्यूनतम गारंटी की सुविधा प्रदान करती हैं, जैसे कि:
 - राष्ट्रीय नीति (विदेशी निवेशकों के साथ घरेलू कंपनियों के समान व्यवहार करना),
 - निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार (अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार),
 - स्वामित्वहरण से सुरक्षा (अपने राज्यक्षेत्र में विदेशी निवेश का अधिग्रहण करने की प्रत्येक देश की क्षमता को सीमित करना)।
 - निवेशकों के अधिकारों का संरक्षण {एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की स्थापना करना, जिसके माध्यम से कोई निवेशक मेजबान राज्य पर उस मेजबान राज्य के ही न्यायालयों में मुकदमा करने के बजाय निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID)⁵² से संपर्क कर सके}।
- वर्तमान में, विश्व में 2,500 से अधिक BITs सक्रिय हैं और व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) इन सभी राज्यों के बीच सभी BITs का एक डेटाबेस रखता है।



9.3. ऋण जाल कूटनीति (Debt Trap Diplomacy)

सुखियों में क्यों?

दक्षिण-पूर्वी यूरोपीय देश **मोंटेनेग्रो** राजमार्ग परियोजना के निर्माण के उद्देश्य से चीन से लिए गए ऋण के भुगतान हेतु संघर्षरत है तथा इस ऋण भुगतान के संघर्ष ने देश में एक गंभीर वित्तीय अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्ष 2018 में, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट में उन आठ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) भागीदार देशों को रेखांकित किया गया है, जो BRI ऋण के कारण ऋण संकट के उच्च जोखिम से ग्रसित हैं। इन देशों में **जिबूती, लाओस, मालदीव, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, पाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान** शामिल हैं।
 - ये देश 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धिमान ऋण-GDP अनुपात की ओर अग्रसर हैं तथा उनके विदेशी ऋण में चीन की लगभग 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

⁵² International Centre for Settlement of Investment Disputes

CHINA'S INITIATIVE



ऋण जाल कूटनीति (Debt Trap Diplomacy) के बारे में

- वर्ष 2017 में इस पद को भारतीय भू-रणनीतिकार ब्रह्म चेलानी द्वारा परिकल्पित किया गया था।

ऋण जाल कूटनीति का निर्माण



अवसंरचना वित्तपोषण के लिए अन्य वैश्विक पहलें

- ब्लू डॉट नेटवर्क:** यह पहल संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस. इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनंस कॉरपोरेशन), जापान (जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन) और ऑस्ट्रेलिया (डिपार्टमेंट ऑफ़ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड) के वित्तीय संस्थानों को शामिल करते हुए आरंभ की गई है। यह नेटवर्क एक प्रमाणन निकाय के रूप में कार्य करेगा। साथ ही, यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अवसंरचना निर्माण परियोजनाओं के मूल्यांकन में भी मदद करेगा।
- आपदा प्रत्यास्थ अवसंरचना के लिए गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure: CDRI):** यह राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों एवं वित्तपोषण तंत्रों, निजी क्षेत्र तथा ज्ञान संस्थानों की संयुक्त भागीदारी में संचालित एक साझेदारी है। इसका उद्देश्य सतत विकास को बनाए रखने के क्रम में जलवायु और आपदा जोखिमों के विरुद्ध नई एवं मौजूदा अवसंरचना प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना है।

- एशिया-अफ्रीका विकास गलियारा (Asia-Africa Growth Corridor: AAGC): यह गलियारा भारत और जापान के मध्य संपन्न एक आर्थिक साझेदारी समझौता है। इसका उद्देश्य अफ्रीका में भारत-जापान सहयोग से अवसंरचना और डिजिटल कनेक्टिविटी (संपर्क) में सुधार करना है।
- यूरोपीय संघ की नई कनेक्टिविटी रणनीति: सितंबर 2018 में, यूरोपीय संघ ने 'कनेक्टिंग यूरोप एंड एशिया - बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एन ई.यू. स्ट्रेटेजी' पर एक संयुक्त पत्र व्यवहार को अंगीकृत किया था। यह रणनीति एक संधारणीय, व्यापक और नियम-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से मौजूदा एवं नियोजित यूरोपीय संघ नेटवर्क के उपयोग पर बल देती है, ताकि यूरोपीय संघ अपने एशियाई भागीदारों के साथ संपर्क को सुनिश्चित कर सके।
- ट्रांस-यूरोपीय परिवहन नेटवर्क (Trans-European Transport Network: TEN-T) नीति: इस नीति के तहत रेलवे लाइनों, सड़कों, अंतर्देशीय जलमार्गों, समुद्री नौवहन मार्गों, बंदरगाहों, विमान पत्तनों और रेलमार्ग टर्मिनलों के यूरोप-व्यापी नेटवर्क के कार्यान्वयन एवं विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- वैश्विक अवसंरचना सुविधा (Global Infrastructure Facility: GIF): यह G20 देशों द्वारा संचालित एक पहल है। यह विकासशील देशों और उभरते बाजारों की संधारणीय व गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं में निजी निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों को एकीकृत करने वाला एक वैश्विक सहयोग मंच है।

9.4. भारत का असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग (India's Civil Nuclear Energy Cooperation)

सुब्रियो में क्यों?

हाल ही में, रूस की प्रमुख परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसाटॉम ने भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE)⁵³ के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) के सहयोग से कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (NPP) की 5वीं इकाई का निर्माण आरंभ किया है।

भारत की परमाणु ऊर्जा संरचना के बारे में

- वर्तमान में, भारत के 14 देशों के साथ असैन्य परमाणु समझौते हैं। इनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जापान, कज़ाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, रूस, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम शामिल हैं।
- ये समझौते, भारत के परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty) के हस्ताक्षरकर्ता नहीं होने और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के दायरे से बाहर कार्य करने के बावजूद संपन्न हुए हैं।
- इन समझौतों का एक केंद्रीय सिद्धांत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसमें अनुसंधान, विद्युत उत्पादन, चिकित्सा तथा कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में सूचना, नाभिकीय पदार्थ, उपकरण या घटकों का उपयोग शामिल है।

भारत के प्रमुख असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग कार्यक्रम

भारत-फ्रांस



- 1950 के दशक से ही दोनों देशों के मध्य सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है क्योंकि फ्रांस ने वर्ष 1950 में असैन्य परमाणु नवाचार पर भारत को तकनीकी सहयोग का प्रस्ताव रखा था।
- भारत द्वारा वर्ष 1974 में किए गए शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण के बाद, फ्रांस इस प्रयास की सहायता करने वाला एकमात्र पश्चिमी देश था। फ्रांस ने इसे परमाणु क्षेत्र में भारत की प्रगति के प्रतिबिंब के रूप में उल्लेख किया।
- परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group: NSG) में भारत-विशिष्ट छूट प्राप्त होने के बाद फ्रांस, वर्ष 2008 में, भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया।
- समझौते के अनुसार, फ्रांस 9,900 मेगावाट की जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिए 1,650 मेगावाट के छह यूरोपीय प्रेशराइज्ड रिएक्टरों का निर्माण करेगा।
- हाल ही में, फ्रांस की ऊर्जा कंपनी ई.डी.एफ. ने इन छह रिएक्टरों के निर्माण के लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) को एक बाध्यकारी तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

भारत-रूस



- दोनों देशों के मध्य परमाणु सहयोग 1960 के दशक से जारी है। उस समय भारत और तत्कालीन सोवियत संघ ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे।
- प्रारंभ में, वैश्विक परमाणु व्यवस्था के साथ भारत का जुड़ाव सीमित था, जिसे देखते हुए भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के साथ-साथ प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों से परमाणु ईंधन की आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- वर्ष 2008 में दोनों देशों ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- दोनों देश तीसरे (अन्य) देशों के साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए आपसी सहयोग पर विचार करने पर सहमत हुए हैं। जैसे- भारत ने बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर एक साथ काम करने के लिए रूस और बांग्लादेश के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौता (या 123 समझौता)



- इस समझौते के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वैश्विक असैन्य परमाणु व्यापार शुरू करने के लिए नई दिल्ली को छूट प्रदान करने हेतु भारत के मुद्दे को NSG में प्रस्तुत किया गया।
- NSG ने वर्ष 2008 में भारत को एक स्पष्ट छूट प्रदान की।
- ऐसे में परमाणु अप्रसार संधि का एक पक्षकार देश नहीं होने के बावजूद भारत परमाणु हथियार संपन्न एकमात्र देश बन गया, जिसे शेष विश्व के साथ परमाणु व्यापार में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।
- हालांकि, भारत को वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ एक समझौते (जिसे इंडिया सेफगाइडर्स एग्रीमेंट कहा जाता है) पर हस्ताक्षर करना पड़ा, जिसके कारण भारत के कुछ असैन्य परमाणु प्रतिष्ठानों को IAEA के सुरक्षोपायों के अधीन लाया गया।

भारत-जापान

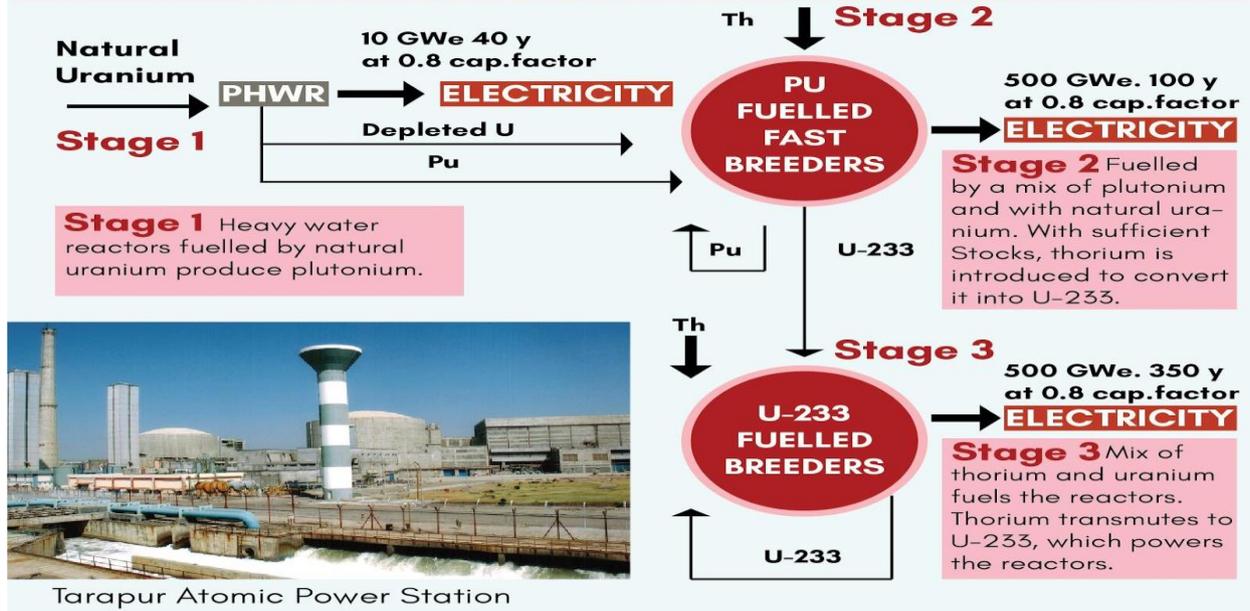


- परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए भारत-जापान समझौते पर वर्ष 2016 में हस्ताक्षर किए गए और वर्ष 2017 में इसे लागू किया गया।
- इस समझौते का एक विवादित पहलू 'नलीफिकेशन व्लॉज' है, जिसमें यह उल्लेख है कि यदि भारत परमाणु परीक्षण करता है तो पक्षकारों के बीच सहयोग स्वचालित रूप से निलंबित हो जाएगा।
- इस समझौते का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट है कि जापान का रिएक्टर के मुख्य घटकों और आधुनिक तकनीक पर एकाधिकार है।

⁵³ Department of Atomic Energy

INDIA'S THREE-STAGE NUCLEAR PROGRAMME

Homi Bhabha envisioned India's nuclear power programme in three stages to suit the country's low uranium resources profile



- भारत ने वर्ष 1998 में पोखरण के दूसरे दौर के उपरांत परमाणु परीक्षण करने पर स्व-स्थगन (दूसरे शब्दों में, भारत का कहना है कि वह अब परमाणु परीक्षण नहीं करेगा) का पालन किया है। साथ ही, भारत ने NPT के सिद्धांतों का पालन इसके कुछ हस्ताक्षरकर्ताओं की तुलना में कहीं बेहतर रीति से किया है।

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group: NSG)

- इसकी स्थापना वर्ष 1974 में भारत द्वारा किए गए सफल परमाणु परीक्षण (ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा या पोखरण- I) के परिणामस्वरूप की गई थी।
- यह परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है। यह परमाणु निर्यात और परमाणु सामग्री या तकनीक निर्यात के लिए दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के माध्यम से परमाणु हथियारों के अप्रसार में योगदान करने हेतु प्रयासरत है।
- भारत इस समूह का सदस्य नहीं है।

9.5. वैश्विक शासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत (Democratic Principles In Global Governance)

सुखियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने लोकतंत्र के विषय पर आयोजित पहले शिखर सम्मेलन⁵⁴ को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वैश्विक शासन (ग्लोबल गवर्नेंस) का मार्गदर्शन करने के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों की वकालत की।

समिट फॉर डेमोक्रेसी या लोकतंत्र शिखर सम्मेलन से संबंधित अन्य तथ्य

- यह लोकतंत्र और मानवाधिकारों को अमेरिकी विदेश नीति के केंद्र में रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की एक पहल है। यह दो चरणों वाली एक पहल है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति की मेजबानी में आयोजित होने वाले इस प्रकार के दो सम्मेलनों में से यह पहला सम्मेलन है।
- इसने लोकतांत्रिक सरकारों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों को एक मंच प्रदान किया है।

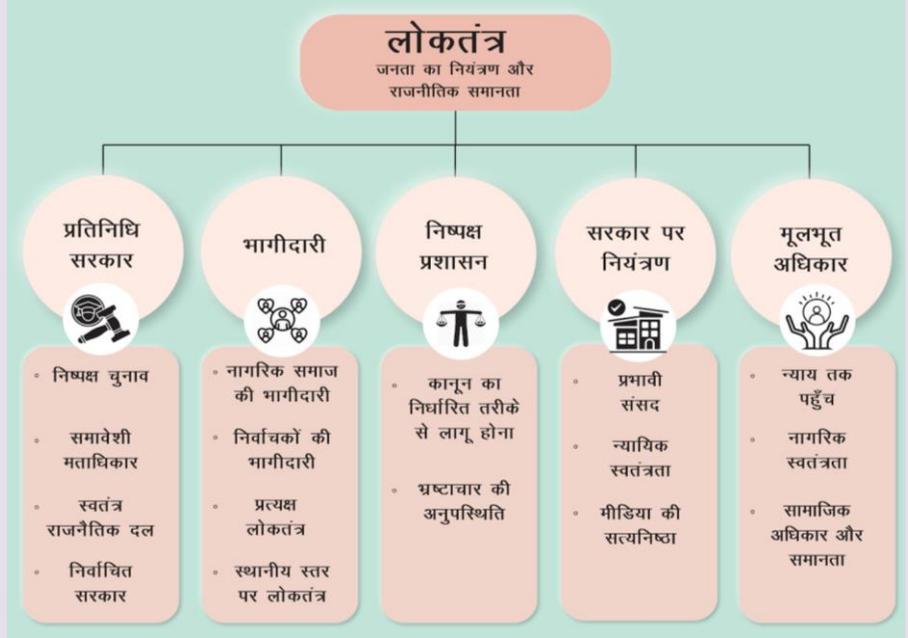


⁵⁴ Summit for Democracy

- इसका उद्देश्य तीन स्तंभों (जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है) पर ध्यान केंद्रित कर लोकतंत्र को स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक मजबूत बनाना है।
- इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतंत्र को स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक बढ़ावा देने के लिए प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेसी रीन्यूवल⁵⁵ की शुरुआत की है। इसके लिए अमेरिका ने 424.4 मिलियन डॉलर खर्च करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट, 2021 से संबंधित अन्य तथ्य

- इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (इंटरनेशनल-आईडिया /International-IDEA) द्वारा जारी किया गया है।
- इस रिपोर्ट के अंतर्गत शासन के तीन प्रमुख प्रकारों यथा- लोकतंत्र, मिश्रित (हाइब्रिड) और सत्तावादी शासन का उल्लेख किया गया है।
 - लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धी चुनाव होते हैं, जिसमें विपक्ष के पास सत्ता प्राप्त करने का एक वास्तविक अवसर होता है। मिश्रित और सत्तावादी शासनों में ऐसा नहीं होता है, इन दोनों को गैर-लोकतांत्रिक शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - यह रिपोर्ट पांच मुख्य विशेषताओं (इन्फोग्राफिक देखें) के आधार पर लोकतंत्र को परिभाषित करती है।
 - रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है, कि वर्ष 2020 में सत्तावादी दिशा में आगे बढ़ने वाले देशों की संख्या लोकतांत्रिक दिशा में जाने वाले देशों से अधिक थी। इसके अलावा, महामारी ने इस प्रवृत्ति को और दीर्घकालिक बना दिया है।
- इंटरनेशनल-आईडिया एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसे विश्व भर में लोकतंत्र को बढ़ावा देने और उसे बेहतर करने का अधिदेश प्राप्त है। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है।



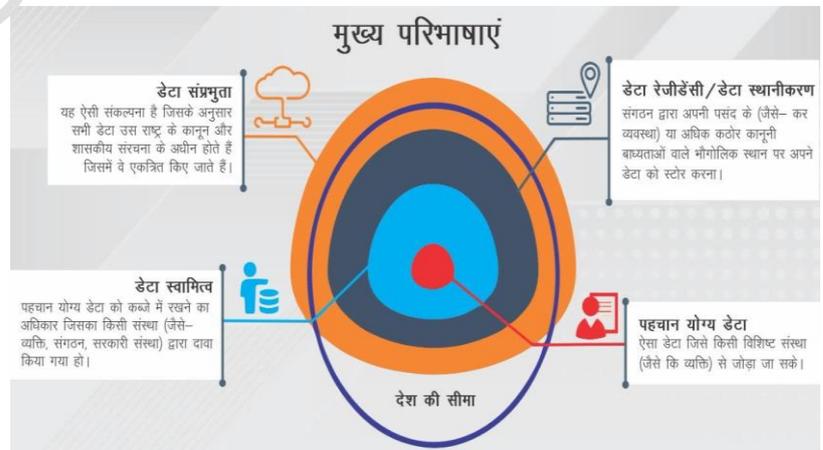
9.6. डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty)

सुखियों में क्यों?

सिडनी-डायलॉग में, प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल युग संप्रभुता, शासन, नैतिकता, कानून, अधिकार और सुरक्षा पर नए प्रश्न उठा रहा है।

डिजिटल संप्रभुता के बारे में

- डिजिटल संप्रभुता किसी राज्य का वह अधिकार है जिसके माध्यम से वह राष्ट्रीय हितों को पूरा करने हेतु अपने नेटवर्क को संचालित करता है। इन राष्ट्रीय हितों में सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा, गोपनीयता और वाणिज्य होते हैं।
 - यह किसी राज्य के स्वयं के डिजिटल भाग्य- डेटा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिस पर कोई राज्य निर्भर रहता है और उसका निर्माण करता है, पर नियंत्रण रखने की क्षमता है।



⁵⁵ Presidential Initiative for Democracy Renewal

सिडनी डायलॉग

- **सिडनी डायलॉग** ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट (एक थिंक-टैंक) की एक पहल है। यह उभरती एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न अवसरों एवं चुनौतियों की सामान्य समझ विकसित करने में राजनेताओं, उद्योग हस्तियों और सरकार को एक साथ लाता है।
- **बैठक में प्रधानमंत्री ने भारत में हो रहे 5 महत्वपूर्ण बदलावों पर प्रकाश डाला।**
 - विश्व की सबसे विस्तृत जन सूचना अवसंरचना का निर्माण भारत में किया जा रहा है जिसमें विशिष्ट डिजिटल पहचान और कुशल भुगतान संरचना शामिल है।
 - भारत में शासन, समावेश, सशक्तीकरण, संपर्कता, लाभ वितरण और जनकल्याण के लिए **डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग।**
 - भारत के पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से विकसित होने वाला स्टार्ट-अप इको-सिस्टम है।
 - भारत के उद्योग और सेवा क्षेत्रक, यहां तक कि कृषि क्षेत्रक में भी व्यापक डिजिटल रूपांतरण।
 - 5जी और 6जी जैसी **दूरसंचार प्रौद्योगिकी में स्वदेशी क्षमताओं** को विकसित करने के प्रयास।
- इसके तहत लोकतांत्रिक देशों को एक साथ काम करने के लिए एक रोडमैप प्रदान किया गया है। इस रोडमैप में डेटा गवर्नेंस तथा डेटा का संरक्षण एवं डेटा के सुरक्षित सीमा पार प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए मानक और मानदंड का निर्माण करने पर विशेष बल दिया गया है।
 - लोकतंत्र में, **डेटा को एक राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है** और यह पारदर्शी नीति निर्माण एवं समस्या समाधान के लिए महत्वपूर्ण है।
 - इसके अतिरिक्त, डेटा एकाधिकार को रोकने और अनुचित प्रथाओं की जांच करने के लिए **डेटा तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण किया जाना चाहिए।**

भारत और डिजिटल संप्रभुता

- **भारत की डिजिटल संप्रभुता की दृष्टि से तीन स्तंभ हैं:**
 - बहुराष्ट्रीय निजी अभिकर्ताओं की कार्यप्रणाली पर नियामक निरीक्षण से **आर्थिक संवृद्धि और विकास के प्रमुख उपकरण के रूप में डेटा का लाभ उठाना;**
 - डिजिटल व्यापार नियमों के असमान निर्माण को रोकने के लिए एक वैश्विक राजनयिक पहल द्वारा समर्थित एक राष्ट्रीय समर्थन;
 - द्विपक्षीय सुरक्षा विवादों में डेटा सुरक्षा का लाभ उठाना।

भारत में उठाए गए कदम

- **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019** जो व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है और उसके लिए एक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करता है।
- **RBI ने सभी सिस्टम प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित संपूर्ण डेटा केवल भारत में स्थित सिस्टम में संगृहीत किया जाए।**

9.7. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ (Other Important News)

<p>पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit: EAS)</p>	<p>प्रधान मंत्री ने 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) में हिस्सा लिया</p> <ul style="list-style-type: none"> • EAS के बारे में: <ul style="list-style-type: none"> ○ EAS एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 18 देशों के नेतृत्व वाला एक विशिष्ट मंच है। यह क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए निर्मित किया गया है। ○ सदस्य: दस आसियान सदस्य देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस और वियतनाम), ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। • भारत वर्ष 2005 में कुआलालंपुर (मलेशिया) में EAS की स्थापना से ही इसका सदस्य है।
<p>विकासशील देश का दर्जा (Developing Country Status)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तीन देशों (बांग्लादेश, नेपाल और लाओस) को अल्प विकसित देशों (LDCs) की श्रेणी से विकासशील देशों के वर्ग में शामिल किया है। <ul style="list-style-type: none"> ○ LDCs वे देश हैं, जो सतत विकास प्राप्त करने के लिए गंभीर संरचनात्मक बाधाओं से ग्रस्त हैं। • यह दर्जा प्रत्येक तीन वर्षों में निम्नलिखित के आधार पर संशोधित किया जाता है: <ul style="list-style-type: none"> ○ प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) (\$1222 या अधिक), ○ ह्यूमन असेट्स इंडेक्स (66 या अधिक) तथा ○ आर्थिक सुभेद्यता सूचकांक (Economic vulnerability Index) (32 या उससे कम)।



	<ul style="list-style-type: none">• लगातार दो त्रैवार्षिक समीक्षाओं में तीन में से किन्हीं दो मानदंडों के लिए क्रमिक वृद्धि सीमा को अवश्य पूरा कर लिया जाना चाहिए। <p>संबंधित सुर्खियाँ</p> <p>हाल ही में, चीन को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में 'विकासशील देश' का दर्जा प्राप्त हुआ।</p> <ul style="list-style-type: none">• विश्व व्यापार संगठन में 'विकासशील देश' के रूप में चीन का दर्जा एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। इसका कारण यह है कि चीन WTO के मानदंडों के अनुरूप विकासशील देशों के लिए आरक्षित लाभ प्राप्त कर रहा है।<ul style="list-style-type: none">○ चीन एक उच्च मध्यम आय वाला देश है।○ इसके अतिरिक्त, चीन पर यह आरोप है कि वह अनुचित व्यापार प्रथाओं का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए अपने देश के उद्यमों के साथ अधिमानी व्यवहार और डेटा प्रतिबंध आदि।• इसलिए, कई देशों ने चीन से आग्रह किया है कि वह या तो विकासशील देशों के लिए उपलब्ध लाभों की मांग न करे या स्वयं को विकासशील देश की श्रेणी में न रखे।• विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश:<ul style="list-style-type: none">○ WTO ने "विकसित" और "विकासशील" देशों को परिभाषित नहीं किया है।○ सदस्य देश स्वयं घोषणा करते हैं कि वे "विकसित" देश हैं या "विकासशील" देश हैं।○ हालांकि, यदि कोई सदस्य विकासशील देशों के लिए उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग करने का निर्णय करता है, तो अन्य सदस्य देश इस पर आपत्ति कर सकते हैं।• विकासशील देश के रूप में दावा करने के लाभ:<ul style="list-style-type: none">○ विकासशील देशों को 'विशेष और विभेदक व्यवहार' (S&DT)⁵⁶ प्रावधानों के माध्यम से विशेष अधिकार प्राप्त हैं।○ WTO के समझौते विकासशील देशों के लिए अधिक उदार लक्ष्य निर्धारित करते हैं। साथ ही, कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिक समय दिया जाता है।○ यह अन्य देशों को अधिमानी व्यवहार करने की अनुमति देता है, जैसे कि बरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली(GSP)⁵⁷।• GSP एक गैर-पारस्परिक अधिमानी प्रशुल्क प्रणाली है। यह WTO के सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र सिद्धांत⁵⁸ से छूट प्रदान करती है।
<p>तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय बैठक {Arctic Science Ministerial (ASM3)}</p>	<ul style="list-style-type: none">• भारत ने तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।<ul style="list-style-type: none">○ ASM3 संयुक्त रूप से आइसलैंड और जापान द्वारा आयोजित किया गया है। यह एशिया में आयोजित प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक है। यह गैर-आर्कटिक राष्ट्रों द्वारा संचालित आर्कटिक विज्ञान अनुसंधान के मूल्य को रेखांकित करती है।○ ASM1 और ASM2 को क्रमशः वर्ष 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका और वर्ष 2018 में जर्मनी द्वारा आयोजित किया गया था।• उद्देश्य: बैठक का आयोजन आर्कटिक क्षेत्र के बारे में सामूहिक समझ को बढ़ाने और पर्यवेक्षणों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ इसकी निरंतर निगरानी पर बल देते हुए शिक्षाविदों, स्वदेशी समुदायों, सरकारों और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारकों को इस दिशा में अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है।• भारत ऊपरी महासागरीय परिवर्तनशीलता और समुद्री मौसम संबंधी मापदंडों की दीर्घकालिक निगरानी के लिए आर्कटिक में ओपन ओशन मूरिंग तैनात करेगा।• भारत वर्ष 2023 तक निसार/ NISAR (नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार) उपग्रह प्रक्षेपित करने की भी योजना बना रहा है। यह इसरो-नासा का एक संयुक्त मिशन है। यह उपग्रह ध्रुवीय क्रायो-स्फीयर और हिंद महासागर क्षेत्र सहित सभी भूमि पर वैश्विक अवलोकन के लिए है।

⁵⁶ special and differential treatment

⁵⁷ Generalized System of Preferences

⁵⁸ Most Favoured Nation principle



<p>पुर्तगाली भाषा के देशों का समुदाय (Community of Portuguese Language Countries: CPLP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> हाल ही में, भारत CPLP में सहयोगी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। CPLP को लूसोफोन कॉमनवेल्थ के रूप में भी जाना जाता है। यह चार महाद्वीपों में अवस्थित लूसोफोन राष्ट्रों का एक संघ है, जहां पुर्तगाली का एक आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस समुदाय के सदस्य देशों में शामिल हैं: ब्राजील, अंगोला, काबो वर्डे, गिनी-बिसाऊ, इक्वेटोरियल गिनी, मोजाम्बिक, पुर्तगाल, साओ टोम और प्रिंसिपे तथा तिमोर-लेस्ते। CPLP के प्रमुख उद्देश्यों में इसके सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और राजनयिक सहयोग को बढ़ावा देना; सभी क्षेत्रों में सहयोग को सुनिश्चित करना तथा पुर्तगाली भाषा का प्रचार एवं प्रसार करना शामिल हैं।
<p>ट्रोइका प्लस</p>	<ul style="list-style-type: none"> यह पाकिस्तान, चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक समूह है। इस समूह ने हाल ही में इस्लामाबाद में अपनी बैठक सम्पन्न की है। इस बैठक में अफगानिस्तान में बढ़ते वैकिंग संकट पर चर्चा की गयी थी। इसमें इस संकट द्वारा संभावित आर्थिक पतन और एक मानवीय आपदा उत्पन्न होने की चेतावनी दी गयी थी, जो एक नए शरणार्थी संकट को बढ़ावा दे सकती है। अफगानिस्तान पर इसी तरह की वार्ता- भारत, ईरान और पांच अन्य मध्य एशियाई देशों के साथ रूस द्वारा आयोजित की जा चुकी है।
<p>हेनले पासपोर्ट सूचकांक (Henley Passport Index)</p>	<ul style="list-style-type: none"> यह सूचकांक विभिन्न देशों के पासपोर्ट को उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है, जहां उनके धारक बिना पूर्व-वीजा के पहुंच सकते हैं। <ul style="list-style-type: none"> हेनले पासपोर्ट सूचकांक लंदन स्थित हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। यह नागरिकता और निवास संबंधी मामलों की विश्व स्तरीय सलाहकार फर्म है। भारत की पासपोर्ट शक्ति में वर्ष 2021 की तुलना (90वां स्थान) में इस तिमाही में सुधार हुआ है। अब यह 83वें स्थान पर है। <ul style="list-style-type: none"> जापान और सिंगापुर सूचकांक में शीर्ष पर हैं।
<p>भारत-डेनमार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ</p>	<ul style="list-style-type: none"> हाल ही में आयोजित इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों ने कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन एवं कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने में मदद करेंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों ने भारत-डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी (GSP)⁵⁹ के तहत हुई प्रगति की भी समीक्षा की। इस साझेदारी को भारत और डेनमार्क ने सितंबर 2020 में एक आभासी शिखर सम्मेलन के उपरांत आरंभ किया था। <ul style="list-style-type: none"> GSP को मुख्यतः राजनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ाने, आर्थिक संबंधों एवं हरित विकास का विस्तार करने तथा रोजगार सृजित करने और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रारंभ किया गया है। दोनों पक्षों ने GSP के लिए एक विस्तृत 5-वर्षीय कार्य योजना (2021-2026) की भी शुरुआत की।
<p>इंटरनेशनल को- ऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर- रुद्राक्ष</p>	<ul style="list-style-type: none"> हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने साझेदारी के 5 क्षेत्रों में से एक, वाराणसी में कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। यह केंद्र एक सांस्कृतिक केंद्र और विभिन्न लोगों को एकजुट करने का माध्यम होगा। वर्ष 2015 में, भारत और जापान ने सिस्टर सिटी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका एक भाग क्योटो-वाराणसी साझेदारी थी। इसके तहत, 5 क्षेत्रों की पहचान की गई थी, जिन पर जापानी अपनी विशेषज्ञता का विस्तार करके पवित्र शहर वाराणसी का पुनरुद्धार करने में सहायता करेंगे। कोबे-अहमदाबाद भी सिस्टर सिटीज हैं।

⁵⁹ Green Strategic Partnership

9.8. सुर्खियों में रहे स्थल (Places in News)



क्रम संख्या	स्थल	मानचित्र
1.	<p>टिग्रे, अफ्रीका</p> <p>टिग्रे क्षेत्र में इथियोपिया के बढ़ते अत्याचारों के कारण, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इथियोपिया की आर्थिक और सुरक्षा सहायता पर प्रतिबंध लगा दिया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> यह इथियोपिया का एक शहर है। <ul style="list-style-type: none"> इस क्षेत्र से टेकेज़ और गश (मारेब) नदियां प्रवाहित होती हैं। इसके पूर्व में कोबार सिंक सहित डेनाकिल मैदान स्थित है। 	

<p>2.</p>	<p>माली, पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र (राजधानी: बमाको)</p> <p>हाल ही में, माली को सैन्य सत्ता परिवर्तन का सामना करना पड़ा, जब उसके संक्रमणकालीन (transitional) राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> नाइजर नदी इसके आंतरिक भाग से होकर बहती है, जो यहाँ के व्यापार और परिवहन के मुख्य मार्ग के रूप में कार्य करती है। 	
<p>3.</p>	<p>इस्वातिनी साम्राज्य (Kingdom of Eswatini) अफ्रीका</p> <ul style="list-style-type: none"> हाल ही में, राजा मस्वाती तृतीय के विरुद्ध विरोध हिंसक हो गया। पूर्ववर्ती स्वाज़ीलैंड साम्राज्य के रूप में विख्यात, इस्वातिनी दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में एक भू-आबद्ध देश है, जहाँ यह मोजाम्बिक से जुड़ा हुआ है। 	
<p>4.</p>	<p>गाम्बिया (राजधानी: बंजुल), अफ्रीका</p> <ul style="list-style-type: none"> भारत व गाम्बिया ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों में सहयोग को सुदृढ़ करने एवं बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गाम्बिया पश्चिमी अफ्रीका में अटलांटिक तट पर स्थित है और पड़ोसी देश सेनेगल से घिरा हुआ है। यह गाम्बिया नदी के चारों ओर भूमि की एक लंबी संकरी पट्टी को धारित करता है। गाम्बिया अफ्रीका का सबसे छोटा गैर-द्विपीय देश है। 	

<p>5.</p>	<p>त्रिपोली, अफ्रीका लीबिया में हुए दंगों में उत्तरी शहर त्रिपोली में दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए।</p> <ul style="list-style-type: none"> त्रिपोली लीबिया की राजधानी है। भूमध्यसागरीय तट के साथ उत्तर-पश्चिमी लीबिया में स्थित, यह देश का सबसे बड़ा शहर और मुख्य बंदरगाह है। 	
<p>6.</p>	<p>ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम (GERD)</p> <ul style="list-style-type: none"> इथियोपिया द्वारा ब्लू नील नदी पर विद्युत उत्पन्न करने के लिए नियोजित 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विशाल जलविद्युत परियोजना, सूडान और मिस्र द्वारा विवादित है। इस विवाद का कारण नील नदी के जल पर इन देशों की अत्यधिक निर्भरता है। एक बार पूर्णतः परिचालन में आ जाने पर, यह बांध आसवन बांध के उच्च जल स्तर को जोखिम में डाल सकता है, जिसे मिस्र की जीवन रेखा माना जाता है। 	
<p>7.</p>	<p>ट्यूनीशिया (राजधानी: ट्यूनिस), अफ्रीका</p> <p>हाल ही में, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने आर्थिक परेशानियों और कोविड-19 से निपटने पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर संसद को निलंबित कर दिया</p> <ul style="list-style-type: none"> यहाँ सबसे ऊँचा पर्वत माउंट चांबी (अल-शनावी) है। मेदजेरदा नदी इस देश से होकर बहने वाली प्रमुख नदी है। 	
<p>8.</p>	<p>दारफुर क्षेत्र (Darfur region)</p> <ul style="list-style-type: none"> सूडान, लंबे समय से निरंकुश शासक ओमर अल-बशीर के साथ-साथ दारफुर संघर्ष में बांछित अन्य अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को सौंपेगा। दारफुर क्षेत्र सूडान के पश्चिमी भाग में लीबिया, चाड और मध्य अफ्रीकी गणराज्य की सीमाओं के निकट स्थित है। सूडान की राजधानी खार्तूम, देश के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है। 	

<p>9.</p>	<p>मोरक्को (राजधानी: रबात), अफ्रीका</p> <ul style="list-style-type: none"> हाल ही में, इज़राइल ने "अब्राहम समझौते" के तहत संबंधों को सामान्य बनाने के लिए मोरक्को में अपने एक राजनयिक मिशन को प्रारंभ किया है। यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक प्रमुख आर्थिक संपन्न राष्ट्र है और यह माघरेब लीग का एक हिस्सा है। मोरक्को के विद्वान इब्रबतूता ने 14वीं शताब्दी में मोरक्को से भारत की यात्रा की थी। 	
<p>10.</p>	<p>जाम्बिया (राजधानी: लुसाका), अफ्रीका</p> <ul style="list-style-type: none"> हाल ही में, जाम्बिया के विपक्षी नेता हाकेंडे हिचिलेमा को नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित (वर्तमान राष्ट्रपति को पराजित कर) किया गया है। जाम्बिया, दक्षिण-मध्य पठार पर स्थित अफ्रीका का एक भू-आबद्ध और राजनीतिक रूप से स्थिर देश है। इसका नामकरण ज़ांबेज़ी नदी के नाम पर किया गया है। यह राष्ट्र समृद्ध जैव-विविधता के साथ-साथ विक्टोरिया फॉल्स, 20 राष्ट्रीय उद्यानों (जैसे काफू राष्ट्रीय उद्यान) आदि के लिए भी प्रसिद्ध है। यह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक (डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के उपरांत) देश है। 	
<p>11.</p>	<p>गिनी (राजधानी: कोनाक्री), अफ्रीका</p> <p>गिनी में एक सैन्य तख्तापलट ने तत्कालीन सरकार को भंग कर दिया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> यह देश पश्चिमी अफ्रीका का भाग है और अटलांटिक तट पर अवस्थित है। गाम्बिया और नाइजर नदी प्रमुख नदियाँ हैं। 	

<p>12.</p>	<p>सोमालिया (राजधानी: मोगादिशु), अफ्रीका</p> <ul style="list-style-type: none"> हाल ही में, सोमालिया के राष्ट्रपति ने अपने प्रधान मंत्री को निलंबित कर दिया है। इस कदम से देश में तनाव बढ़ने की संभावना है। सोमालिया, अफ्रीका का सबसे पूर्वी देश है। यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप पर, पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित है। भूमध्य रेखा दक्षिणी सोमालिया से होकर गुजरती है। 	
<p>13.</p>	<p>बुर्किना फासो (राजधानी औगाडौगु), अफ्रीका</p> <ul style="list-style-type: none"> हाल ही में बुर्किना फासो में सेना द्वारा सैन्य सत्ता परिवर्तन की घोषणा की गई। <p>राजनीतिक सीमाएं:</p> <ul style="list-style-type: none"> यह पश्चिमी अफ्रीका में एक स्थलरुद्ध (landlocked) देश है। यह एक पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश है। इसने वर्ष 1960 में अपर वोल्टा गणराज्य के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 	

Emphasis on conceptual clarity to train the aspirants for developing an understanding to solve ethics case study from basic to advance level

Case studies covers all the exclusive topics from contemporary and current issues as well as previous Year UPSC Paper Case studies

To discuss on Various techniques on writing strong answers.

One to one mentoring session

ETHICS

Case Studies Classes

ADMISSION OPEN

Focus on contemporary issues and interlinking case studies with topics of current interest.

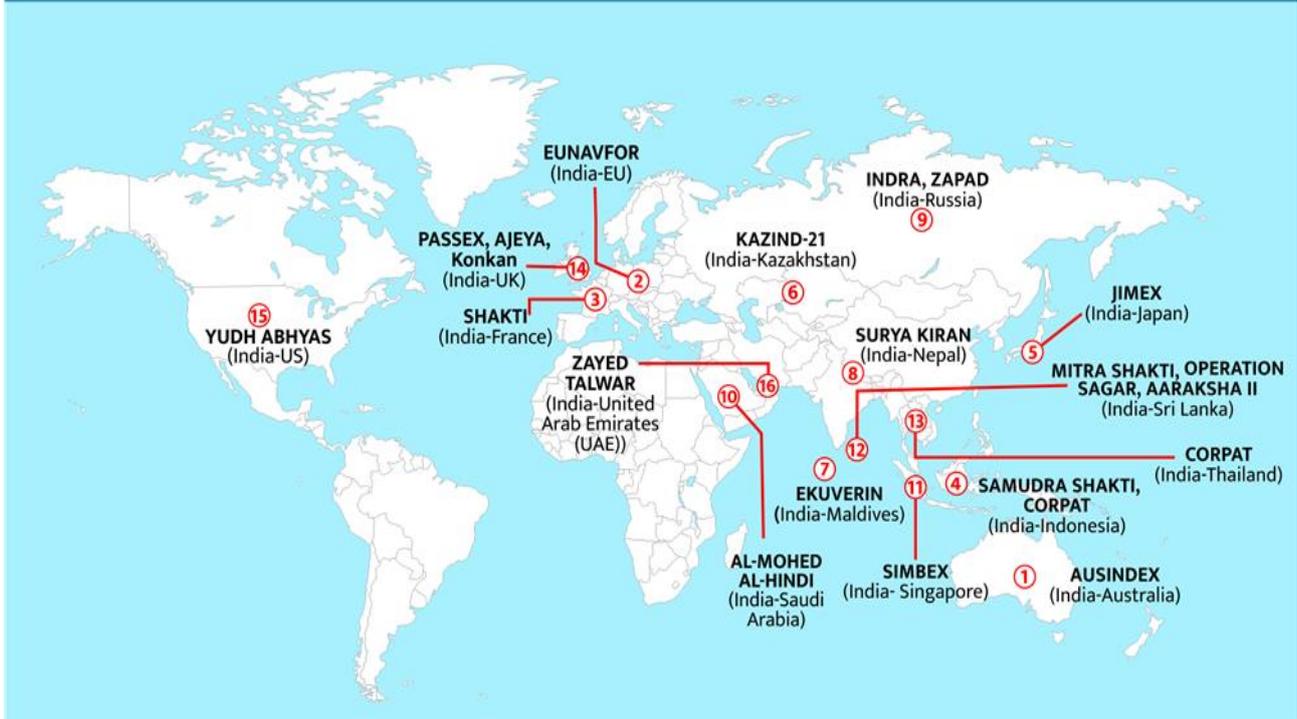
Regular Doubts clearing session and personal guidance for the ethics paper throughout your preparation

Daily Class assignment and discussion

Comprehensive & updated ethics material

10. सुर्खियों में रहे भारत के सैन्य/नौसेना अभ्यास (Military/Naval Exercises of India in News)

BILATERAL DEFENCE EXERCISES IN NEWS



PT 365 - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

महत्वपूर्ण बहुपक्षीय अभ्यास		
क्रम संख्या	शामिल देश	अभ्यास का नाम
1.	हिंद महासागर के सभी तटवर्ती देश और दक्षिण पूर्व एशिया के देश।	अभ्यास मिलन
2.	इस युद्धाभ्यास में पूर्वी अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों सहित 12 पूर्वी अफ्रीकी देश, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, इंटरपोल आदि ने भाग लिया।	कटलास एक्सप्रेस अभ्यास 2021
3.	अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण (SEACAT) ⁶⁰ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक सैन्य अभ्यास है।	दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण (SEACAT)
4.	अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत	मालाबार अभ्यास
5.	मालदीव, भारत और श्रीलंका	दोस्ती
6.	भारत, सिंगापुर और थाईलैंड	सिटमेक्स (STIMEX)
7.	ईरान, रूस और चीन	CHIRU-2Q22

⁶⁰ Southeast Asia Cooperation and Training

अन्य महत्वपूर्ण अभ्यास और ऑपरेशन	
पैनेक्स-21 (PANEX-21)	<ul style="list-style-type: none"> PANEX-21 मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। यह बिम्स्टेक (BIMSTEC) देशों की भागीदारी के साथ पुणे में आयोजित किया गया। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और भारत।
अभ्यास 'सागर शक्ति'	<ul style="list-style-type: none"> यह भारत की युद्धक तत्परता का परीक्षण करने के लिए कच्छ में आयोजित एक व्यापक 'सैन्य अभ्यास' है। इसमें कई एजेंसियां भाग ले रही हैं। इसका आयोजन भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा किया गया था। इसमें भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल, गुजरात पुलिस और समुद्री पुलिस आदि भागीदार के रूप में शामिल हुए हैं।
ऑपरेशन सर्प विनाश (Operation SarpVinash)	<ul style="list-style-type: none"> जम्मू में पुंछ की पहाड़ियों में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन सर्प विनाश इस क्षेत्र में सबसे लंबा अभियान है। <ul style="list-style-type: none"> यह एक आतंकवाद रोधी अभियान है, जिसे वर्ष 2003 में शुरू किया गया था। यह ऑपरेशन कश्मीर घाटी को जम्मू से अलग करने वाली पीर पंजाल रेंज के सुरनकोट इलाके में शुरू हुआ था। <ul style="list-style-type: none"> इस ऑपरेशन का लक्ष्य हिल्काका नामक स्थान था।
अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन (Exercise Peaceful Mission)	<ul style="list-style-type: none"> यह SCO सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने और बहुराष्ट्रीय सैन्य टुकड़ियों की कमान संभालने के लिए सैन्य नेताओं की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए SCO का एक अभ्यास है।

CSAT

कलासेस

2022

ENGLISH MEDIUM
11 January

हिन्दी माध्यम
22 December

लाइव/ऑनलाइन

कक्षाएं भी उपलब्ध

A central brain diagram with various educational icons (math, science, history, etc.) connected to it by arrows, symbolizing comprehensive learning.

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

Heartiest Congratulations to all successful candidates

10 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2020

FROM VARIOUS PROGRAMS OF VISION IAS



1
AIR

SHUBHAM
KUMAR



2
AIR

JAGRATI
AWASTHI



3
AIR

ANKITA
JAIN



4
AIR

YASH
JALUKA



5
AIR

MAMTA
YADAV



6
AIR

MEERA
K



7
AIR

PRAVEEN
KUMAR



8
AIR

JIVANI KARTIK
NAGJIBHAI



9
AIR

APALA
MISHRA



10
AIR

SATYAM
GANDHI

ABHYAAS 2022

ALL INDIA PRELIMS

(GS + CSAT)

MOCK TEST SERIES

3 TEST

TEST-1
17 APRIL

TEST-2
1 MAY

TEST-3
15 MAY

- 🎯 All India Ranking
- 🎯 Comprehensive Evaluation, Feedback & Corrective Measures
- 🎯 Available In ENGLISH / हिन्दी

Register @ www.visionias.in/abhyaas

OFFLINE IN
100+ CITIES

AGARTALA | AGRA | AHMEDABAD | AIZAWL | AJMER | ALIGARH | ALMORA | ALWAR | AMRAVATI | AMRITSAR | ANANTHAPURU | AURANGABAD | BAREILLY
BENGALURU | BHAGALPUR | BHOPAL | BHUBANESWAR | BIKANER | BILASPUR | CHANDIGARH | CHENNAI | CHHATARPUR | COIMBATORE | CUTTACK | DEHRADUN
DELHI MUKHERJEE NAGAR | DELHI RAJENDRA NAGAR | DHANBAD | DHARWAR | DIBRUGARH | FARIDABAD | GANGTOK | GAYA | GHAZIABAD | GORAKHPUR
GREATER NOIDA | GUNTUR | GURGAON | GUWAHATI | GWALIOR | HALDWANI | HARIDWAR | HAZARIBAGH | HISAR | HYDERABAD | IMPHAL | INDORE | ITANAGAR
JABALPUR | JAIPUR | JAMMU | JAMSHEDPUR | JHANSI | JODHPUR | JORHAT | KANPUR | KOCHI | KOHIMA | KOLKATA | KOTA | KOZHIKODE (CALICUT) | KURNOOL
KURUKSHETRA | LUCKNOW | LUDHIANA | MADURAI | MANGALURU | MATHURA | MEERUT | MORADABAD | MUMBAI | MUZAFFARPUR | MYSURU | NAGPUR | NASIK
NAVI MUMBAI | NOIDA | ORAI | PANAJI (GOA) | PANIPAT | PATIALA | PATNA | PRAYAGRAJ (ALLAHABAD) | PUNE | RAIPUR | RAJKOT | RANCHI | ROHTAK | ROORKEE
SAMBALPUR | SHILLONG | SHIMLA | SILIGURI | SONIPAT | SRINAGAR | SURAT | THANE | THIRUVANANTHAPURAM | TIRUCHIRAPALLI | UDAIPUR | VADODARA
VARANASI | VIJAYAWADA | VISHAKHAPATNAM | WARANGAL

8468022022



WWW.VISIONIAS.IN



DELHI | JAIPUR | PUNE | AHMEDABAD | HYDERABAD | CHANDIGARH | LUCKNOW | GUWAHATI